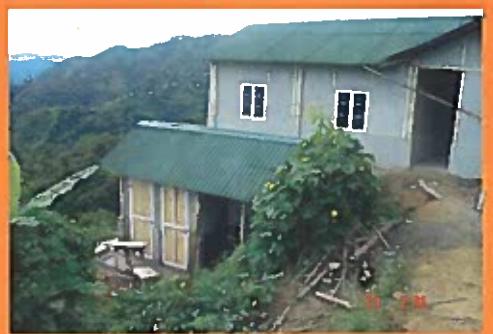


वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2006-2007



bmtpc

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संबद्धन परिषद्
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार

Building Materials and Technology Promotion Council
Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation, Govt. of India



वार्षिक रिपोर्ट

2006–2007

bmapc

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संबद्धन परिषद्

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार
कोर-5ए, प्रथम तल, इंडिया हेबिटेट सेंटर, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

吉門大成

7125-5625

吉門大成

7125-5625

भूमिका

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संबद्धन परिषद् की वर्ष 2006-07 की 17वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यधिक संतोष एवं हर्ष हो रहा है।

नवीन एवं आपदा प्रतिरोधी भवन प्रौद्योगिकियों के संबद्धन विकास एवं अनुप्रयोग के लिए परिषद् को प्राप्त मुख्य जनादेश के माध्यम से परिषद् ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपना कर एक नयी सफलता को छुआ है। यह एक अग्रणी आंकलन एजेन्सी के रूप में उभरी है तथा जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत जो परियोजनाएं चल रही है उनके लिए परिषद् को निगरानी एजेन्सी के रूप में चुना गया हैं समग्र समाज के लिए गौण लाभों वाली परियोजनाओं के लिए इसके प्रोत्साहन कार्यकलापों को सुदृढ़ करने के लिए एक सुविचारित नीति को लागू किया गया है। भवन निर्माण के जटिल क्षेत्रों में क्षमता निर्माण की दिशा में व्यवसायियों, वास्तुकारों, राज मिस्ट्रियों एवं निर्माण मजदूरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं दक्षता विकास कार्यक्रमों को निरन्तर प्रोत्साहित तथा आयोजित किया है। बी.एम.टी.पी.सी. ने मंत्रालय की जे.एन.एन.यू.आर.एम. सैल की सहायता से जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत बी.एस.यू.पी. एवं आई.एच.एस.डी.पी. की परियोजना विकास हेतु नगर निगम के यू.एल.बी. कार्यकारियों के क्षमता निर्माण करने के नये युग में प्रवेश किया है।

बी.एम.टी.पी.सी ने नवीन एवं आपदा प्रतिरोधी निर्माण प्रौद्योगिकियों के वास्तविक अनुप्रयोग को महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में चलायी जा रही तत्कालीन वैम्बे योजना जो अब जे.एन.एन.यू.आर.एम. की आई.एच.एस.डी.पी. योजना में विलीन हो गयी है, के तहत प्रदर्शन आवास परियोजनाओं में प्रदर्शित की गयी है। उत्तराखण्ड में 100 ईकाइयों एवं महाराष्ट्र में 70 आवास इकाईयों पर कार्य पूर्ण हो गया है तथा राज्य सरकारों को इन्हें सौंपा जाने वाला है। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एवं कर्नाटक परियोजनाओं का निर्माण विभिन्न चरणों में है, और अगले वित्तिय वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा।

बांस आधारित भवन प्रौद्योगिकियों जो कि परिषद् का एक मुख्य क्षेत्र है मिजोरम एवं त्रिपुरा राज्यों में समुदायिक भवन का निर्माण करके प्रदर्शित किया गया है। मिजोरम राज्य में इन भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है तथा इनको राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। त्रिपुरा में छः भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और शेष चार भवनों पर कार्य अगले वर्ष पूर्ण होने की आशा है। बी.एम.टी.पी.सी. ने बैंगलोर में प्रथम वृहत आवास प्रदर्शन परियोजना को पूरा कर लिया था जिसमें 252 आवास ईकाइयां थीं। बी.एम.टी.पी.सी. ने, बवाना में औद्योगिक वर्करों के लिए 3164 घरों का निर्माण करने हेतु डी.एस.आई.आई.डी.सी. को तकनीकी सहायता भी प्रदान की है। डी.एस.आई.आई.डी.सी. ने अब इस प्रकार के 4300 और घरों का निर्माण करने के लिए एक अन्य पहल की है। ग्रेटर नोएडा में ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने और दादर एवं नगर हवेली में ओमनीबस औद्योगिक विकास निगम ने इस प्रकार के लागत प्रभावी आवास संबंधी पहल की हैं। विभिन्न एजेंसियों के यह उद्यम, लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों की बढ़ती स्वीकार्यता की ओर संकेत करते हैं, जिन्हें दोहराया जा रहा है और बड़े पैमाने पर इनका अनुप्रयोग किया जा रहा है।

परिषद् ने, आपदा अल्पीकरण और प्रबंधन के लिए अपने कार्यकलापों द्वारा स्टेकहोल्डरों की अपेक्षाओं को पूरा किया है। प्रमुख उपलब्धि वल्नरेविलिटी एटलस ऑफ इंडिया का संशोधित डिजिटाइजड संस्करण रही है जिसे सबसे पहले 1997 में प्रकाशित किया गया था। संशोधित संस्करण में, अद्यतन आंकड़ों के अनुसार खतरे संबंधी सारणियां और डिजिटाइजड राज्यों के आपदा संबंधी नकशे शामिल हैं। वल्नरेविलिटी एटलस ऑफ इंडिया को, वर्ष 2006 के लिए दुबई अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों के अंतर्गत यू.एन.-हैबीटेट द्वारा सर्वोत्तम पद्धतियों के लिए प्राप्त मामलों में से 'अच्छी प्रगति' के रूप में मान्यता दी गई है। परिषद्, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मॉडल निर्माण उप-नियमों के प्रसार के लिए और बाद में निर्माण उप-नियमों के संशोधन के लिए गृह मंत्रालय के एक महत्त्वपूर्ण स्रोत संस्थान के रूप में बनी हुई है। इस वर्ष के दौरान परिषद्, ने पूरे देश में 7 राज्यों में मॉडल निर्माण उप-नियमों पर तकनीकी कार्यशालाएं आयोजित की हैं। रेट्रोफिटिंग प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से बी.एम.टी.पी.सी. ने कुपवाड़ा, जम्मू एवं कश्मीर में प्रसिद्ध सब-डिवजिनल अस्पताल की रेट्रोफिटिंग का काम पूरा किया है।

परिषद्, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा गठित एक कार्य दल के अधीन, हरित पर्यावास के लिए दिशानिर्देश तैयार कर रही है, जिसमें अनन्य रूप से आवास क्षेत्र के लिए हरित पर्यावास के विभिन्न पहलू कवर किए जाएंगे। हरित पर्यावास

के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का समग्र उद्देश्य, उन बेहतर या नई पद्धतियों के माध्यम से प्रत्येक स्टेकहोल्डर के लिए एक साधन के रूप में काम करना होगा, जिन्हें अपेक्षित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनाया जाना चाहिए।

विश्व हैबीटेट दिवस के अवसर पर परिषद् ने "नेपाल और भूटान पर सूचना के साथ भारतीय निर्माण सामग्रियों और उत्पादों की डायरेक्टरी" का रवां संस्करण निकाला है। इस अवसर पर 'बिल्डिंग मैटीरियल न्यूज' का वार्षिक प्रकाशन भी निकाला गया। बी एम टी पी सी ने विकलांग बच्चों के लिए एक पेटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया और विजेताओं को विश्व हैबीटेट दिवस समारोह के दौरान पुरस्कार दिए गए। निरंतर निवेश के साथ परिषद् की वैबसाइट का बार-बार इस्तेमाल किया जाता है और इसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेकहोल्डरों का ध्यान आकर्षित किया है।

परिषद् ने, दक्षिण अफ्रीका, रूस, बेल्जियम, यू.एस.ए., मोजाम्बिक और आस्ट्रेलिया से आए विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के दौरे की मेजबानी करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में कार्यकलापों को पर्याप्त महत्व दिया। जिला मौंगर, भूटान में बी.एम.टी.पी.सी. द्वारा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन व उत्पादन केन्द्र स्थापित करने के लिए, सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार और सचिव, निर्माण एवं मानव अधिवास, भूटान सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

अभिनव निर्माण प्रौद्योगिकियों का विकास करने पर फोकस करते हुए विशिष्ट परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं, जैसे प्लांट फाइबर आधारित मिश्रणों से लकड़ी का विकल्प विकसित करना, चावल की भूसी से रिएक्टिव सीलिका का उत्पादन करने के लिए बड़े संयंत्र स्थापित करना, दो मंजिले बम्बू हाउस के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी का विकास, रूफिंग के लिए बम्बू मैट रिज कैप का विकास करना, मिश्रणों का इस्तेमाल करके और बांस पर आधारित प्रिफेक्ट्रीकेटड मोडुलर मकान बनाना।

परिषद् द्वारा कार्यान्वित अनेक कार्यक्रमों के लिए अध्यक्ष, प्रबंध मण्डल के सदस्यों और कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष व सदस्यों और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से प्राप्त बहुमूल्य मार्गदर्शन व सतत प्रोत्साहन का मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। विशेष रूप से योजना आयोग, शहरी विकास पर बनी स्थायी संसदीय समिति, जे.एन.एन.यू.आर.एम. मिशन निदेशालय, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, विभिन्न राज्य सरकारों, नगर निगमों, स्थानीय शहरी निकायों, गृह मंत्रालय, डोनर मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, एन.डी.एम.ए., एन.आई.डी.एम., एम.ओ.एस. एण्ड.पी.आई., डी एस टी, सी एस आई आर, आई आई टी, सी ई पी टी, आई पी आई आर टी आई, एस ई आर सी, हुड्को, बी आई एस, एन एच बी, सी पी डब्ल्यू डी, एन एस आई सी, सी आई डी सी, यूनिडो और यू एन-हैबीटेट द्वारा परिषद् के प्रयासों को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु लगातार दिए गए सहयोग और रुचि के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

बी एम टी पी सी में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा परिषद् के क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने में किए गए उनके प्रयासों के लिए मैं विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। परिषद् आवास एवं शहरी एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त सहायता व सहयोग के लिए बहुत आभारी है, जिससे परिषद् के लक्ष्यों को पूरा करने में व इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिली है।



(जे. के. प्रसाद)
कार्यकारी निदेशक

विषय-सूची

आदर्श कथन	1
प्रस्तावना	2
वर्ष 2006–2007 के दौरान प्रमुख पहलें एवं कार्यकलाप	4
I. लागत-प्रभावी प्रौद्योगिकियों के उपयोग से प्रदर्शन घरों का निर्माण	4
1. वैम्बे के अंतर्गत प्रदर्शन घरों का निर्माण	4
2. मिजोरम और त्रिपुरा में बास आधारित इमारतों का प्रदर्शन	5
3. बड़ी आवास परियोजनाओं में लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों का फैल त्तरीय अनुप्रयोग	5
II. आपदा अल्पीकरण – मरम्मत, पुनर्निर्माण और रेट्रोफिटिंग	6
1. बलरेविलिटी एटलस ऑफ इंडिया –पहला संशोधन (2006) का विमोचन	6
2. भॉडल मवन निर्माण उप-नियमों पर एक-दिवसीय तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन-गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित	7
3. जम्मू एवं कश्मीर में आये भूकम्प के बाद बी.एम.टी.पी.सी. की पहले	7
4. भूकम्प के प्रति सुरक्षा के लिए कुपवाड़ा, जम्मू एवं कश्मीर में उप-जिला अस्थाताल की रेट्रोफिटिंग	8
5. दिल्ली नगर निगम के भवनों में भूकम्पीय सुदृढ़ीकरण के लिए रेट्रोफिटिंग तकनीकों का प्रदर्शन	10
6. भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन और निर्माण पर अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरूआत	10
III. पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कार्यकलाप	11
1. स्थानीय संसाधनों और आपदा प्रतिरोधी निर्माण पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रों में किए गए महत्वपूर्ण कार्यकलाप	11
IV. निर्माण क्षेत्र में सूचना एवं आंकड़ा आधार को सुदृढ़ बनाना	13
1. विश्व पर्यावास, 2006 के अवसर पर “सिटीज – मेगनेट ऑफ होप” विषय पर न्यूज लैटर के विशेष अंक का प्रकाशन	13
2. भारतीय निर्माण सामग्रियों एवं उत्पादों की डायरेक्टरी-सातवां संस्करण: 2006 का विमोचन	13
3. परिषद की वैबसाइट के माध्यम से सूचना प्रसार	13
4. मानकीकरण और उत्पाद मूल्यांकन	14
V. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबद्धनात्मक और क्षमता निर्माण कार्यकलाप	15
1. क्षमता निर्माण कार्यक्रम	15
2. भारतीय निर्माण सामग्री विनिर्माताओं के तकनीकी प्रतिनिधिमंडल के इटली के दौरे का आयोजन	19
3. भूटान की शाही सरकार के साथ सहयोग कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना	20
4. भिलाई, छत्तीसगढ़ में अर्ध-कुशल कारीगरों के लिए कुशलता उन्नयन कार्यक्रम	20
5. विश्व पर्यावास दिवस 2006 के अवसर पर विक्रक्ता प्रतियोगिता	21
6. बी.एम.टी.पी.सी. में विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का दौरा	21
7. ग्रीन हैबीटेट के लिए व्यापक दिशानिर्देश	21
8. 14–27 नवम्बर 2006 के दौरान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2006, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भाग लेना	23
9. शहरी विकास पर बनी स्थायी संसदीय समिति का दौरा	24
10. संसदीय राजमाला समिति की उप-समिति का दौरा	24
VI. प्रौद्योगिकी विकास, प्रसार और हस्तांतरण	24
1. नीडल्ड फैल्ट प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके ल्याट फाइबर आधारित मिश्रणों से लकड़ी का विकल्प विकसित करना	24
2. चावल की भूसी से रिएक्टिव सिलिका का उत्पादन करने के लिए प्रदर्शन संयंत्र की स्थापना	25
3. दो-पंजिले भवनों के निर्माण के लिए बम्बू हाऊसिंग प्रणाली प्रौद्योगिकी का विकास	25
4. बांस चटाई की नालीदार चादरों से छत बनाने के लिए बम्बू मैट रिज कैप का विकास	26
5. बांस आधारित मिश्रणों का इस्तेमाल करके प्रिफ्रीकेटड मोडुलर घरों का विकास	26
6. एच.पी.एल. में स्थायी उड़न राख ईंट उत्पादन व प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केन्द्र की स्थापना	26
7. राजकोषीय प्रोत्साहन	27
VII. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)	28
1. जे.एन.एन.यू.आर.एम. के कार्यान्वयन में बी.एम.टी.पी.सी. की मूलिका	28

VIII	वर्ष के दौरान कुछ परियोजनाओं / अध्ययनों की प्रमुख विशेषताएं	29
1.	भूगर्भीय-जलवायु और भौगोलिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए निर्देश लोगों के लिए किफायती घर बनाने हेतु टैम्पलेट्स तैयार करना.....	29
2.	बांस की चटाई की नालीदार शीटों से रुफिंग के लिए बन्धू मैट रिज कैप के उत्पादन का औद्योगिक उन्नयन करने हेतु परियोजना का प्रस्ताव	30
3.	फ्लैटटंड बन्धू मिश्रणों और लेमीनेट्ड बन्धू लम्बर उत्पादों का विकास	31
4.	ग्रेनाइट उद्योग के अपशिष्ट से भवन अवयवों का विकास.....	32
5.	छत्तीसगढ़ और मेघालय में बांस प्रदर्शन इमारतों का निर्माण	32
6.	मार्बल के मलबे/ मार्बल के छूरे के निपटान के पर्यावरण संबंधी प्रभावों और कंकरीट में इसके इस्तेमाल पर जांचों का अध्ययन	33
7.	निर्माण केन्द्रों के प्रौद्योगिकीय आवार का सूदृढ़ीकरण	33
8.	लागत प्रभावी आवास प्रौद्योगिकियों का प्रचार करने और बड़े पैमाने पर जनता में रुचि उत्पन्न करने के लिए वीडियो फिल्म बनाना.....	34
9.	वेयान्टु, केरल में सामुदायिक बांस चटाई बुनाई सुविधा स्थापित करना.....	35
10.	उत्तराखण्ड में आपदा प्रतिरोधी निर्माण प्रौद्योगिकियों में मास्टर राजमिस्त्रियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना	35
11.	रायपुर, छत्तीसगढ़ के निकट के ग्रामीण क्षेत्रों के 30 राजमिस्त्रियों के क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	36
12.	पूर्वीनीर्मित निर्माण संघटकों के उत्पादन के लिए मशीनों का उन्नयन.....	36
	संगठन	38
	स्टाफ / कार्मिक संख्या (31.3.2007 की स्थिति के अनुसार)	40
	लेखा	41
अनुबन्ध - I	राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों में भागीदारी	55
	प्रदर्शनियां	
	संगोचियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम	
	भारतीय मानक व्यूरो की तकनीकी समितियां	
	अन्य तकनीकी समिति/कार्य समूह इत्यादि	
	अन्य क्रियाकलाप	
अनुबन्ध - II	वर्ष के दौरान पूरे किए गए प्रायोजित अध्ययन / परियोजनाएं	68
	प्रायोजित अध्ययन	
	प्रायोजित परियोजनाएं	
अनुबन्ध - III	आरम्भ की गई प्रायोजित परियोजनाएं, अध्ययन और वीडियो फिल्में	69
	प्रायोजित अध्ययन	
	प्रायोजित परियोजनाएं	
	वीडियो फिल्में	
अनुबन्ध - IV	प्रस्तुति/प्रकाशित लेख	71
अनुबन्ध - V	वर्ष के दौरान निकाले गए प्रकाशन.....	72
अनुबन्ध - VI	दूसरे देशों से आए प्रमुख आगन्तुक	73
अनुबन्ध - VII	वर्ष 2007-08 के लिए कार्य-योजना	74

बी.एम.टी.पी.सी. का आदर्श कथन

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों और भवनों के लिए पर्यावरण अनुकूल एवं ऊर्जा प्रभावी नव परिवर्तित सामग्री की उत्पादन तकनीकों और आपदा प्रतिरोधी निर्माण के तरीकों के प्रयोग के प्रोत्साहन के लिए तकनीकी विकास और उसके हस्तांतरण व पूँजी निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना और उसे कार्यरूप देना ।

प्रस्तावना

लागत प्रभावी, पर्यावरण-अनुकूल एवं उर्जा-दक्ष अभिनव निर्माण सामग्रियों और आपदा प्रतिरोधी निर्माण प्रौद्योगिकियों के प्रयोगशाला संबंधी विकास और विस्तृत स्तर पर फील्ड अनुप्रयोग के बीच के अन्तर को पाटने के मुख्य उद्देश्य से आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय,, भारत सरकार के तत्त्वावधान में निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद् का गठन सन् 1990 में एक शीर्षस्थ स्वायत्त संगठन के रूप में किया गया । उत्तरोत्तर राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीतियों में इस बात पर बल दिया गया कि अपशिष्ट-आधारित एवं स्थानीय भवन सामग्रियों की तकनीकों के नवीनीकरण, अन्वेषण व तकनीकी प्रचार-प्रसार के माध्यम से लागत-प्रभावी आवास परियोजनाओं व योजनाओं के निष्पादन के लिए एकीकृत व आत्मनिर्भर दृष्टिकोण अपनाया जाये ।

अभिनव और पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्रियों तथा निर्माण प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों में बी.एम.टी.पी.सी. ने, परिषद् के मैडेट में दिए गए बहु-आयामी उद्देश्यों को पूरा करने हेतु कार्यकलापों की शृंखलाएं आरम्भ की हैं । पिछले वर्षों में, परिषद् ने अभिनव, लागत प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा दक्ष निर्माण सामग्रियों तथा प्रौद्योगिकियों के संवर्द्धन एवं विकास पर ध्यान केन्द्रित किया है । आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के सक्रिय समर्थन से परिषद् ने वैम्बे योजना के अंतर्गत बड़ी आवास परियोजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा अभिनव निर्माण सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के फील्ड स्तरीय अनुप्रयोग भी आरम्भ किया है । अपने प्रौद्योगिकी विकास, संवर्द्धन और प्रसार संबंधी प्रयासों में परिषद् ने, बांस-चटाई उत्पादन केन्द्रों की स्थापना सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में आवास एवं भवन निर्माण और प्रदर्शन इमारतों के निर्माण में बांस के इस्तेमाल के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित की । सबसे पहली वल्लरेबिलिटी एटलस ॲफ इंडिया प्रकाशित कराने के अलावा, परिषद्, प्राकृतिक खतरों के प्रति सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों के निर्माण उप-नियमों में संशोधन करने के लिए उनकी सहायता भी कर रही है । परिषद् को, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर. एम.) के अंतर्गत बी.एस.यू.पी. और आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन तथा निगरानी के लिए नामजद किया गया है । हाल के वर्षों में परिषद् ने लागत प्रभावी निर्माण सामग्रियों और निर्माण तकनीकों के गहन मूल्यांकन, प्रसार और प्रदर्शन के जरिए प्रौद्योगिकियों के संवर्द्धन और विपणन के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्निर्धारण किया है ।

उद्देश्य

- आवास एवं निर्माण क्षेत्र में किफायती, नवीन भवन सामग्रियों व निर्माण तकनीकों के विकास, उत्पादन, मानकीकरण और विस्तृत अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करना ।
- तकनीकी सहायता और कर-सम्बंधी रियायत सुलभ करा कर अपशेषों पर आधारित नई भवन सामग्रियों व अवयवों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के

- लिए आवश्यक कियाकलाप चलाना तथा उद्यमियों को विभिन्न शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए उत्साहित करना
- प्राकृतिक आपदा उपशमन, इमारतों की भेद्यता एवं जोखिम—न्यूनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/पुर्णनिर्माण तथा मानव बसावों में आपदा प्रतिरोधी डिजाइन व योजना प्रचलन के लिए पद्धतियों एवं तकनीकों का विकास व प्रोत्साहन।
 - भवन सामग्री एवं निर्माण क्षेत्र में प्रयोगशाला से वास्तविक प्रयोग क्षेत्र तक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए व्यवसायियों (प्रोफेशनल्स), निर्माण एजेंसियों तथा उद्यमियों को चुनाव, मूल्यांकन, उन्नयन, डिजाइन अभियांत्रिकी, दक्षता उन्नयन और विपणन जैसी सहायक सेवाएं उपलब्ध कराना।

प्रमुख कार्य क्षेत्र

- किफायती भवन निर्माण सामग्रियों, उनके उत्पादन और उपलब्धता की उत्तरात्तर बढ़ातरी के लिए नीतिगत माहौल में सुधार करना।
- उड़नराख, लाल मिट्टी, फास्फॉजिप्सम, कृषि अपशिष्टों और अन्य दूसरे अपशेषों और उत्पादों पर आधारित निर्माण सामग्रियों/घटकों की उत्पादन इकाइयों का संवर्द्धन।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योग स्तरीय निर्माण सामग्रियों की उत्पादन इकाइयों का आधुनिकीकरण।
- निर्माण लागत में मितव्ययिता को बढ़ावा देना।
- स्थानीय निर्माण सामग्रियों के लिए मानकों का निर्धारण।
- राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ काम करते हुए भवन सामग्री क्षेत्र में और अधिक पूजी निवेश आकर्षित करने के लिए औद्योगिक विस्तार सेवा का सुदृढ़ीकरण।
- प्रौद्योगिकी विकास, उसकी जानकारी प्राप्त करना, उसका समाहिकरण करना तथा प्रचार-प्रसार करना।
- प्राकृतिक आपदा उन्मुख क्षेत्रों में वलरेबिलिटी एवं जोखिम का निर्धारण।
- आपदा प्रतिरोधी निर्माण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
- भवन सामग्रियों और निर्माण क्षेत्रों में विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी खोज एवं संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना।

वर्ष 2006–2007 के दौरान प्रमुख पहलें एवं कार्यकलाप

I. लागत-प्रभावी प्रौद्योगिकियों के उपयोग से प्रदर्शन घरों का निर्माण

1. वैम्बे के अंतर्गत प्रदर्शन घरों का निर्माण

जैसाकि पहले सूचित किया गया है, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वैम्बे), जिसका विलय अब जे.एन.एन.यू.आर.एम. की आई.एच.एस.डी.पी. के साथ हो गया है, के अन्तर्गत बी.एम.टी.पी.सी. को लागत प्रभावी निर्माण सामग्रियों और आपदा प्रतिरोधी निर्माण प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके प्रदर्शन गृहों के निर्माण का कार्य सौंपा था। इस समय इस परियोजना के अंतर्गत पांच राज्यों में प्रदर्शन गृहों का निर्माण आरम्भ कर दिया गया है, जो निम्नलिखित हैं:

- नागपुर, महाराष्ट्र में 70 प्रदर्शन गृह
- देहरादून, उत्तरांचल में 100 प्रदर्शन गृह
- बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में 100 प्रदर्शन गृह
- कुडालू, कर्नाटक में 70 प्रदर्शन गृह
- त्रिचि, तमिलनाडु में 100 प्रदर्शन गृह।

विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति निम्नलिखित है:

नागपुर (महाराष्ट्र):

परिषद ने कलमाना, नागपुर में भूकम्प प्रतिरोधीपन के लिए भूतल स्तर पर टाई बीमों और आर.सी.सी. लिंटल, फेरोसीमेंट डोर शटरों तथा उडन राख पॉलिमर, प्रिकास्ट आर.सी.सी., डोर फ्रेमों, फर्श/छत के लिए फिल्लर स्लैब, चिनाई के लिए उडन राख/जिस्पम का इस्तेमाल करके सॉलिड/खोखले ब्लॉकों, नीव के लिए अंडर-रीम्ड पाइल्स जैसी विभिन्न लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके 70 प्रदर्शन गृहों के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया है। प्रत्येक इकाई का क्षेत्र 181 वर्ग फुट है और प्राप्त हुई निर्माण लागत 275 रुपए प्रति वर्ग फुट है। नागपुर इम्पूवमेंट ट्रस्ट, जो राज्य सरकार की नोडल एजेंसी है, से अनुरोध किया गया है कि वह पूरे कर लिए गए घरों का कब्जा प्राप्त कर लें।

देहरादून (उत्तरांचल):

तीन विभिन्न स्थानों, अर्थात् राम कृष्ण आश्रम, त्यागी रोड (28 इकाइया), रोटरी क्लब, कुष्ठ आश्रम, भगत सिंह कालोनी (34 इकाइया) और शान्ति कुष्ठ आश्रम, भगत सिंह कालोनी (38 इकाइया) पर 100 घरों का काम पूरा कर लिया गया है। प्रत्येक इकाई का क्षेत्र 181 वर्ग फुट है और प्राप्त हुई निर्माण लागत 250 रुपये प्रति वर्ग फुट है। इस परियोजना में छत डालने के लिए प्रिकास्ट आर.सी.सी. तख्तों और कड़ियों, दीवार बनाने के लिए सॉलिड कंक्रीट ब्लॉकों, आर.सी.सी. डोर फ्रेमों, छज्जों, प्लैंक और जायस्ट्स, शेल्वों आदि जैसी लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों का

इस्तेमाल किया गया है।

बिलासपुर (छत्तीसगढ़):

इमलीभट्टा, बिलासपुर में स्लम में रहने वाले लोगों के लिए 100 घरों का निर्माण किया जा रहा है। यह रो टाइप आवास हैं, जिनमें एक ब्लॉक में 12 इकाइयां हैं, 8 इकाइयां भूतल पर हैं और 4 इकाइयां प्रथम तल पर हैं। सभी आठ ब्लॉकों में भूतल के छत स्तर पर प्रिकास्ट रूफिंग कम्पोनेंट्स स्थापित करने का काम लगभग पूरा होने वाला है।

कुड़ालू (कर्नाटक):

कुड़ालू बंगलौर में 70 आवास इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें भूतल+2 तल हैं। प्रथम तल स्तर की चिनाई का काम पूरा हो जाने के पश्चात प्रथम तल के रूप स्लैब की कास्टिंग का काम चल रहा है।

त्रिचि (तमिलनाडु):

त्रिचि (तमिलनाडु) नागामंडलम, त्रिचि में क्लस्टर अप्रोच में सिंगल स्टोरी में डिजाइन की गई 100 आवास इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। सभी 100 इकाइयों का चिनाई कार्य दहलीज स्तर तक पूरा कर लिया गया है।

2. मिजोरम और त्रिपुरा में बांस आधारित इमारतों का प्रदर्शन

बी.एम.टी.पी.सी. ने मिजोरम और त्रिपुरा, दोनों में बांस आधारित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके 10 प्रदर्शन इमारतों के निर्माण का काम आरम्भ किया है। इन इमारतों में घर, ओपीडी. बिल्डिंग, पुस्तकालय की बिल्डिंग, पिकनिक हट, स्कूल आदि शामिल हैं।

पिछले वर्ष के दौरान मिजोरम में 9 इमारतों का काम पूरा किया गया था। दसवीं इमारत, अर्थात् स्कूल बिल्डिंग का काम भी पूरा कर लिया गया है और इसे राज्य सरकार को सौंप दिया गया है।

बांस आधारित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके 6 प्रदर्शन इमारतों के निर्माण का काम त्रिपुरा में पूरा किया गया है और इसे राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। शेष बची चार इमारतों पर कार्य चल रहा है।

परम्परागत निर्माण की तुलना में विभिन्न प्रकार की इमारतों के लिए बांस आधारित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके, कारपेट ऐरिया पर निर्भर करते हुए निर्माण लागत में 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की काफी कमी आई है। विभिन्न प्रकार की इमारतों के निर्माण के दौरान स्थानीय ठेकेदारों, राज मिस्त्रियों, कारीगरों को भवन निर्माण में बांस का इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

3. बड़ी आवास परियोजनाओं में लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों का फील्ड स्तरीय अनुप्रयोग

पिछले वर्ष के दौरान परिषद ने बवाना, दिल्ली में दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचनात्मक विकास निगम (डी.एस.आई.आई.डी.सी.) को 3164 घरों के निर्माण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की थी। फील्ड स्तर पर पर्यावरण-अनुकूल और

लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों के सफल प्रदर्शन के कारण नई बड़ी आवास परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं, जैसे डी.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा नरेला में 1892 इकाइयों, बोरगढ़ में 1200 इकाइयों और बवाना में 1184 इकाइयों का निर्माण। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने भी ओमिक्रॉन-II, ग्रेटर नोएडा में 1848 ई.डब्ल्यू.एस. घरों की नई परियोजनाएं आरम्भ की हैं और ओमनीबस औद्योगिक विकास निगम द्वारा दादरा और नगर हवेली में 576 ई.डब्ल्यू.एस. घरों की नई परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं।

II. आपदा उपशमन – मरम्मत, पुनर्निर्माण और रेट्रोफिटिंग

1. वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया –पहला संशोधन (2006) का विमोचन

प्राकृतिक आपदा अल्पीकरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दशक (आईडीएनडीआर) –1990–2000 की मध्यावधि समीक्षा के दौरान सुरक्षित विश्व के लिए योकोहामा रणनीति की अनुवर्ती कार्यवाई के रूप में तत्कालीन शहरी विकास मंत्रालय ने, सबसे पहली वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया तैयार करने हेतु एक विशेषज्ञ समूह (1994) गठित किया था। बी.एम.टी.पी.सी द्वारा 1997 में तैयार की गई इस एटलस में भूकम्पों, चक्रवातों और बाढ़ों के सम्बन्ध में खतरा दर्शाने वाले नक्शे और हाउसिंग स्टॉक की जिला-वार खतरे सम्बन्धी सारणियां दी गई हैं। इसके प्रकाशन के समय से ही इस एटलस ने आपदा-पूर्व अल्पीकरण तथा सरकार की योजना तैयार करने के लिए एक बहुत प्रभावी आरम्भिक साधन का मार्ग प्रशस्त किया है।

नए राज्यों और जिलों के बन जाने, भूकम्प के खतरे वाले जोनेशन नक्शों में परिवर्तन, बाढ़ के परिदृश्य में परिवर्तन, भूकम्पीय – टेक्टोनिक विवरणों की उपलब्धता, आई.एम.डी. से प्राप्त अद्यतन स्टोर्म सर्ज डाटा, आवास सम्बन्धी परिदृश्य में परिवर्तनों पर विचार करते हुए आवास एवं शहरी गरीबी उपमशन मंत्रालय ने इस एटलस में संशोधन एवं अद्यतनीकरण करने के लिए प्रोफेसर ए.एस. आर्य, राष्ट्रीय भूकम्प सलाहकार की अध्यक्षता में अन्य सम्बन्धित संगठनों के विशेषज्ञों का एक बहुविध समकक्ष समूह स्थापित किया था।

बी.एम.टी.पी.सी. द्वारा तैयार की गई, संशोधित एटलस विशेषज्ञ समूह द्वारा की गई चर्चा और बैठकों की एक शृंखला में उपलब्ध सभी आंकड़ों के विस्तृत अध्ययन का परिणाम है। इस एटलस में भूकम्पों, चक्रवातों, बाढ़ों के सम्बन्ध में खतरा दर्शाने वाले डिजिटाइज्ड नक्शे और 2001 की जनगणना के अनुसार हाउसिंग स्टॉक की जिला-वार जोखिम तालिकाएं दी गई हैं। इसमें भू-स्खलन के खतरे वाले नक्शे और सुनामी पर एक अध्याय भी शामिल है।

प्राकृतिक खतरों की स्थिति में संभावित तीव्रता पर अद्यतन सूचना वाली और हाउसिंग तथा बिल्डिंग के परिणामी खतरों के स्तर वाली यह संशोधित एटलस हमारी भावी आपदा प्रबंधन योजना और तैयारी में बहुत उपयोगी होगी।

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा गठित किए गए विशेषज्ञ समूह ने 9 अक्टूबर, 2006 को मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। संशोधित वलरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया को मुद्रित कराया गया था और इसका विमोचन माननीय शहरी विकास मंत्री, श्री एस. जयपाल रेड़ी द्वारा माननीया आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कुमारी शैलजा की उपरिथिति में दिनांक 13 दिसम्बर, 2006 को नई दिल्ली में आयोजित की गई 'आवास एवं मानव अधिवास' विषय पर एशिया-पेसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान किया गया।

2. मॉडल निर्माण उप-नियमों पर एक दिवसीय तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन – गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित

जैसकि पहले सूचना दी गई है, परिषद्, गृह मंत्रालय के साथ एक संयुक्त कार्यकलाप के रूप में, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग एकट, जोनिंग विनियम, प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सुरक्षा हेतु निर्माण विनियमों में मॉडल संशोधन पर एक दिवसीय तकनीकी कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है ताकि मॉडल उपनियमों में दिए गए उपबंधों के अनुसार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के उपनियमों, अधिनियमों को संशोधित करने में उनकी सहायता कर सके। इस वर्ष के दौरान यी एम टी पी सी ने निम्नलिखित राज्यों में कार्यशालाएं आयोजित की:

इटानगर, अरुणाचल प्रदेश	25 अप्रैल, 2006
इम्फाल, मणिपुर	21 अगस्त, 2006
एजवाल, मिजोरम	24 अक्टूबर, 2006
कोहिमा, नागालैंड	23 नवम्बर, 2006
पोर्ट ब्लायर, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	17-18 जनवरी, 2007
गंगटोक, सिक्किम	16 फरवरी, 2007
रांची, झारखण्ड	12 मार्च, 2007

इंजीनियरों और आर्कीटेक्टों सहित राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने इन कार्यशालाओं में भाग लिया। गृह मंत्रालय द्वारा गठित किए गए विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकार, अपने उपनियमों में संशोधन करने के लिए कार्रवाई कर रही हैं।

परिषद्, अगले वर्ष के दौरान बाकी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, दिल्ली और महाराष्ट्र में कार्यशालाएं आयोजित करेगी।

3. जम्मू एवं कश्मीर में आये भूकम्प के बाद बी.एम.टी.पी.सी. की पहलें

श्रीनगर से केवल 100 किलोमीटर दूर, सीमा नियंत्रण रेखा के बिल्कुल निकट, पाकिस्तान के मुज्जफराबाद में स्थित अधिकेन्द्र के साथ 5 अक्टूबर, 2005 को 7.6 (रिएक्टर पैमाने पर) की तीव्रता का एक भूकम्प आया। भूकम्प का प्रभाव इतना तीव्र था कि इसने जम्मू एवं कश्मीर राज्य में और मुख्य रूप से कश्मीर घाटी के बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में अत्यधिक क्षति पहुंचाई।

बी.एम.टी.पी.सी. ने, जम्मू एवं कश्मीर में भूकम्प के आवेग में स्थिति का तत्काल आकलन करने के लिए केन्द्रीय दल में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया।

रेट्रोफिटिंग प्रौद्योगिकियां दर्शाने वाले और जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र में स्थानीय सामग्रियों का इस्तेमाल करके भूकम्प प्रतिरोधी घरों के निर्माण के लिए "भूकम्प सुरक्षा के लिए सरल तरीके" शीर्षक वाली बुकलेट के अंग्रेजी और उर्दू दोनों भाषाओं में तथा 10 पोस्टरों का एक सैट छपवाया गया और जम्मू एवं कश्मीर के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में विस्तृत रूप से परिचालित किया गया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के साथ परिषद् ने आपदा अल्पीकरण और प्रबंधन तकनीक विषयों में, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में 300 इंजीनियरों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

4. भूकम्प के प्रति सुरक्षा के लिए कुपवाड़ा, जम्मू एवं कश्मीर में उप-जिला अस्पताल की रेट्रोफिटिंग

जम्मू एवं कश्मीर के भूकम्प प्रभावित क्षेत्र में केन्द्रीय दल के दौरे के दौरान यह अवलोकन किया गया कि कुपवाड़ा में उप-जिला अस्पताल में भूकम्प के कारण क्षति पहुंची थी। यह भी अवलोकन किया गया कि जहां तक भूकम्प के प्रति सुरक्षा का सम्बन्ध है, अस्पताल में अनेक कमियां थीं। डिवीजनल कमीशनर, श्रीनगर और भारत सरकार के राष्ट्रीय भूकम्पीय सलाहकार डॉ. ए.एस. आर्य के साथ की गई चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया गया कि अस्पताल, जो एक लाइफ लाइन भवन है, इस भवन में बी.एम.टी.पी.सी. द्वारा भूकम्पीय सुदृढीकरण का काम आरम्भ किया जा सकता है ताकि भूकम्पों के प्रति सुरक्षा के लिए रेट्रोफिटिंग तकनीकों को प्रदर्शित किया जा सके। तदनुसार, नेशनल सेंटर फॉर पीपल्स एक्शन इन डिसास्टर प्रीपियर्डनस (एन.सी.पी.डी.पी.) जो अहमदाबाद, गुजरात का एक गैर-सरकारी संगठन है, जिसने गुजरात में भूकम्प के बाद पुनर्वास कार्यक्रम में बी.एम.टी.पी.सी. के साथ इस प्रकार के कार्य किए हैं, की सहायता से, इसके भूकम्पीय मूल्यांकन के लिए बिल्डिंग अध्ययन आरम्भ किया गया।

अस्पताल की मुख्य बिल्डिंग में दो विंग हैं, अगला विंग आयताकार है और पिछला विंग वर्गाकार है। इसमें, दो मंजिल वाला, अच्छी गुणवत्ता वाले सीमेंट मोर्टर में ईंटों की चिनाई वाला निर्माण है। ऊपरि और निचली मंजिलों में लींटल स्तर पर सभी दीवारों में और पिछले विंग की ऊपरि मंजिल में ओलती स्तर के कुछ फुट नीचे, जहां दीवार लगभग 4.5 मीटर ऊंची हो, आर.सी. बैंड मौजूद हैं। अगले विंग में सामने की और पिछली दीवारों में अनेक खिड़कियां हैं, जो केवल उन संकीर्ण खम्भों से अलग-अलग की गई हैं, जो क्रास दीवारों के अलावा कुछ नहीं हैं।

अगले और पिछले विंगों के कुछ भागों में विशेष रूप से (क) खिड़कियों के बीच के ईंटों के खम्भों और (ख) जीने के पार्श्व भाग की ऊंची दीवारों में दरारें पड़ गईं।

लगभग सभी दरारें ग्रेड 2 की क्षति की श्रेणी में आती हैं। तथापि, इनमें से अधिकांश दरारें, दीवार की मोटाई के बीचोबीच हैं। इस प्रकार, इन दीवारों की मजबूती, इस क्षति के कारण काफी कम हो गई।

हालांकि, बैंडों के कारण, दीवारों में, उस बैंडिंग दबाव के प्रति पर्याप्त प्रतिरोध है, जो समतल भूकम्पीय शक्तियों के कारण हो सकता है। कुछ अन्य निम्नलिखित अंतर्निहित असुरक्षितताएं भी थीं:

- दीवारों में कोई ऐसा वर्टीकल रिइन्फोर्समेंट नहीं था, जो मुख्य बाहरी दीवार को तन्यता प्रदान कर सकता था।
- अगले और पिछले विंगों में किसी भी खुले स्थान पर आर.सी.सी. खोल नहीं था। खुले स्थानों के कोनों में आसानी से तिरछी या रेकिंग शीयर दरारें पड़ सकती हैं।
- उत्तरी और दक्षिणी बाहरी दीवारों में, बड़ी खिड़कियों के कारण व्यावहारिक रूप से कोई शीयर दीवार नहीं है।
- सर्जिकल वार्ड में कमरे बड़े हैं और दीवारें 5 मीटर से अधिक ऊंची हैं।
- अटारी के टिम्बर डैक, जो सामने के विंग में ईंट की दीवारों पर टिका हुआ है, सुनम्य है, क्योंकि इसमें अंदर की तरफ केवल सजावटी फाल्स सीलिंग है। पिछले विंग में अटारी में अच्छा टिम्बर फलैंक फ्लोर है। परन्तु डैक केवल दीवारों के ऊपरि हिस्से पर टिका था और टिम्बर वाले प्लेटों पर स्थिरक था, जिसका दीवारों के साथ अन्यथा कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि उस स्तर पर कोई आर.सी. बैंड मौजूद नहीं है।

ठाइप डी प्रकार की इमरातों में भूकम्पीय निष्पादन स्तर सुनिश्चित करने के लिए बिल्डिंग को रेट्रोफिट करना महत्वपूर्ण माना गया। इसमें निम्नलिखित सुधारों की आवश्यकता थी:

- सभी कोनों में उर्ध्वाधर प्रबलीकरण स्थापित करना।
- दीवारों से सम्बद्ध दीवारों और वेल्डिड वायर मैश के बने भूकम्पीय बैल्टों से सभी खुले स्थानों को ढकना।
- 5 मीटर से अधिक लम्बाई वाली दीवारों के दोनों तरफ और सभी दीवारों के एक तरफ ओलती स्तर की भूकम्पीय बेल्ट स्थापित करना।
- एम.एस. एंगल ब्रैकिटों या अन्य उपयुक्त विकल्पों का इस्तेमाल करके दीवारों में रुफ डक की एंकरिंग करना।
- छत के निचले कोर्ड के ऊपरी सिरे पर डायगनल ब्रेसिंग स्थापित करके, अगले विंग के रुफ डक की डायफ्राम क्रिया में सुधार करना।

कुपवाड़ा के उप-डिवीजन अस्पताल की बिल्डिंग का रेट्रोफिटिंग कार्य, इसके नेटवर्क पार्टनर एन.सी.पी.डी.पी., अहमदाबाद के जरिए पूरा कर लिया गया है। स्थानीय जनता, अस्पताल के स्टाफ, सुरक्षा स्टाफ आदि ने, रेट्रोफिटिंग तकनीकों के ब्योरे जानने में गहरी रुचि दिखाई। अस्पताल की बिल्डिंग में इस्तेमाल किए गए

भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण के सम्बन्ध में सूचना के प्रसार के लिए तैयार किए गए पोस्टरों को आम जनता से अच्छा प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ। इसने, कुपवाड़ा में सुरक्षित निर्माण पद्धति के बारे में जागरूकता उत्पन्न की।

5. दिल्ली नगर निगम के भवनों में भूकम्पीय सुदृढ़ीकरण के लिए रेट्रोफिटिंग तकनीकों का प्रदर्शन

भूकम्पीय सुदृढ़ीकरण के लिए रेट्रोफिटिंग तकनीकों को प्रदर्शित करने के अपने प्रयासों में परिषद् ने दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की रेट्रोफिटिंग के जरिए प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने की पहल की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, बी.एम.टी.पी.सी, दिल्ली में 12 म्युनिसिपल वार्डों में एक-एक, दिल्ली नगर निगम के स्कूल की 12 बिल्डिंगों की रेट्रोफिटिंग करने में संलग्न है ताकि रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता और तकनीकों के बारे में लोगों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच जागरूकता उत्पन्न की जा सके। दिल्ली नगर निगम के पदाधिकारियों की सहायता से, रेट्रोफिटिंग के लिए स्कूलों का चयन कर लिया गया है।

आरम्भ में, इंडियन एयरलाइन्स कालोनी, वसन्त विहार में दिल्ली नगर निगम के स्कूल की बिल्डिंग का भूकम्पीय सुदृढ़ीकरण और रेट्रोफिटिंग का काम आरम्भ किया गया था और यह कार्य पूरा कर लिया गया है। रेट्रोफिटिंग के दौरान दिल्ली नगर निगम के स्थानीय इंजीनियरों और ठेकेदारों को भी प्रशिक्षित किया गया था। दिल्ली नगर निगम की चयनित 4 स्कूल बिल्डिंगों की रेट्रोफिटिंग और भूकम्पीय सुदृढ़ीकरण के लिए, शॉर्ट-लिस्ट किए गए नगर निगम के चार स्कूलों के रेट्रोफिटिंग कार्य के निष्पादन के लिए 'वर्किंग ड्राइंग' को अंतिम रूप दे दिया गया है। चार स्कूली बिल्डिंगों का रेट्रोफिटिंग कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

6. भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन और निर्माण पर अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शृंखलाएं

वर्तमान दशक में भूकम्पों के कारण भारत में कई बड़ी आपदाएं आई हैं, जैसे 26 जनवरी 2001 का भुज का भूकम्प, 8 अक्टूबर, 2005 का कश्मीर का भूकम्प। अधिकांश मौतें, बिल्डिंगों के ढहने के कारण या ढह गई बिल्डिंगों के नीचे दबे पीड़ितों के बचाव एवं राहत की कमी के कारण, हुई थीं। इन भूकम्पों से स्पष्ट रूप से आपदा अल्पीकरण के लिए ऐसी व्यापक रणनीति तैयार करने की आवश्यकता महसूस हुई, जिसमें भूकम्प प्रतिरोधी उपायों के लिए कोडल उपबन्धों के सख्ती से अनुपालन करने के जरिए भूकम्प प्रतिरोधी बिल्डिंगों की योजना, डिजाइन और निर्माण शामिल हों।

आर्काटेक्टों, टाउन प्लानरों, बिल्डरों और सिविल/ संरचनात्मक इंजीनियरों को प्रशिक्षण प्रदान करने और भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन तथा कोडल उपबन्धों की मौजूदा पद्धति से उन्हें अवगत करने के लिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के निकट सहयोग से परिषद् द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक शृंखला आयोजित करने हेतु पहल की गई है। इससे सभी अध्ययनों, निष्कर्षों, भूकम्पीय आंकड़ों, भूकम्प की विशिष्ट विशेषताओं, क्षति रिपोर्टिंग और रेट्रोफिटिंग अनुभवों को समेकित करने का अवसर प्राप्त होगा।

उपरोक्तानुसार, परिषद द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के साथ संयुक्त रूप से, एन.आई.टी.एस., नोएडा में 8 से 12 जनवरी, 2007 तक 'कार्य-निष्पादन आधारित डिजाइन और बिल्डिंगों तथा इमारतों की रेट्रोफिटिंग' विषय पर एक 5 दिवसीय अल्पकालिक प्रमाणपत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 25 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिनिधियों में सी.पी.डब्ल्यू.डी., एन.टी.पी.सी., एन.एच.पी.सी., राज्यों के सार्वजनिक निर्माण विभागों, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड आदि जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। संकाय सदस्यों में भूकम्प इंजीनियरी विभाग, आई.आई.टी., रुड़की के प्रोफेसर और बी.एम.टी.पी.सी. के आफिसर-चीफ (बी.एम.) शामिल थे।

III. पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कार्यकलाप

1. स्थानीय संसाधनों और आपदा प्रतिरोधी निर्माण पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रों में किए गए महत्वपूर्ण कार्यकलाप

बी.एम.टी.पी.सी., बांस की प्रोसेसिंग हेतु बांस चटाई उत्पादन केन्द्र स्थापित करके, बांस आधारित उत्पादों के वाणिज्यिक उत्पादन को प्रोत्साहित करके, प्रदर्शन घरों आदि का निर्माण करके, बांस आधारित प्रौद्योगिकियों का विकास करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा बांस के उत्पादन वाले अन्य क्षेत्रों में इन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के काम में लगा हुआ है। परिषद, बांस की प्रोसेसिंग में स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के काम में भी लगा हुआ है। परिषद, पूर्वोत्तर क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यकलाप चला रहा है:

प्रदर्शन इमारतों का निर्माण

बी.एम.टी.पी.सी. ने, मिजोरम और त्रिपुरा में बांस आधारित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके 10–10 प्रदर्शन इमारतों का निर्माण कर रही है। इनमें घर, ओ.पी.डी. बिल्डिंगों, पुस्तकालय की बिल्डिंगें, पिकनिक हटें, स्कूल आदि शामिल हैं। मिजोरम में सभी इमारतों का निर्माण पूरा कर लिया गया था और इन्हें राज्य सरकार को सौंप दिया गया था। त्रिपुरा में बांस आधारित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके 6 इमारतों का निर्माण पूरा कर लिया गया है और इन्हें त्रिपुरा सरकार को सौंप दिया गया है। बाकी चार इमारतों पर कार्य चल रहा है। परम्परागत निर्माण की तुलना में बांस आधारित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करने से निर्माण लागत में 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक की कमी आई है। विभिन्न प्रकार की इमारतों के निर्माण के दौरान, स्थानीय ठेकेदारों, राज मिस्त्रियों, कारीगरों को, भवन निर्माण में बांस के इस्तेमाल पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। इस्तेमाल किए गए विनिर्देशन निम्नलिखित हैं:

- संसाधित बांस के कॉलम और बीम।
- बांस ग्रिड रिइन्फोर्समेंट पर फेरो सीमेंट दीवारें।
- संसाधित बांस की कॉचियां, कड़ियां और बत्ते।
- दरवाजे के शटरों के लिए लकड़ी के फ्रेमों में बांस चटाई के बोर्ड

- बांस की चटाई कोरुगेटड रूफिंग शीटें।
- दरवाजे और खिड़कियों के फ्रेमों के लिए, स्थानीय रूप से उपलब्ध लकड़ी।
- आई.पी.एस. फर्श आदि।

बांस चटाई उत्पादन केन्द्रों की स्थापना

बी.एम.टी.पी.सी., केन एण्ड बम्बू टेक्नोलॉजी सेंटर (सी.बी.टी.सी.), गुवाहाटी तथा राज्य सरकार के सहयोग से असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में दो-दो बांस चटाई उत्पादन केन्द्र स्थापित कर रही हैं। बांस चटाई उत्पादन केन्द्रों के मुख्य उद्देश्य हैं – उत्पादकता, गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए, बांस आधारित निर्माण संघटकों की विनिर्माण इकाइयों को बांस की चटाईयों की अबाधित आपूर्ति उपलब्ध कराना, चटाई उत्पादन प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रदान करना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करना। पहले चरण में, परिषद्, कोवईफंग, त्रिपुरा; साइरंग और बुआलपुई, मिजोरम तथा सोखर नोंगतलुह, मेघालय में बांस चटाई उत्पादन केन्द्र स्थापित कर रही हैं। परिषद् ने पहले ही कोवईफंग, त्रिपुरा और साइरंग, मिजोरम में बांस चटाई उत्पादन केन्द्रों की स्थापना का कार्य पूरा कर लिया है। बाकी दो स्थानों पर बी.एम.टी.पी.सी. की स्थापना का काम, पूरा होने के अंतिम चरण में है।

सी.बी.टी.सी. के सहयोग से, परिषद्, प्रत्येक बांस चटाई उत्पादन केन्द्र के कारीगरों को बांस चटाई उत्पादन में प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है। प्रत्येक उत्पादन केन्द्र की उत्पादन क्षमता 300 चटाई प्रतिदिन होगी। यह अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक केन्द्र 35/- रुपए प्रति चटाई की दर से चटाई का उत्पादन करने में सक्षम होगा और 45/- रुपए प्रति चटाई की दर से बेच सकेगा। इससे लगभग 150 महिला/ पुरुष प्रतिदिन अर्थात् 45,000 महिला/पुरुष प्रति वर्ष प्रति केन्द्र का रोजगार सृजन होगा। उपरोक्त के अलावा, केन्द्र, हैंडीक्राफ्ट के सामान बनाने के लिए कारीगरों को, बांस अवशिष्ट से बनी बांस की छड़ियों की आपूर्ति करके आय सृजित कर सकते हैं। बांस चटाई उत्पादन केन्द्रों द्वारा उत्पादित चटाईयों का उपयोग उन विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा भी किए जाने की संभावना है, जो बांस चटाई कोरुगेटड रूफिंग शीटों, बांस चटाई बोर्डों आदि का उत्पादन कर रहे हैं।

प्रौद्योगिकी प्रदर्शन व उत्पादन केन्द्र की स्थापना

परिषद्, अगरतला के निकट, लागत प्रभावी अभिनव निर्माण सामग्रियों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रदर्शन व उत्पादन केन्द्र की स्थापना कर रही है, जिसके लिए राज्य सरकार ने पहले ही स्थान का चयन कर लिया है। त्रिपुरा में प्रौद्योगिकी प्रदर्शन व उत्पादन केन्द्र स्थापित करने के लिए कार्रवाई आरम्भ की गई थी। शेड के निर्माण का कार्य उन्नत चरण में है।

IV. निर्माण क्षेत्र में सूचना और डाटाबेस को सुदृढ़ बनाना

1. विश्व पर्यावास दिवस, 2006 के अवसर पर "सिटीज – मेगनेट ऑफ होप" विषय पर न्यूज लैटर के विशेष अंक का प्रकाशन

परिषद् द्वारा, विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर "सिटीज–मेगनेट ऑफ होप" विषय पर बिल्डिंग मेटीरियल्स न्यूज के एक विशेष अंक का विमोचन, नई दिल्ली में 3 अक्टूबर, 2006 को विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर कुमारी शैलजा, माननीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा किया गया। इस प्रकाशन में, उपरोक्त विषय से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर लेख हैं। इस प्रकाशन का परिचालन, इस विषय में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों में व्यापक रूप से किया गया।

2. नेपाल और भूटान पर सूचना के साथ भारतीय निर्माण सामग्रियों एवं उत्पादों की डायरेक्टरी – सातवां संस्करण: 2006 का विमोचन

निर्माण क्षेत्र में तेजी से होने वाले विस्तार के प्रत्युत्तर में और व्यवसायविदों की आवश्यकताओं को महसूस करते हुए, परिषद् इस क्षेत्र के डाटाबेस को सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय निर्माण सामग्रियों एवं उत्पादों की एक डायरेक्टरी निकाल रही है। 1994, 1996, 1998, 2000, 2002 और 2004 में निकाले गए छ: संस्करणों को उत्कृष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ। डायरेक्टरी के सातवें संस्करण की संरचना, अधिक आसान फोरमेट में, एक सशक्त सूचना भंडार के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए, की गई है। विभिन्न क्षेत्रों से 4500 से भी अधिक भारतीय विनिर्माताओं पर सूचना के अलावा, इस संस्करण में नेपाल और भूटान की निर्माण सामग्रियों और उत्पादों पर सूचना शामिल की गई है। डायरेक्टरी का प्रकाशन बी.एम.टी.पी.सी. और एस.टी.ई.एम., बंगलौर के संयुक्त प्रकाशन के रूप में किया गया है और इसे हुडको द्वारा प्रायोजित किया गया है। डायरेक्टरी का विमोचन, नई दिल्ली में 3 अक्टूबर, 2006 को विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर कुमारी शैलजा, माननीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा किया गया। इस बार भी परिषद् ने, प्रकाशन का विपणन करने और प्रेक्षितशनरों, आर्चाटेक्टों, इंजीनियरों और निर्माण व्यवसायविदों के बीच इसकी पहुंच में वृद्धि करने के लिए मास्टर बिल्डर – एक व्यावसायिक पत्रिका के प्रकाशक को आमंत्रित किया।

3. परिषद् की वेबसाइट के माध्यम से सूचना का प्रसार

परिषद् की वेबसाइट (www.bmtpc.org), विद्वानों और व्यवसायविदों सहित स्टेकहोल्डरों के बीच बहुत लोकप्रिय है और इसका इस्तेमाल, संदर्भ स्रोत के रूप में किया जा रहा है। परिषद्, उत्पाद और सेवाओं, विपणन मार्गदर्शकों, व्यापार संबंधी पृच्छाओं, प्रकाशन की बिक्रियों, संयुक्त उद्यम आदि के बारे में आम इन्क्वायरी के रूप में वेबसाइट पर नियमित रूप से प्रभावशाली प्रत्युत्तर प्राप्त करती रही है। मौजूदा वर्ष के दौरान, इसने काफी व्यापार सृजित किया है और उपयोगकर्ताओं ने इसकी विषयवस्तु को पढ़ा है तथा लागत प्रभावी, पर्यावरण-अनुकूल, ऊर्जा दक्ष एवं

आपदा प्रतिरोधी निर्माण प्रौद्योगिकियों पर सूचना प्राप्त करने के लिए निःशुल्क प्रकाशनों को डाउनलोड किया है।

किराए पर लेने, खरीदने संबंधी आवश्यकताओं, निविदा सूचनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सूचना का अधिकार अधिनियम जैसी सूचनाओं तथा समय-समय पर यथा आवश्यक अन्य सूचनाओं को शामिल करने के लिए परिषद् की वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाता है।

4. मानकीकरण और उत्पाद मूल्यांकन

किसी उत्पाद, जिसमें निर्माण सामग्रियां, उत्पाद, पुर्जे, एलीमेंट्स, सिस्टम्स आदि शामिल हैं, के विनिर्माताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/ स्थापितकर्ताओं को आकलन की उचित प्रक्रिया अपनाने के बादे कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए परिषद् एक तृतीय पक्ष मूल्यांकन योजना अर्थात् कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणन योजना (पी.ए.सी.एस.) चला रही है।

कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणन योजना (पी.ए.सी.एस.) का प्रचालन करने के लिए, बी.एम.टी.पी.सी. के करार बोर्ड (बी.एम.बी.ए.) की पहली बैठक 18 अप्रैल, 2006 को अध्यक्ष श्री बी. मजूमदार, तत्कालीन महानिदेशक, सी.पी.डब्ल्यू.डी. की अध्यक्षता में हुई। बोर्ड द्वारा नीति संबंधी दिशानिर्देशों का अनुमोदन किया गया।

बी.एम.टी.पी.सी. द्वारा चलाई जा रही कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणन योजना (पी.ए.सी.एस.) की तकनीकी मूल्यांकन समिति (टी.ए.सी.) की बैठक, बी.एम.टी.पी.सी. के कार्यालय में 28 जून, 2006 को हुई थी। यह पहली बैठक होने के कारण सदस्यों को, पी.ए.सी.एस. की संकल्पना, विस्तृत प्रक्रियाएं और टी.ए.सी. के सदस्यों की भूमिका की सूचना दी गई।

इंट विनिर्माण के लिए वर्टिकल शाफ्ट बुक विलन प्रौद्योगिकी हेतु 'डवलपमेंट आल्टरनेटिव' नई दिल्ली को कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणपत्र जारी किया गया। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निम्नलिखित कम्पनियों/ विनिर्माताओं ने आवेदन किया और योजना के अंतर्गत कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणपत्र प्राप्त करने में रुचि दिखाई। फर्मों के नाम और जिस उत्पाद के लिए प्रमाणपत्र मांगा गया है, वह उत्पाद तथा स्थिति का विवरण निम्नलिखित है:

आवेदक का नाम	उत्पाद	स्थिति
डवलपमेंट आल्टरनेटिव, नई दिल्ली	वर्टिकल शाफ्ट ब्रिक विलन प्रौद्योगिकी	पी.ए.सी. जारी कर दिया गया
रिलायंस इंडस्ट्रीज, अहमदाबाद	कंकरीट और मोर्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला रिक्रोन 3 एस फाइबर	पी.ए.सी. के नीवकरण की प्रक्रिया चल रही है
रिया इंटरप्राइजज, गान्धीधाम,	फिंगर जाइंटेड लकड़ी के	परीक्षण के अधीन

ગુજરાત વી.કે. પ્લાસ્ટિક્સ, માનેસર, હરિયાણા	દરવાજે રૂફિંગ શીર્ટે	નિરીક્ષણ કાર્ય પૂરી હો ગયા હૈ
કાન્ટેક કેમિકલ્સ, પાલડી, અહમદાબાદ	સીર્ટેચિંગ આસંજક પર 6 ઉત્પાદ	પી.એ.એફ. પ્રાપ્ત હો ગયા હૈ
રાઇટવિઝન (ઇંડિયા) પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, નई દિલ્લી	વિભિન્ન આકાર ઔર રૂપ કે એચ.ડી.પી.ઈ. કવર બ્લોક	પી.એ.એફ. પ્રાપ્ત હો ગયા હૈ

भारतीय मानक ब्यूरो की सेवनशाल समितियों को तकनीकी इनपुट पी.एसी.एस. के अलावा परिषद, सीमेंट और कंकरीट, फ्लोरिंग, वाल फर्नीशिंग और रूफिंग सामग्रियों, भूकम्प इंजीनियरी, हाउसिंग प्रिफेक्ट्रीकेटड निर्माण, पर्वतीय क्षेत्र के विकास, नेशनल बिल्डिंग कोड आदि जैसे सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित विभिन्न विषयों पर भारतीय मानक बनाने हेतु भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न सेवनशाल समितियों को तकनीकी इनपुट उपलब्ध करा रही है।

V. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संवर्धनात्मक और क्षमता निर्माण कार्यकलाप

1. क्षमता निर्माण कार्यक्रम

नई निर्माण सामग्रियों, प्रौद्योगिकियों की प्रगति और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव का कम करने के लिए आपदा प्रतिरोधी निर्माण की आवश्यकता के उभर कर सामने आने के साथ यह बात महत्वपूर्ण है कि काम करने वाले व्यवसायविद्, विषयों पर अपनी जानकारी और समझबूझ को निरंतर अद्यतन बनाए रखें। व्यवसायविदों की क्षमता निर्माण की इस आवश्यकता को महसूस करते हुए बी.एम.टी.पी.सी. ने, नियमित आधार पर काम करने वाले व्यवसायविदों के लिए निर्माण सामग्रियों के क्षेत्र में हुई प्रगति से संबंधित विषयों पर संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में अपने प्रयास जारी रखे हैं। वर्ष के दौरान आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम पर संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

27-28 अप्रैल, 2006 को नई दिल्ली में "कंकरीट निर्माण के लिए रसायन और मिनरल अधिमिश्रणों का इस्तेमाल" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम पानी, समुच्चय, हाइड्रोलिक सीमेंट और फाइबर के अलावा अधिमिश्रण ऐसे संघटक हैं, जो मिश्रित करने से ठीक पहले या के दौरान कंकरीट बैच में मिलाए जाते हैं। अधिमिश्रणों का उचित इस्तेमाल, कंकरीट को कुछ लाभदायक प्रभाव प्रदान करता है, जिसमें उन्नत गुणवत्ता, सैटिंग के समय में तीव्रता या कमी, तेजी से जमना और सत्फेट प्रतिरोधी, शक्ति विकास का नियंत्रण, उन्नत कार्य क्षमता और उन्नत परिष्करणशीलता शामिल है। कंकरीट निर्माण के लिए रसायन और मिनरल अधिमिश्रणों के इस्तेमाल पर एक दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, 27-28 अप्रैल, 2006 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया ताकि निर्माण से संबंधित व्यवसायविदों की जानकारी को ताजा किया जा सके। इसका उद्देश्य निम्नलिखित

उप-विषयों को कवर करते हुए गुणवत्ता वाले निर्माण में सुविधा प्रदान करना था:

- मजबूत कंकरीट की आवश्यकताएं।
- सीमेंट – गुणधर्म और अनुप्रयोग।
- रसायन अधिमिश्रणों के मूलभूत सिद्धान्त।
- अधिमिश्रणों और कंकरीट की संगतता।
- मिनरल अधिमिश्रण – कंकरीट में उनका विशिष्ट इस्तेमाल।
- उच्च कार्य-निष्पादन वाला कंकरीट।
- स्वतः सुसम्बद्ध कंकरीट – अधिमिश्रण की भूमिका।
- मरम्मत और पुनरुद्धार के लिए अधिमिश्रणों का इस्तेमाल।

विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के 24 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

25–26 मई, 2006 को नई दिल्ली में “वाटर प्रूफिंग एण्ड डैम्प प्रूफिंग मेटीरियल्स एण्ड टेक्नीक्स फॉर बिल्डिंग्स एण्ड स्ट्रक्चर्स” विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम “वाटर प्रूफिंग एण्ड डैम्प प्रूफिंग मेटीरियल्स एण्ड टेक्नीक्स फॉर बिल्डिंग्स एण्ड स्ट्रक्चर्स” विषय पर नई दिल्ली में (फरवरी, 2006) आयोजित किए गए पिछले प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्राप्त हुए फीडबैक और अच्छे प्रत्युत्तर के आधार पर, अन्य क्षेत्रों के व्यवसायविदों के लाभ के लिए 25–26 मई, 2006 के दौरान पुणे में उसी विषय पर एक दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किए गए विषय निम्नलिखित थे:

- वाटर प्रूफिंग से संबंधित कंकरीट प्रौद्योगिकी के मूलभूत सिद्धान्त।
- वाटर प्रूफिंग की अच्छी निर्माण पद्धतियां।
- वाटर प्रूफिंग के सिद्धान्त और प्रक्रिया तंत्र।
- बेसमेंट, स्वीमिंग पूल, भूमिगत मेट्रोज, सुरंगों आदि ग्रेड से नीचे वाटर प्रूफिंग।
- इंजेक्शन ग्राउटिंग, जाइंट फिल्टर्स, इंसुलेशन।
- वाटर प्रूफिंग के मानक।
- डी.पी.सी., दीवारों के ग्रेड से ऊपर वाटर प्रूफिंग।
- बिल्डिंगों में गीले क्षेत्रों की वाटर प्रूफिंग।
- छत की वाटर प्रूफिंग – सिद्धान्त, सामग्रियां, तरीके और प्रभावोत्पादकता।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, तमीलनाडू स्लम क्लीयरेंस बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय, भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, एन.टी.पी.सी., विरला सीमेंट, सी.पी.डब्ल्यू.डी., पुणे, पी.डब्ल्यू.डी., पुणे, एम.एच.ए.डी.ए., एम.ई.एस., रक्षा मंत्रालय, ग्रेटर मुम्बई नगर निगम, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, पी.डब्ल्यू.डी., यू.पी. आदि जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों के 35 प्रतिभागियों और स्थानीय बिल्डरों तथा डेवलपरों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। उद्घाटन समारोह में, मुख्य इंजीनियर – एम.ई.एस., निदेशक – प्रशिक्षण केन्द्र, एम.एच.ए.डी.ए. और कार्यकारी निदेशक – बी.एम.टी.पी.सी. ने भाग लिया। बी.एम.टी.पी.सी. के अधिकारियों सहित वरिष्ठ व्यवसायविदों ने प्रस्तुतीकरण किए।

14–16 जून, 2006 को नई दिल्ली में “रेट्रोफिटिंग एण्ड रिपेयर फॉर सीसमिक स्ट्रेचनिंग ऑफ बिल्डिंग एण्ड स्ट्रक्चर्स” विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

14–16 जून, 2006 के दौरान, निर्माण भवन, नई दिल्ली के प्रशिक्षण केन्द्र में “रेट्रोफिटिंग एण्ड रिपेयर फॉर सीसमिक स्ट्रेचनिंग ऑफ बिल्डिंग एण्ड स्ट्रक्चर्स” विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में भवनों और इमारतों के भूकम्पीय सुदृढीकरण के लिए रेट्रोफिटिंग और मरम्मत के विभिन्न पहलू कवर किए गए। उन भूगर्भीय-तकनकी पहलुओं पर उचित ध्यान दिया गया, जिनकी आमतौर पर अनदेखी कर दी जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कवर किए गए उप-विषय निम्नलिखित थे:

- परियोजना संबंधी योजना के साधन और भारतीय निर्माण उद्योग में उनका गुणवत्ता पहलू।
- रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता और प्रक्रिया।
- भारत में भूकम्प की असुरक्षितता का परिदृश्य।
- भूकम्प का डिजाइन सिद्धान्त और तत्त्व ज्ञान।
- एम्स और अन्य बिल्डिंगों की केस स्टडीज सम्बन्धी जांच।
- ईटों की बिल्डिंगों का असुरक्षितता आकलन और रेट्रोफिटिंग।
- आर.सी.सी. की बिल्डिंगों का असुरक्षितता आकलन और रेट्रोफिटिंग।
- भूकम्प से क्षतिग्रस्त बिल्डिंगों का मूल्यांकन और रेट्रोफिटिंग।
- बिल्डिंगों की रेट्रोफिटिंग के लिए उन्नत तकनीकें।
- बिल्डिंगों की रेट्रोफिटिंग का लागत प्रभाव।
- भूकम्पीय आंकलन के लिए बिल्डिंगों का सर्वेक्षण।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 47 प्रतिनिधियों, केन्द्रीय और राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभागों/ एजेंसियों, निजी क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों का पंजीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किया गया। प्रशिक्षण कक्ष में प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ व्यावहारिक अनुभव की आवश्यकता और महत्व को स्वीकार करते हुए, बी.एम.टी.पी.सी. द्वारा हाल ही में रेट्रोफिटिंग की गई, दिल्ली नगर निगम के स्कूल की बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग का फील्ड दौरा आयोजित किया गया। मृदा द्रवीकरण संभाव्यता का परीक्षण करने के बारे में प्रतिनिधियों को अवगत कराने के लिए केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान स्टेशन का एक दौरा भी आयोजित किया गया। संकाय सदस्यों की सूची में, बी.एम.टी.पी.सी. के अपने अधिकारियों सहित आई.आई.टी. जैसे अनुसंधान संस्थानों और अन्य व्यावसायिक एजेंसियों के प्रसिद्ध विशेषज्ञ शामिल थे। संयुक्त सचिव (वित्त) ने प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित किए।

22–23 अगस्त, 2006 को नई दिल्ली में “बिल्डिंगों और इमारतों की मरम्मत, अनुरक्षण एवं पुनरुद्धार” विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

22–23 अगस्त, 2006 के दौरान नई दिल्ली में “बिल्डिंगों और इमारतों की मरम्मत, अनुरक्षण एवं पुनरुद्धार” विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में मरम्मत, अनुरक्षण के विभिन्न पहलू और बिल्डिंगों एवं इमारतों के

पुनरुद्धार से संबंधित मुद्दे कवर किए गए, जो इंजीनियरों और आचीटेक्टों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित पहलू कवर किए गए:

- नींव की दरारें – इमारतों के दोषों का परीक्षण, निदान, कारण और मरम्मत।
- रिफ्कोर्समेंट का क्षय
- बिल्डिंग में दरारें और उनकी मरम्मत तकनीकें।
- निर्माण संबंधी रसायन – बिल्डिंगों के अनुरक्षण और मरम्मत में इस्तेमाल।
- अच्छी प्लंबिंग पद्धतियां और प्लंबिंग सेवाओं की मरम्मत।
- बिजली के कार्यों का अनुरक्षण।
- बिल्डिंग के परीक्षण के गैर-विनाशी तरीके।
- भूकम्प द्वारा पहुंचाई गई क्षति – इंटों की बिल्डिंगों की मरम्मत और रेट्रोफिटिंग।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सार्वजनिक निर्माण विभागों/ एजेंसियों और अंडमान आदि जैसे दूर-दराज के क्षेत्रों से आए व्यक्तियों सहित निजी क्षेत्र के 19 प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और उसका लाभ उठाया। संकाय सदस्यों में, बी.एम.टी.पी.सी. के अपने प्रमुख (बी.एम.), डॉ. आर. के. भंडारी के अलावा, अध्यक्ष, आपदा प्रबंधन एवं अल्पीकरण केन्द्र, वेलोर प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रो. बी. भट्टाचार्जी, आई.आई.टी., दिल्ली और इस क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञ शामिल थे।

6 से 8 सितम्बर, 2006, नई दिल्ली में "कंकरीट मेकिंग मेटीरियल्स, मिक्स डिजाइन एण्ड हाई परफोरमेंस कंकरीट" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
परिषद् ने 6 से 8 सितम्बर, 2006 तक, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, लोधी इस्टेट, नई दिल्ली में "कंकरीट मेकिंग मेटीरियल, मिक्स डिजाइन एण्ड हाई परफोरमेंस कंकरीट" विषय पर एक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण उप-विषय कवर किए गए:

- सीमेंट के प्रकार और उनका अनुप्रयोग।
- रसायन अधिमिश्रण।
- एग्रीगेट्स और अधिमिश्रण।
- ताजे और सख्त कंकरीट के गुणधर्म और परीक्षण।
- कंकरीट निर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन।
- भारतीय मानक के अनुसार कंकरीट अधिमिश्रण और स्वीकार्यता मानदंड।
- आई.एस.:456 के अनुसार मजबूती की अपेक्षिता।
- कंकरीट मिक्स डिजाइन पद्धति और उदाहरण।

परिषद् को स्टेकहोल्डरों से अति उत्साहजनक प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ और प्रशिक्षण कार्यक्रम में 40 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उनमें से कुछ विशेष थे – एन.टी.पी.सी., ए.पी. हाउसिंग कॉर्पोरेशन, ड्यू पोन्ट इंडिया, मेकोन, एम.पी. वेयरहाउसिंग, दिल्ली पी.डब्ल्यू.डी. और सी.पी.डब्ल्यू.डी. के प्रतिनिधि। उद्घाटन भाषण डालमिया सीमेंट लिमिटेड के डॉ. के.सी. नारंग द्वारा दिया गया। अन्य संकाय सदस्यों में आई.आई.

टी, दिल्ली के प्रो. बी. भट्टाचार्जी, सी.एस.एम.आर.एस. के संयुक्त निदेशक श्री मुरारी रत्नम, भूतपूर्व महानिदेशक, एन.सी.सी.बी.एम., डॉ. ए.के. मलिक, एन.सी.सी.बी.एम. के भूतपूर्व संयुक्त निदेशक डॉ. एस.सी. मैती और प्रमुख – बी.एम., बी.एम.टी.पी.सी. शामिल थे।

22-23 जनवरी, 2007 नई दिल्ली में "वाटर प्रूफिंग एण्ड डम्प प्रूफिंग मेटीरियल्स एण्ड टेक्नीक्स फॉर बिल्डिंग्स एण्ड स्ट्रक्चर्स" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

22 और 23 जनवरी, 2007 को कोलकाता में, कार्यक्रम सहयोगी – डॉ. फिक्सट ढांचागत पर संरक्षण एवं पुनरुद्धार संस्थान के सहयोग से "वाटर प्रूफिंग एण्ड डैम्प प्रूफिंग मेटीरियल्स एण्ड टेक्नीक्स फॉर बिल्डिंग्स एण्ड स्ट्रक्चर्स" विषय पर एक दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किए गए विषय निम्नलिखित थे:

- वाटर प्रूफिंग से संबंधित कंकरीट प्रौद्योगिकी के मूलभूत सिद्धान्त।
- वाटर प्रूफिंग की अच्छी निर्माण पद्धतियां।
- वाटर प्रूफिंग के सिद्धान्त और प्रक्रिया तंत्र।
- बेसमेंट, स्वीमिंग पूल, भूमिगत मेट्रोज, सुरंगों आदि ग्रेड से नीचे वाटर प्रूफिंग।
- इंजेक्शन ग्राउटिंग, जाइंट फिल्टर्स, इंसुलेशन।
- वाटर प्रूफिंग के मानक।
- डी.पी.सी., दीवारों के ग्रेड से ऊपर वाटर प्रूफिंग।
- बिल्डिंगों में गीले क्षेत्रों की वाटर प्रूफिंग।
- छत की वाटर प्रूफिंग – सिद्धान्त, सामग्रियां, तरीके और प्रभावोत्पादकता।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 20 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिनिधियों ने सी.पी.डब्ल्यू.डी., एन.टी.पी.सी., एन.एच.पी.सी., राज्य के पी.डब्ल्यू.डी., सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड आदि के प्रतिनिधि शामिल थे। संकाय सदस्यों में जबलपुर विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरी विभाग के अध्यक्ष, वाटर प्रूफिंग विशेषज्ञ और प्रमुख (बी.एम.) – बी.एम.टी.पी.सी. शामिल थे।

2. भारतीय निर्माण सामग्री विनिर्माताओं के तकनीकी प्रतिनिधिमंडल के इटली के दौरे का आयोजन

यूनिडो-आई.सी.एस. प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत बी.एम.टी.पी.सी. ने, वैकल्पिक निर्माण सामग्रियों और आवास प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अंतरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन, संयुक्त उद्यम की संभावना का पता लगाने के लिए 13 से 17 नवम्बर, 2006 तक, भारतीय निर्माण सामग्री विनिर्माताओं के तकनीकी प्रतिनिधिमंडल के इटली दौरे का आयोजन किया। प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व 7 औद्योगिक पार्टनरों द्वारा किया गया, जिनमें बी.एम.टी.पी.सी. और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे।

महत्वपूर्ण केन्द्र जो कि दौरे में शामिल थे – एरिया साइंस पार्क, ट्रिस्टे जो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों की सहायता करता है, प्रौद्योगिकी संवर्द्धन उद्यमिता विकास और आई.सी.एस., ट्रिस्टे, पोदोवा प्रान्त, इटली के मेयर, प्रबंध

निदेशक, यूनिडो-आई.सी.एस., ट्रिस्टे, उपाध्यक्ष, चम्बर ऑफ कॉमर्स, पोदोवा, औद्योगिक प्रान्त, इटली जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ, भावी सहयोग की संभावना के लिए बैठक आयोजित की गई। कुछ भारतीय उद्योग पार्टनरों ने प्लास्टिक अवशिष्ट और मलबा रिसाइकिलिंग संयंत्रों को अत्याधुनिक अभिनव पाया और इसे भारत में तुरन्त अपनाने की इच्छा व्यक्त की तथा इस संबंध में बी.एम.टी.पी.सी. के साथ संयुक्त रूप से काम करने की उत्सुकता दिखाई।

इस दौरे के परिणाम के रूप में, भावी सहयोग के लिए निर्माण सामग्री उद्योगों को इटली के एक प्रतिनिधिमंडल के मार्च-अप्रैल, 2007 में भारत में आने की संभावना है।

3. भूटान की शाही सरकार के साथ सहयोग कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना

पिछले वर्ष भूटान में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे के यथावसर, भूटान सरकार ने, भूटान में लागत प्रभावी और अभिनव निर्माण सामग्रियों के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन व उत्पादन केन्द्र (टी.डी.पी.सी.) स्थापित करने में अपनी रुचि दिखाई थी ताकि आवास और निर्माण क्षेत्र की निर्माण सामग्रियों की मांग पूरी की जा सके। बाद में, सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के भूटान के दौरे के दौरान बी.एम.टी.पी.सी. के अधिकारियों ने भूटान का दौरा किया और बी.एम.टी.पी.सी. की तकनीकी सहायता से घेलपोशिंग, जिला मोंगर, भूटान में एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन व उत्पादन केन्द्र स्थापित करने के लिए 15 मई, 2006 को सचिव, शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार और सचिव, निर्माण कार्य एवं मानव अधिवास मंत्रालय, भूटान सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

बी.एम.टी.पी.सी. ने, मानक और गुणवत्ता नियंत्रण प्राधिकरण (एस.क्यू.सी.ए.), निर्माण कार्य एवं मानव अधिवास मंत्रालय, भूटान शाही सरकार के साथ संयुक्त रूप से 16-18 मई, 2006 के दौरान "निर्माण में मानक एवं गुणवत्ता नियंत्रण" विषय पर एक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें भूटान के विभिन्न सरकारी विभागों और निजी संगठनों के 50 से अधिक इंजीनियरों, आर्किटेक्टों और व्यवसायविदों ने भाग लिया। सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में, सचिव, निर्माण कार्य एवं मानव अधिवास, भूटान, कार्यकारी निदेशक, बी.एम.टी.पी.सी., निदेशक-एस.क्यू.सी.ए. और मिशन के उप-मुख्य, भारतीय दूतावास, थिम्पू भूटान ने भाग लिया।

4. भिलाई, छत्तीसगढ़ में अर्ध-कुशल कारीगरों के लिए कुशलता उन्नयन कार्यक्रम

बी.एम.टी.पी.सी. के मार्गदर्शन में, निर्माण विकास अनुसंधान संस्थान, रायपुर (एक गैर-सरकारी संगठन), जो छत्तीसगढ़ आवास बोर्ड के 4 बिल्डिंग सेंटरों का प्रबंधन कर रहा है और उन्हें चला रहा है, के सहयोग से बिल्डिंग सेंटर, भिलाई में अर्ध-कुशल कारीगरों के लिए 7 दिवसीय कुशलता उन्नयन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लक्ष्य समूह "अर्ध-कुशल निर्माण वर्कर्स (राज मिस्ट्री)" का चयन,

प्रशिक्षण स्थान के 50 किलोमीटर के दायरे से किया गया था। कार्यक्रम के दौरान, परम्परागत सामग्रियों और निर्माण प्रौद्योगिकियों के अलावा, वैकल्पिक सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 70 वर्करों ने भाग लिया।

5. विश्व पर्यावास दिवस, 2006 के अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता

विश्व पर्यावास दिवस के अवसर को यादगार बनाने के लिए बी.एम.टी.पी.सी. ने विशेष (विकलांग) बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। तीन विभिन्न श्रेणियों अर्थात् मानसिक रूप से असामान्य, मानसिक रूप से असामान्य और दृष्टिहीन, के अंतर्गत 60 से अधिक बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। सर्वोत्तम पेंटिंगों को नकद पुरस्कार दिए गए और कुमारी शैलजा, माननीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा 3 अक्टूबर, 2006 को विश्व पर्यावास दिवस के समारोह के दौरान, प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाणपत्र वितरित किए गए।

6. बी.एम.टी.पी.सी. में विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का दौरा

दक्षिणी अफ्रीका सरकार के माननीय आवास मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल, 2006 के दौरान बी.एम.टी.पी.सी. का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने बवाना स्थित औद्योगिक वर्करों के आवास निर्माण स्थल का दौरा किया, जहां अभिनव सामग्रियों और निर्माण तकनीकों का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर आवास निर्माण कार्य किया गया है।

प्रतिनिधिमंडल ने, बी.एम.टी.पी.सी. द्वारा विकसित और संवर्धित पर्यावरण-अनुकूल तथा ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों में गहरी रुचि ली।

माननीय निर्माण मंत्री, चीन सरकार ने भी बवाना स्थित, बी.एम.टी.पी.सी. द्वारा समर्थित, औद्योगिक वर्कर्स आवास परियोजना का दौरा किया और निम्न लागत वाले आवास के क्षेत्र में बी.एम.टी.पी.सी. के साथ तकनीकी सहयोग करने में गहरी रुचि दिखाई।

7. ग्रीन हैबीटेट के लिए व्यापक दिशानिर्देश

भारत में 6 प्रकार की जलवायु होती हैं, जो ठंडी और मेघाचादित से लेकर गर्म ऊष्ण और शुष्क की रेंज में होती हैं। परम्परागत बिल्डिंगें इस जलवायु संबंधी भिन्नता के प्रति उस देशी आर्चीटेक्चर की विभिन्न शैलियों के माध्यम से प्रतिक्रिया दर्शाती हैं, जो पूरे देश प्रदर्शित की जाती हैं। दिशानिर्देशों और अनिवार्य उपबंधों के अभाव में, बढ़ते हुए शहरीकरण ने उस, पर्यावास डिजाइन, जिसमें मुख्य लक्ष्यों के रूप में पर्यावरणीय सरोकार और ऊर्जा दक्षता शामिल नहीं है, के प्रति अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य किया है। प्रचलित मानदंडों में इन पर कम ध्यान दिया गया है। इस तथ्य से चिन्ता और बढ़ जाती है कि भारत में ऊर्जा के वाणिज्यिक रूपों की कमी है, चाहे वह प्रदान की जाने वाली विजली के रूप में

हो या अधिक मूल तेल और गैस और यहां तक कि कोयला हो। निर्माण उद्योग द्वारा संसाधनों का उपयोग इस समय अत्यधिक अतर्कसंगत है, क्योंकि डिजाइन संबंधी निर्णय लेने में पहले निम्न लागत हावी रहती है।

निर्माण व्यापार में इस समय, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की अनेक कम्पनियां हैं, जो प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, फंडिंग, डिजाइन, निर्माण और बिल्डिंग कार्य के प्रचालन में अधिक सहयोग के बिना भाग लेती हैं। हालांकि हाल ही में निर्माण संहिताओं से संबंधित ऊर्जा और बिल्डिंग रेटिंग प्रणालियां विकसित करके (जैसे सी.आई.आई. और टी.ई.आर.आई. द्वारा किए गए प्रयास) ऊर्जा चेतना आर्कटेक्चर को प्रोत्साहित करने के कुछ सीमित प्रयास किए गए हैं परन्तु अब तक केवल वाणिज्यिक बिल्डिंगों के विशेष प्रभारों पर ही ध्यान केन्द्रित रहा है।

वास्तव में, इस बात की अत्यधिक आवश्यकता है कि केवल बिल्डिंगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पर्यावास के लिए इस प्रकार के प्रयास किए जाएं।

समग्र उद्देश्य

- ग्रीन हैबीटेट के लिए दिशानिर्देशों (जी.जी.एच.) का समग्र उद्देश्य ऐसी बेहतर या नई पद्धतियों के जरिए प्रत्येक स्टेकहोल्डर के लिए एक साधन के रूप में काम करना होगा, जिन्हें लक्षित स्थायी कार्य-निष्पादन के उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए आवश्यक सहयोग की उच्चतम मात्रा प्राप्त करने और इन लक्ष्यों को साकार रूप देने की दृष्टि से अपनाया जाना चाहिए।
- जी.जी.एच. का उद्देश्य होगा – सरकारी एजेंसी के अधिकारियों और स्टाफ, कार्यान्वयन एजेंसियों और निर्वाचित अधिकारियों, आर्कटेक्टों और इंजीनियरों, ठेकेदारों, निर्माण प्रबंधकों और जनता को निर्देश देना और उनसे इनपुट को सुलभ बनाना।
- जी.जी.एच., मौजूदा मानकों और संहिताओं तथा बिल्डिंग रेटिंग प्रणालियों के साथ संबंध स्थापित करेगा और उनमें सुधार करेगा।

इसके लक्ष्य निम्नलिखित हाँगें:

- जागरूकता उत्पन्न करना और इसलिए विभिन्न स्टेकहोल्डरों के बीच पर्यावास के इष्टतम कार्य-निष्पादन की अपेक्षाएं हैं।
- निम्नलिखित को शामिल करने के लिए स्थायी पर्यावास पद्धतियां प्रोत्साहित करना:
 - कम ऊर्जा और सामग्री खर्च, अवशिष्ट निपटान लागत और उपयोगिता बिलों के जरिए ऊर्जा और संसाधन संरक्षण।
 - बिल्डिंग में रहने वाले व्यक्तियों और पब्लिक आगंतुकों के आराम, स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार, और
 - स्थायी डिजाइन और निर्माण पद्धतियां, जिनके परिणामस्वरूप ऐसे निवेश होंं जिनसे आर्थिक और पर्यावरणीय विवेक हो।
- निम्नलिखित के माध्यम से इन उन्नत पद्धतियों को मुख्यधारा में लाना:

- चुनिन्दा परियोजनाओं पर विशिष्ट हरित पर्यावास रणनीतियों का वृद्धिक इस्तेमाल।
- व्यापक पायलट बिल्डिंग प्रयास; और
- आवास बोर्डों या योजनाओं (जैसे जे.एन.एन.यू.आर.एम.) या अन्य एजेंसियों, जो भी उपयुक्त हों, के माध्यम से इन दिशानिर्देशों को अनिवार्य बनाना।
- पर्यावरणीय और आर्थिक कार्य-निष्पादन लक्ष्यों के इर्द-गिर्द, डिजाइन तथा निर्माण प्रक्रिया में साझेदारियां सृजित करना।
- स्थायी पर्यावास प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के लिए बाजारों का अनुकरण करना।

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 2 नवम्बर, 2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एन-16012/9/2006एच.1 के अंतर्गत, हरित पर्यावास के लिए दिशानिर्देश बनाने हेतु पहले ही एक कार्य दल गठित कर दिया है।

हरित पर्यावास के लिए दिशानिर्देश (जी.जी.एच.) बनाने के लिए संदर्भ शर्तों पर चर्चा करने हेतु कार्य दल की पहली बैठक दिनांक 21 फरवरी, 2007 को आयोजित की गई। कार्य दल में, आई.आई.टी, दिल्ली, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, योजना आयोग, यू.एन.डी.पी. आदि के सदस्य हैं और बी.एम.टी.पी.सी. के कार्यकारी निदेशक संचालन सदस्य हैं। सभी सदस्यों की सर्वसम्मत राय थी कि हरित पर्यावास के लिए व्यापक दिशानिर्देशों की आवश्यकता है। यह भी सुझाव दिया गया कि ग्रामीण और शहरी आवास, दोनों की ही समस्याएं हल किए जाने की आवश्यकता है। बाद में, हरित पर्यावास के लिए दिशानिर्देशों की रूपात्मकताएं निर्धारित करने के लिए प्रमुख तकनीकी सदस्यों के कार्य दल की एक बैठक भी हुई।

8. 14–27 नवम्बर, 2006 के दौरान भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2006, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भाग लेना

बी.एम.टी.पी.सी. ने, 14 से 27 नवम्बर, 2006 तक भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आई आई एफ टी) के दौरान हुड़को बिल्डटैक और टैकमार्ट पवेलियन में भाग लिया। बिल्डटैक और टैकमार्ट में बी.एम.टी.पी.सी. के स्टाल ने बड़ी संख्या में व्यवसायविदों, अति विशिष्ट व्यक्तियों, विदेशी प्रतिनिधिमंडलों और आम जनता को आकर्षित किया जिन्होंने परिषद् द्वारा प्रोन्नत की जा रही विभिन्न अभिनव निर्माण सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों में रुचि ली। पनामा, श्रीलंका, नाइजीरिया, दुबई, वेनेजुएला आदि देशों के अनेक प्रतिनिधिमंडलों ने बी.एम.टी.पी.सी. के स्टाल का दौरा किया।

9. शहरी विकास पर बनी स्थायी संसदीय समिति का दौरा

शहरी विकास पर बनी स्थायी संसदीय समिति ने मई, 2006 के अंतिम सप्ताह और जून, 2006 के पहले सप्ताह के दौरान लेह और श्रीनगर का तत्काल अध्ययन दौरा किया। स्थायी संसदीय समिति ने, इनहोंने स्पीटेबल तराई में हरी सज्जियां उगाने के लिए लेह में आई.टी.बी.पी. के लिए बी.एम.टी.पी.सी. द्वारा निर्मित ग्रीन हाउस परियोजना का दौरा किया। समिति ने बी.एम.टी.पी.सी. की परियोजना की अत्यधिक सराहना की और यह इच्छा भी व्यक्त की कि पूरे राज्य में इन्हें दोहराया जाए। राज्य सरकार, हुड़को, बी.एम.टी.पी.सी., सी.पी.डब्ल्यू.डी. आदि के अधिकारियों के साथ श्रीनगर में की गई अनौपचारिक चर्चा के दौरान समिति ने राज्य सरकार को सलाह दी कि वह, लागत प्रभावी आपदा प्रतिरोधी निर्माण और पूरे राज्य में ग्रीन हाउसों के निर्माण की पद्धति अपनाने के लिए बी.एम.टी.पी.सी. की सहायता ले।

10. संसदीय राजभाषा समिति की उप-समिति का दौरा

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने 15 सितम्बर, 2006 को बी.एम.टी.पी.सी. में सरकारी कार्य में राजभाषा के इस्तेमाल की समीक्षा की। समिति के सदस्य इस संबंध में बी.एम.टी.पी.सी. द्वारा की गई प्रगति से संतुष्ट थे। परिषद् के कार्य की समीक्षा करते समय, समिति ने सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ पहल किए जाने की आवश्यकता है।

VI प्रौद्योगिकी विकास, प्रसार और हस्तांतरण

1. नीडल्ड फैल्ट प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके प्लान्ट फाइबर आधारित मिश्रणों से लकड़ी के विकल्प विकसित करना

पिछले वर्ष परिषद् ने, नीडल्ड फैल्ट प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके प्लान्ट फाइबर आधारित मिश्रणों से लकड़ी का विकल्प विकसित करने के लिए एक परियोजना आरम्भ की थी। विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए ग्लास फाइबर रीइनफोर्स्ड ग्लासटिक्स और लकड़ी आधारित उत्पादों को प्रतिस्थापित करने के लिए आवश्यक विशिष्ट शक्ति के गुणों वाले मिश्रण बनाने के लिए पोलीमर में रीइन्फोर्समेंट के रूप में जूट, साइसल, कॉयर जैसे प्लान्ट फाइबरों का इस्तेमाल किया गया है। तथापि, पोलीमर की ऊंची कीमत होने के कारण प्लान्ट फाइबर मिश्रण (में फाइबर का अंश अधिक से पी.एफ.सी.) अधिक होना चाहिए ताकि उसे लकड़ी आधारित सामग्रियों के साथ आर्थिक रूप से प्रतियोगितात्मक बनाया जा सके।

नीडल फैल्ट प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके पी.एफ.सी. का निर्माण अब एक नया विकास है, इसलिए प्रक्रिया और उत्पादों के वाणिज्यिकीकरण के लिए उत्पादों की बाजार सम्भाव्यता और प्रक्रिया की टेक्नो-इक्नोमिकल व्यवहार्यता के बारे में उद्यमियों का विश्वास प्राप्त करने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी पैकेज, बाजार सर्वेक्षण के नमूने प्रक्रिया का प्रदर्शन और तकनीकी कार्मिकों का प्रशिक्षण उपलब्ध कराके प्रक्रिया तथा उत्पादों के वाणिज्यिकीकरण को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि

से एक बड़े संयंत्र की सुविधा सृजित करना इस परियोजना का उद्देश्य है। चूंकि यह प्रक्रिया सभी प्लांट फाइबरों पर लागू होती है, इसलिए बड़े संयंत्र के लम्बे समय तक बने रहने की गुणाइश है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य कम्पोजिट प्रोसेसिंग में देशज नीडल फैल्टिंग मशीन को शामिल करते हुए एक प्रदर्शन संयंत्र स्थापित करना, और नारियल जटा-पी.एफ. और साइसल-पी एफ मिश्रणों के लिए प्रोसेस फ्लो शीट, उत्पाद विनिर्देशन ओर तकनीकी – आर्थिक डाटा सृजित करना थे।

वाणिज्यिक उत्पादन के लिए प्रक्रिया की तकनीकी जानकारी और नारियल जटा तथा साइसल फाइबर मिश्रण पेनलिंग सामग्रियों के लिए उत्पाद विनिर्देशन का विकास कर लिया गया है और यह परीक्षण के अधीन है।

2. चावल की भूसी से रिएक्टिव सिलिका का उत्पादन करने के लिए प्रदर्शन संयंत्र की स्थापना

परियोजना के चरण ॥ के कार्यकलापों का उद्देश्य निरंतर आधार पर चावल की भूसी/आंशिक रूप से जलाई गई चावल की भूसी से रिएक्टिव सिलिका के उत्पादन के लिए माइक्रो प्लांट टेस्ट करना और प्रक्रिया को वाणिज्यिक स्तर पर ले जाना है। चरण । के दौरान प्रयोगशाला में पहले से सृजित आंकड़ों को मौजूदा कार्य का आधार माना गया। जिन कार्यकलापों की योजना बनाई गई है, वह हैं – चावल की भूसी/आंशिक रूप से जलाई गई भूसी को साफ करना, माइक्रो-पायलट रोटरी किल्न में राख डालना, ठंडा करना, पीसना, औद्योगिक अनुप्रयोग परीक्षण और प्रोसेस स्केल अप।

परियोजना के चरण ॥ के मुख्य उद्देश्य साफ करने, राख डालने, ठंडा करने और पीसने के लिए माइक्रो पायलेट स्केल परे प्रयोग करना, आंकड़ों का सूजन, औद्योगिक अनुप्रयोग परीक्षण के लिए रिएक्टिव सीलिका के लगभग 100 किलोग्राम का थोक उत्पादन, प्रोसेस स्केल अप और उपयुक्त प्लूरडाइज्ड बेड रिएक्टर में प्रयोग करना थे।

उच्च कार्य-निष्पादन कंकरीट में अनुप्रयोग की संभावना वाले 10 कि.ग्रा. रिएक्टिव सिलिका का उत्पादन किया गया। इस चावल की भूसी के औद्योगिक अनुप्रयोग परीक्षण हेतु स्ट्रॉक्चरल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, चेन्नई और केरल हाइवे अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम से अनुरोध किया गया और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर, परीक्षण के लिए एस.ई.आर.सी., चेन्नई को चुना गया। कोची, केरल में स्थित राइस मिल्स ऑनर्स कन्सोर्टियम ने, अपनी भूसी का मूल्य वर्द्धित उत्पाद में रूपांतरित करने के लिए इस प्रौद्योगिकी में रुचि दिखाई है।

3. दो-मंजिले भवनों के निर्माण के लिए बम्बू हाउसिंग प्रणाली प्रौद्योगिकी का विकास

इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य थे – बांस से दो मंजिले मकानों का एक आर्चिटैक्चरल डिजाइन तैयार करना, दो मंजिले मकानों का निर्माण करने के लिए

बांस से जोड़ने की प्रणाली सहित विभिन्न हाउसिंग घटकों का डिजाइन तैयार करना और उनका विकास करना तथा घटकों से दो मंजिले मकानों के निर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना।

दो मंजिले भवनों के निर्माण के लिए बम्बू हाउसिंग प्रणाली की प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया गया है और इमारत के प्रोटोटाइप का निर्माण बंगलौर में किया जा रहा है।

4. बांस चटाई की नालीदार चादरों से छत बनाने के लिए बम्बू मैट रिज कैप का विकास

परिषद् ने पहले बम्बू मैट कोर्लगेटड शीट (बी.एम.सी.एस.) के विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया था और उसका वाणिज्यिकरण किया था। इस समय मेघालय में इस प्रकार की एक यूनिट बी.एम.सी.एस. का विनिर्माण कर रही है। चूंकि बी.एम.सी.एस. का इस्तेमाल रुफिंग सामग्री के रूप में हाउसिंग कार्यकलापों में शुरू हो चुका है, इसलिए यह बहुत आवश्यक हो गया है कि बी.एम.सी.एस. से बनाई गई छत के ऊपरी भाग/कोनों को कवर करने के लिए रिज कैप का विकास किया जाए।

इस परियोजना के उद्देश्य थे – बम्बू मैट से बनाई जाने वाली रिज कैप के आकार और उपयुक्त प्रोफाइल का डिजाइन तैयार करना और उसका विकास करना, उपयुक्त डाइयों का फैब्रीकेशन जिसे प्लेटन आकार 1450 एम एमx650 एमएम के हाइड्रोलिक हॉट प्रेस में लगाया जाएगा, रिज कैप बनाने के लिए ट्रायल रन और यदि आवश्यक हो तो सुधार तथा संशोधन करना, और परीक्षण तथा कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन।

रुफिंग के लिए बम्बू मैट रिज कैप के विनिर्माण की प्रौद्योगिकी, आई.पी.आई.आर.टी.आई., बंगलौर में विकसित कर ली गई है। उत्पाद का परीक्षण किया जा रहा है।

5. बांस आधारित मिश्रणों का इस्तेमाल करके प्रिफेब्रीकेटड मोड्युलर घरों का विकास

यह परियोजना, प्रिफेब्रीकेटड घरों में बांस मिश्रित निर्माण सामग्रियों का अनुप्रयोग विकसित करने और परम्परागत सामग्रियों की तुलना में उनके लाभों के लिए आरम्भ की गई थी। इस प्रकार के घरों का निर्माण, आपदा के बाद की राहत के लिए तुरन्त और दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए, बहुत तेजी से किया जा सकता है।

संलग्न बाथ और रसोई वाले प्रिफेब डबल वाल्ड बम्बू कम्पोजिट घर का डिजाइन तैयार कर लिया गया है। प्रोटोटाइप के निर्माण का कार्य बंगलौर में अग्रगामी चरण में है।

6. एच.पी.एल. में स्थायी उड़न राख ईंट उत्पादन व प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केन्द्र की स्थापना

हिन्दुस्तान प्रिफेब लिमिटेड (एच.पी.एल.) में ब्रिक और ब्लॉक मैकिंग मशीन और पैन मिक्सर की स्थापना और प्रदायगी के साथ एच.पी.एल. में बी.एम.टी.पी.सी. द्वारा

समर्थित पलाई ऐश ब्रिक उत्पादन व प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केन्द्र की स्थापना कर दी गई है। इस समय विभिन्न उत्पादन मानदंडों का इष्टतम उपयोग किया जा रहा है और पलाई ऐश ईंटों का परीक्षण उत्पादन चल रहा है।

7. राजकोषीय प्रोत्साहन

कृषि-औद्योगिक अवशिष्टों पर आधारित लागत-प्रभावी, वातावरण-अनुकूल और ऊर्जा दक्ष निर्माण सामग्रियों के उत्पादन के लिए निवेश के वातावरण में सुधार करने की दृष्टि से राजस्व विभाग, भारत सरकार को, कुछ मदों पर उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में छूट देने जैसे राजकोषीय प्रोत्साहन देने के लिए आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के माध्यम से सिफारिशों की गई। बी.एम.टी.पी.सी. की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2006-07 के केन्द्रीय बजट में निम्नलिखित उत्पाद और सीमाशुल्क रियायतें/छूट प्रदान की गई हैं। इन छूटों से, भारत में और विदेशों में विकसित की गई अभिनव निर्माण सामग्रियों/प्रौद्योगिकियों के विस्तृत वाणिज्यिकरण में बहुत सहायता मिली है:

- ऐसे सामान जिनमें भार के हिसाब से 25 प्रतिशत रेड मड या प्रैस मड या ब्लास्ट फरनस स्लग का या सबका इस्तेमाल किया जाता है।
- ऐसे सामान जिनमें भार के हिसाब से कम से कम 25 प्रतिशत तक उड़न राख या फास्कोजिप्सम या दोनों का इस्तेमाल किया जाता है।
- तैयार मिश्रित कंकरीट
- पकी हुई ईंटों के अलावा मिट्टी की ईंटें
- रेत-चूना ईंटें
- छत की टाइलें
- आई एस 3367 के अनुसार पकी हुई टाइल्स
- निर्माण स्थल पर पर तैयार की गई वस्तुएं जो वहाँ उपयोग में लाई जाएं
- सीमेंट बॉण्डेड पार्टिकल बोर्ड
- जूट पार्टिकल बोर्ड
- धान भूसी बोर्ड
- ग्लास रेशे से प्रबलित जिप्सम बोर्ड
- पटसन रेशा बोर्ड
- गने की खोई से बोर्ड

केन्द्रीय सरकार के स्तर पर विशेष रूप से प्रदान किए गए उपरोक्त प्रोत्साहनों ने राष्ट्रीय स्तर पर उद्यमियों और निवेशकों के बीच एक विश्वास उत्पन्न किया है। इसके अलावा, इससे विभिन्न राज्यों में नई सामग्रियों की उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए उच्चतर निवेश को बढ़ावा दिया गया है।

VII जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)

1. जे.एन.एन.यू.आर.एम. के कार्यान्वयन में बी.एम.टी.पी.सी. की भूमिका

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार "बेसिक सर्विसेज टु अरबन पूअर" (बी.एस.यू.पी.), जो हाल ही में आरंभ किए गए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) का उप-घटक है, को कार्यान्वित कर रहा है।

डी.पी.आर. का मूल्यांकन

परिषद् को, मंत्रालय द्वारा, पहचान किए गए मिशन शहरों से बी.एस.यू.पी. के अंतर्गत प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के मूल्यांकन के लिए एक मूल्यांकन एजेंसी के रूप में नामजद किया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2007 को यथास्थिति, बी.एम.टी.पी.सी. ने मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, चंडीगढ़, गुजरात, कर्नाटक, नागालैंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्यों से प्राप्त 3325 करोड़ रुपये मूल्य की 46 डी.पी.आर. का मूल्यांकन किया है। इन्हें केन्द्रीय स्वीकृति और मानीटरिंग समिति के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया है और इन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। इन परियोजनाओं का राज्य-वार विभाजन निम्नलिखित है:

राज्य	परियोजनाओं की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	9
गुजरात	10
कर्नाटक	3
मध्य प्रदेश	18
चंडीगढ़	2
नागालैंड	1
हिमाचल प्रदेश	1
राजस्थान	2
कुल	46

बी.एम.टी.पी.सी., विभिन्न कार्यशालाओं, बैठकों आदि के माध्यम से डी.पी.आर. तैयार करने और उनमें संशोधन करने में म्युनिसिपल निकायों और राज्य नोडल एजेंसियों की भी सहायता कर रही है। परिषद् को, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्य सरकारों से भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि वह उनके राज्यों के लिए डी.पी.आर. तैयार करे।

परिषद् को उन राज्यों में परियोजनाओं की मानीटरिंग के लिए मानीटरिंग एजेंसी के रूप में नामजद किया जा रहा है, जहां परिषद् द्वारा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। इन परियोजनाओं के प्रभावी मानीटरन के लिए, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के परामर्श से एक विस्तृत मानीटरिंग प्रक्रियात्र तैयार किया जा रहा है।

क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन

परिषद् ने बी.एस.यू.पी. और आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं के लिए डी.पी.आर. तैयार करने में म्युनिसिपल पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। निम्नलिखित कार्यक्रमों में प्रस्तुतीकरण दिए गए:

- हैदराबाद में 7 जुलाई, 2006
- नई दिल्ली में 13–14 जुलाई, 2006
- पुणे में 20–22 जुलाई, 2006
- कोलकाता में 31 जलाई, 2006
- शिलांग में 18 सितम्बर, 2006
- नई दिल्ली में 27 अक्टूबर, 2006
- भुवनेश्वर में 28 अक्टूबर, 2006
- पुणे में 13 नवम्बर, 2006
- बंगलौर में 5–6 जनवरी, 2007
- पटना में 11–12 जनवरी, 2007
- कोलाकता में 15–16 जनवरी, 2007
- पोर्ट ब्लेयर में 17–18 जनवरी, 2007
- चंडीगढ़ में 23 जनवरी, 2007।

बी.एम.टी.पी.सी. ने, 16–17 मार्च, 2007 को आयोजित की गई “जे.एन.एन.यू.आर.एम.: डवलपिंग इनकलुसिव सिटीज़” विषय पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक के संबंध में सभी प्रबंध किए। इस कार्यक्रम का आयोजन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा किया गया और इसे हुड्को, बी.एम.टी.पी.सी., ए.आई.आई.एल.एस.जी., यशदा और सी.जी.जी., हैदराबाद द्वारा प्रायोजित किया गया। 16 मार्च, 2007 को हुई विशेषज्ञ समूह की बैठक का उद्घाटन सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा किया गया और मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन 17 मार्च, 2007 को माननीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री द्वारा किया गया। माननीय शहरी विकास मंत्री ने 17 मार्च, 2007 को समापन भाषण दिया। सम्मेलन में 259 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें राज्य सरकारों के मंत्री, मेयर, म्युनिसिपल निकायों के अध्यक्ष, कमीशनर, गैर-सरकारी संगठन के और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अन्य पदाधिकारी शामिल थे।

VIII वर्ष के दौरान कुछ परियोजनाओं / अध्ययनों की प्रमुख विशेषताएं

1. भूगर्भीय-जलवायु और भौगोलिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए निर्धन लोगों के लिए किफायती घर बनाने हेतु टेम्पलेट्स तैयार करना

1.00 लाख रुपए में निर्धन लोगों के लिए किफायती घर बनाने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 12.2.2007 को संयुक्त सचिव (आवास) की अध्यक्षता में आवास एवं

शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बी.एम.टी.पी.सी., तराइ, अर्थात् पवर्तीय क्षेत्रों, मैदानी, भूकम्प संभावित क्षेत्रों आदि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 4-5 टेम्पलेट्स तैयार करेगी और इन घरों का बिल्ड अप ऐरिया 25 वर्गमीटर होगा तथा लागत लगभग 1.00 लाख रुपये होगी। घरों की लागत कम करने की दृष्टि से यह आवश्यक माना गया कि नीति स्तर पर हस्तक्षेप जैसे राजकोषीय रियायतें प्रदान करना, विनिर्माताओं द्वारा प्रत्यक्ष आपूर्ति आदि की संभावनाओं का पता लगाया जाए। इसके बाद इन टेम्पलेट्स को राज्य सरकारों और अन्य स्टेकहोल्डरों में परिचालित किया जाएगा ताकि उनके विचार और टिप्पणियां प्राप्त की जा सकें और बाद में सांचों के अंतिम और स्वीकार्य रूपों पर निर्णय लेने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श किया जा सके।

कार्य का दायरा

- भिन्न-भिन्न भूगर्भीय-जलवायु जोनों के लिए आंकड़ों का चयन और संयोजन।
 - उपरोक्त जोन आवश्यकता के आधार पर, गृह योजना, ब्लॉक योजना और पार्ट क्लस्टर योजना तैयार करना।
 - विशिष्ट एलीवेशन, सेक्षन, प्लंबिंग, सेनीटेशन और आंतरिक इलेक्ट्रीफिकेशन।
 - विशिष्ट नींव और रुफ स्ट्रक्चरल योजनाओं के साथ वेसिक स्ट्रक्चरल नक्शे तैयार करना।
 - लागत कम करने के लिए वैकल्पि सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों का चयन।
 - दरों की राज्य अनुसूची के आधार पर विभिन्न भूगर्भीय-जलवायु के लिए विस्तृत आकलन तैयार करना।
 - भिन्न-भिन्न भूकंप जोनों और आवास योग्य इकाई के लिए जी+2 और जी+3 हेतु मिट्टी की भिन्न-भिन्न धारण क्षमता ($10\text{टी}/\text{एम}^2$, $6\text{टी}/\text{एम}^2$ ब्लॉक कॉटन मिट्टी) के मेट्रिक्स के लिए लागत की तुलना तैयार करना।
 - भिन्न-भिन्न भूगर्भीय-जलवायु जोनों के लिए प्रौद्योगिकी विकल्प के मेट्रिक्स तैयार करना और यह दर्शाना कि एक लाख रुपए के घर में क्या आता है और इसके ऊपर की लागत के घर में क्या आता है।
- टेम्पलेट्स को तैयार करने की परियोजना आरम्भ कर दी गई है।

2. बांस की चटाई की नालीदार शीटों से रुफिंग के लिए बम्बू मैट रिज कैप के उत्पादन का औद्योगिक उन्नयन करने हेतु परियोजना का प्रस्ताव

परिषद्, बांस की प्रोसेसिंग के लिए बम्बू मैट उत्पादन केन्द्रों की स्थापना करके, पूर्वात्तर क्षेत्र और बांस की पैदावार वाले अन्य क्षेत्रों में बांस आधारित प्रौद्योगिकियों का विकास करने और इन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के काम में सक्रिय रूप से लगी हुई है जिससे बांस आधारित उत्पादों के वाणिज्यिक उत्पादन, प्रदर्शन गृहों के निर्माण आदि को प्रोत्साहन मिल रहा है।

बी.एम.टी.पी.सी. ने मिजोरम और त्रिपुरा में बांस आधारित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके दोनों राज्यों में 10-10 प्रदर्शन इमारतों का निर्माण आरम्भ किया है और वर्षा के मौसम के दौरान रिसाव से बचने के लिए रुफिंग के ऊपरी भाग पर रिज कैप लगाने की समस्या का सामना किया है। दो एमएम मोटे बम्बू मैट बोर्ड के फ्लैट बोर्डों के इस्तेमाल के तरीके से बचा जाना चाहिए, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण कुछ समय बाद इसमें छेद हो जाते हैं। आई.पी.आई.आर.टी.आई., बंगलौर के साथ निकट सहयोग से बी.एम.टी.पी.सी. रुफिंग के लिए उपयुक्त निर्मित आकार की डाई वाली बम्बू मैट रिज कैप के उत्पादन के लिए बड़े संयंत्र में प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है।

जैसे-जैसे दिन प्रतिदिन बी.एम.सी.एस. का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उपयुक्त रिज कैप की मांग में भी वृद्धि हो रही है। प्रयोगशाला के स्तर पर रिज कैप के विकास की सफलता के साथ इस बात की आवश्यकता महसूस की गई है कि वाणिज्यिकरण के लिए प्रक्रिया के अप्स्केलिंग के लिए आगे काम किया जाए। इस संबंध में यह बहुत आवश्यक है कि बम्बू मैट रिज कैप के विनिर्माण के लिए 650 एमएमX2000 एमएम और इससे बड़े आकार की डाइयां फेब्रीकेट करके इस परियोजना का औद्योगिक अप्स्केलिंग किया जाए।

उपरोक्त बात को ध्यान में रखते हुए, रिज कैप के उत्पादन और इसके परीक्षण तथा कार्य-निष्ठादान मूल्यांकन में मौजूदा हाइड्रोलिक होट प्रैस और ट्रायल रन में संस्थायन के लिए 650 एमएमX2000 एमएम के आकार की डाइयों के दो सैटों के फेब्रीकेशन के लिए एक परियोजना आरम्भ की गई है।

बम्बू मैटों से बने रिज कैप से बम्बू बोर्ड छत के कोनों को कवर करना, बी.एम.सी.एस. के लिए अनुकूल और उपयुक्त होना आसान और सुविधाजनक हो जाएगा।

3. फ्लैटन्ड बम्बू मिश्रणों और लेमीनेटड बम्बू लम्बर उत्पादों का विकास

परिषद् ने फ्लैटन्ड बम्बू मिश्रणों और लेमीनेटड बम्बू लम्बर उत्पादों के विकास के लिए एक परियोजना आरम्भ की है। स्ट्रक्चरल अनुप्रयोगों के लिए फ्लैटन्ड बम्बू बोर्ड, मौजूदा बम्बू मैट बोर्डों और बम्बू मैट विनिअर मिश्रणों का विकल्प होगा। स्ट्रक्चरल उद्देश्यों के लिए अब इस्तेमाल किए जा रहे उच्च श्रेणी के टिम्बर के लिए, लम्बर को एक विकल्प के रूप में स्थान दिया जाएगा। इसके अलावा, जहां कहीं लेमीनेटड विनिअर लम्बरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें बम्बू लम्बर द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। बम्बू लम्बर, स्ट्रक्चरल उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले क्लास। और विनिअर लम्बरों की तुलना में सस्ता होगा।

उद्देश्य

- प्रोसेसिंग मानदंडों, अर्थात् फ्लैटन्ड बम्बू बनाने के लिए मशीनरी, संरक्षण और शोषक मानदंडों का इष्टतम उपयोग।
- बांडिंग फ्लैटन्ड बम्बू और बम्बू मैटों के लिए उपयुक्त एड्हेसिव प्रणाली का

विकास।

- फ्लैटन्ड बम्बू गोर्डों के विनिर्माण के लिए प्रक्रिया मानदंडों का मानकीकरण।
- लेमीनेटड बम्बू लम्बर के विनिर्माण के लिए प्रक्रिया मानदंडों का मानकीकरण।
- शक्ति संबंधी गुणधर्मों का मूल्यांकन।
- एक हाउसिंग कम्पोनेंट के रूप में विकसित उत्पादों की उपयुक्तता पर अध्ययन।

यह परियोजना, आई.पी.आई.आर.टी.आई., बंगलौर के साथ आरम्भ की जा रही है।

4. ग्रेनाइट उद्योग के अपशिष्ट से भवन अवयवों का विकास

परिषद् ने ग्रेनाइट उद्योग से निकले ग्रेनाइट के मलबे से बिल्डिंग कम्पोनेंटों के विकास के लिए एक परियोजना आरम्भ की है।

परियोजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- ग्रेनाइट के मलबे का लक्षण-वर्णन।
- ग्रेनाइट के मलबे से ब्रिक्स/पेवमेन्ट के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए मानदंड तैयार करना।
- प्रौद्योगिकी अंतरण।

यह परियोजना, आन्ध्र प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास एवं संवर्द्धन केन्द्र, हैदराबाद के निकट सहयोग से आरम्भ की जा रही है।

5. छत्तीसगढ़ और मेघालय में बांसप्रदर्शन इमारतों का निर्माण

परिषद् ने, बांस आधारित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके छत्तीसगढ़ और मेघालय में प्रदर्शन गृहों के निर्माण का काम आरम्भ किया है। आवास और निर्माण में बांस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बांस आधारित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके, प्रदर्शन इमारतों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है। परिषद् ने मिजोरम और त्रिपुरा में प्रदर्शन इमारतें बनाई हैं और इससे इस क्षेत्र में निर्माण सामग्री के रूप में बांस के इस्तेमाल के बारे में काफी जागरूकता उत्पन्न हुई है।

दोनों क्षेत्रों में आवास और भवन निर्माण में बांस आधारित प्रौद्योगिकी के संवर्द्धन को ध्यान में रखते हुए, परिषद् ने निम्नलिखित प्रदर्शन इमारतों का निर्माण आरम्भ किया है:

- i. टाइप I आवास - कुल क्षेत्रफल 26.11 वर्ग मीटर
- ii. टाइप II आवास - कुल क्षेत्रफल 52.83 वर्ग मीटर
- iii. पिकनिक हट - कुल क्षेत्रफल 54.35 वर्ग मीटर
- iv. वाह्य रोगी विभाग भवन - कुल क्षेत्रफल 23.07 वर्ग मीटर

प्रदर्शन इमारतों के निर्माण के लिए नक्शे और आकलन तैयार कर लिए गए हैं। सभी अवसंरचनाओं सहित इन प्रदर्शन इमारतों को बनाने के लिए, राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराएगी।

6. मार्बल के मलबे/ मार्बल के चूरे के निपटान के पर्यावरण संबंधी प्रभावों और कंकरीट में इसके इस्तेमाल पर जांचों का अध्ययन

परिषद् ने, मार्बल के मलबे/ मार्बल के चूरे के निपटान के पर्यावरण संबंधी प्रभावों और मार्बल उद्योग के अवशिष्ट के लाभप्रद उपयोग के लिए कंकरीट में इसके इस्तेमाल पर जांचों का अध्ययन आरम्भ किया है।

प्रस्तावित अनुसंधान अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मार्बल अवशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न विकल्पों के पर्यावरणीय लागत लाभ का आकलन करना और मार्बल के मलबे तथा अवशिष्ट मार्बल ब्लॉकों के पर्यावरणीय और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य उपयोग का सुझाव देना है।

प्रस्तावित अनुसंधान के एक भाग के रूप में, निम्नलिखित कार्यकलापों के पर्यावरणीय लागत लाभ विश्लेषण पर विचार किया गया है:

- मलबे से पानी को अलग करने के लिए फिल्टर प्रैस की स्थापना करना और इससे मलबे की परिवहन लागत को कम करना।
- मार्बल के मलबे का इस्तेमाल करके निर्माण सामग्री का उत्पादन करना।
- सड़क निर्माण और बड़े कंकरीट कार्य में मार्बल के मलबे का इस्तेमाल।
- मार्बल के मलबे और अवशिष्ट ब्लॉकों से बना उत्पाद।

इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप आरम्भ किए जाएंगे:

- अभिनव प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन, वैधीकरण और उपलब्ध लागत प्रभावी विकल्पों पर सलाह।
- विभिन्न निर्माण सामग्रियों के लिए स्थान विशिष्ट व्यवहार्यता रिपोर्ट और मांग आकलन रिपोर्ट।
- नई और पर्यावरण-अनुकूल मानकीकृत सामग्रियों का विकास।

प्रवाह में वृद्धि करने के लिए आर्बल अवशिष्ट का उपयोग कंकरीट में किया जा सकता है। तथापि, पाउडर के पार्टीकल आकार, एक स्थायी तरीके से उपलब्ध होने चाहिए। इसलिए, इस अनुसंधान में निम्नलिखित शामिल हैं:

- कंकरीट में मार्बल के मलबे/ पाउडर की व्यवहार्यता और प्रवाहक्षमता और वियोजन प्रतिरोधिता पर इसके प्रभाव का अध्ययन।
- पार्टीकल के आकार और कंकरीट पर्यावरण से संबंधित इसकी अभिक्रियाशीलता का अध्ययन।

यह परियोजना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से आरम्भ की जा रही है।

7. निर्माण केन्द्रों के प्रौद्योगिकीय आधार का सूदृढ़ीकरण

प्रौद्योगिकी प्रदर्शन व उत्पादन इकाइयों/ निर्माण केन्द्रों का सूदृढ़ीकरण, पिछले वर्षों में बी.एम.टी.पी.सी. का एक प्रमुख कार्यकलाप रहा है, जिसके अंतर्गत लागत प्रभावी निर्माण सामग्रियों और पुर्जों के उत्पादन के लिए भशीनें उपलब्ध कराने के रूप में

सहायता प्रदान करने के माध्यम से अनेक इकाइयों/ केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया गया है। पिछले सफल रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2006–07 के दौरान और अधिक टी.डी.पी.सी./ निर्माण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण करने की अपेक्षा की गई थी और इसे कार्य-योजना में शामिल किया गया था।

इस वर्ष के दौरान, परिषद् ने अपने निर्माण केन्द्रों के माध्यम से प्रिकास्ट बिल्डिंग कम्पोनेंट्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मशीनरीज उपलब्ध करा कर रायपुर में छत्तीसगढ़ आवास बोर्ड के स्वामित्व वाले निर्माण केन्द्र और उत्तराखण्ड निर्माण केन्द्र, श्रीनगर, गढ़वाल के उत्पादन आधार को सुदृढ़ बनाया है।

8. लागत प्रभावी आवास प्रौद्योगिकियों का प्रचार करने और बड़े पैमाने पर जनता में रुचि उत्पन्न करने के लिए वीडियो फिल्म बनाना

परिषद् ने, स्लम निवासियों के लिए योजना के अंतर्गत लगगारे, बंगलौर में 252 आवास इकाइयों का निर्माण करके लागत प्रभावी, ऊर्जा दक्ष और पर्यावरण-अनुकूल निर्माण सामग्रियों और निर्माण प्रौद्योगिकियों के फील्ड स्तरीय अनुप्रयोग को दर्शाने वाली एक प्रदर्शन परियोजना सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इस परियोजना का कार्यान्वयन “वाल्मीकी अन्वेषक आवास योजना” (वैम्बे, जो आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई एक पहल थी) के अंतर्गत किया गया और कुमारी शैलजा, माननीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार ने 10 फरवरी, 2005 को परदे का अनावरण किया और सुपुर्दगी समारोह का उद्घाटन किया।

परिषद्, निम्नलिखित स्थानों पर इसी प्रकार की 5 और प्रदर्शन परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है:

- नागपुर (महाराष्ट्र)
- देहरादून (उत्तरांचल)
- बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
- त्रिचि (तमिलनाडु)
- कुडाळु (कर्नाटक)

परिषद् ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों की 10–12 मिनट की एक वीडियो फिल्म बनाने की पहल की है, जिसमें बी.एम.टी.पी.सी. द्वारा कार्यान्वित की जा रही उपरोक्त प्रदर्शन परियोजनाएं दर्शायी गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर जनता की रुचि उत्पन्न करने और परिषद् की अच्छी समझबूझ को बढ़ावा देने की दृष्टि से अत्यधिक रचनात्मक और सुरुचिपूर्ण ढंग से अभिनव, लागत प्रभावी, ऊर्जा दक्ष और पर्यावरण-अनुकूल निर्माण सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग को कवर किया गया है। इस फिल्म का इस्तेमाल, विभिन्न प्रदर्शनियों/ व्यापार मेलों, सार्वजनिक समारोहों और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रोड शो में किया जाएगा।

9. वायान्दु केरल में सामुदायिक बांस चटाई बुनाई सुविधा स्थापित करना

परिषद्, केरल राज्य बांस निगम (के.एस.बी.सी.), केरल सरकार का उपक्रम, अर्नाकुलम, केरल के सहयोग से वेयान्दु, जो केरल राज्य में एक पिछड़ा और जनजातीय जिला है, में एक सामुदायिक बांस चटाई बुनाई सुविधा स्थापित करने के लिए एक परियोजना आरम्भ कर रही है।

केरल राज्य बांस निगम के कार्यकलाप हैं: बांस सरकण्डों, बेत और इंख पर आधारित उद्योगों का विकास करना और उन्हें बढ़ावा देना; उपरोक्त उत्पादों का विनिर्माण और व्यापार करना; तकनीकी और अन्य सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान करना। उपरोक्त के अलावा, निगम का मुख्य कार्यकलाप है – सरकारी वनों से अच्छी किस्म के बांस एकत्र करना, निगम के पंजीकृत चटाई बुनकरों को उधार आधार पर बांस का वितरण करना और बुनी हुई मैटों की निर्धारित कीमत पर अधिप्राप्ति करना।

परिषद्, सुविधा स्थापित करने के लिए बम्बू मशीनरी उपलब्ध कराएगी। अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं सहित भूमि और भवन, उनकी अपनी लगातार केरल राज्य बांस निगम (के.एस.बी.सी.) द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

उपरोक्त इकाई से 100 कारीगरों को रोजगार प्राप्त होगा। केन्द्र में उत्पादित मैटों की अधिप्राप्ति, बांस बोर्ड और प्लाई का उत्पादन करने के लिए के.एस.बी.सी. द्वारा की जाएगी। इसलिए, केन्द्र, राज्य में स्थानीय संसाधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायता करेगा।

10. उत्तराखण्ड में आपदा प्रतिरोधी निर्माण प्रौद्योगिकियों में मास्टर राजमिस्त्रियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना

परिषद् ने, उत्तराखण्ड में आपदा प्रतिरोधी निर्माण प्रौद्योगिकियों में मास्टर राजमिस्त्रियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु एक परियोजना आरम्भ की है।

प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य, आपदा प्रतिरोधी निर्माण प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से मास्टर राजमिस्त्रियों को परिचित कराना है, क्योंकि उत्तराखण्ड भूकम्पीय जोन V में पड़ता है। इस क्षेत्र में कुछ ही दिन पहले बड़े भूकम्प आए हैं।

कंकरीट ब्लॉक मैसनरी, कंकरीट कोरनर ब्लॉक मैसनरी, एम.सी.आर. टायल्स, आर. सी.सी. चौखटों, बोन्ड्स, बोन्ड्स और अन्य प्रिफेब्र प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल में, कुशल और अकुशल वर्करों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। केन्द्र का प्रस्ताव है कि निम्नलिखित स्थानों पर 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रत्येक स्थान पर 2-2) आयोजित किए जाएं:

1. श्रीनगर, गंगानाली, जिला पौड़ी गढ़वाल
2. गैरसेन, जिला चमोली

3. सांकर, जिला पौड़ी गढ़वाल
 4. बैदियागढ़, जिला टिहरी गढ़वाल
- प्रत्येक कार्यक्रम की अवधि 7-7 दिन होगी और 10 कुशल तथा 10 अकुशल राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

11. रायपुर, छत्तीसगढ़ के निकट के ग्रामीण क्षेत्रों के 30 राजमिस्त्रियों के क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

परिषद्, रायपुर, छत्तीसगढ़ के निकट के ग्रामीण क्षेत्रों के राजमिस्त्रियों के क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दो भागों में होगा:

कक्षा में प्रशिक्षण

निर्माण केन्द्र पर 25 कार्य दिवसों का प्रशिक्षण, जिसमें सिद्धान्त, प्रदर्शन और वास्तविक निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करके बेसिक कार्य का प्रशिक्षण शामिल होगा। प्रशिक्षणार्थियों को एक प्रशिक्षण किट उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें नोट बुक, पेंसिल और उनकी भाषा में छपे हुए लीफलेट होंगे।

निर्माण स्थल पर ग्रायोगिक अनुभव

प्रशिक्षणार्थियों को 6-6 राजमिस्त्रियों के बैच में एक मास्टर प्रशिक्षक के पर्यवेक्षण में रखा जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों को गैर-सरकारी संगठन के विभिन्न निर्माण स्थलों पर भेजा जाएगा और प्रशिक्षणार्थियों के कौशल को विकसित करने के लिए उन्हें विभिन्न कार्यकलाप सौंपे जाएंगे। गैर-सरकारी संगइन के साइट इंजीनियरों द्वारा निरंतर मानीटरिंग और गुणवत्ता जांच की जाएगी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का फोकस निम्नलिखित विषयों पर होगा:

- अच्छी निर्माण पद्धतियां।
- इमरातों में प्रबलन।
- सीमेंट गरे के विभिन्न प्रकार।
- दीवार के विकल्प।
- आर.सी.सी. लिंटल और शटरिंग।
- फैरो-सीमेंट उत्पाद।
- आर.सी.सी. फिल्टर स्लैब।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, निर्माण केन्द्र, निर्माण विकास अनुसंधान संस्थान (छत्तीसगढ़ आवास बोर्ड की एक इकाई), रायपुर के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा।

12. पूर्वनिर्मित निर्माण संघटकों के उत्पादन के लिए मशीनों का उन्नयन

बी.एम.टी.पी.सी., कार्यकलाप के अपने क्षेत्र के एक भाग के रूप में, लागत प्रभावी निर्माण संघटकों के उत्पादन के लिए 30 भिन्न-भिन्न मशीनरियों को बढ़ावा दे रही

है। इनमें से कुछ मशीनें पिछले 10 वर्षों से काम कर रही हैं और इनमें सुधार की आवश्यकता है।

बाजार में प्रिकास्ट निर्माण संघटकों की बढ़ती मांग और अन्य मशीन विनिर्माताओं से प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए और मशीनों की उत्पादन क्षमता, दक्षता, मजबूती आदि में वृद्धि करने के लिए इनका उन्नयन भी आवश्यक है। अनुसंधान और विकास कार्यकलापों के लिए निम्नलिखित मशीनों का नया डिजाइन तैयार किए जाने की आवश्यकता है:

पूर्वनिर्भित आर.सी.सी. फलक बनाने की मशीन

मौजूदा 2 प्लंक प्रति चक्र से बढ़ाकर 4 प्लंक प्रति चक्र करने के लिए मशीन की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मलबे के रिसाव की समस्या को ध्यान में रखते हुए इसके डिजाइन में भी परिवर्तन किया जाएगा।

पूर्वनिर्भित आर.सी.सी. जोड़स्ट बनाने की मशीन

मशीन द्वारा इस समय उत्पादित प्लेन आर.सी.सी. जोड़स्ट्स के अलावा टेपर्ड जोड़स्ट्स का उत्पादन। उपरोक्त मशीन में डिमोलिंग प्रक्रिया में भी परिवर्तन किया जाएगा।

पूर्वनिर्भित दरवाजों/खिड़कियों के चौखट बनाने की मशीन

इस समय मशीन द्वारा बनाए जाने वाले कंकरीट डोर/विंडो फ्रेमों के अलावा वेंटीलेटर फ्रेमों का उत्पादन करना। इसके लिए मशीन में अतिरिक्त वाइब्रेटर लगाया जाएगा।

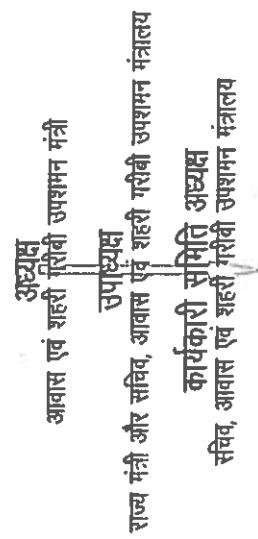
संगठन

अगले पृष्ठ पर दिये गये चार्ट से परिषद की व्यवस्था में विभिन्न कार्य यूनिटों के संगठन स्वरूप को दर्शाया गया है। 31 मार्च 2007 को बी.एम.टी.पी.सी. में 20 अधिकारियों एवं 25 सहायक कर्मचारियों तथा ठेके पर लिये गये तकनिशियनों /प्रोफेशनल्स को मिलाकर 45 व्यक्ति कार्यरत थे।

अर्थव्यवस्था में खुलापन आने और औद्योगिक सैक्टर में निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप भवन सामग्री तथा उद्योग ने भी धीरे-धीरे पिछले वर्षों की तुलना में भारतीय तथा विदेशी दोनों ही तरह के उद्यमियों से निवेश अधिक संख्या में आकर्षित किए हैं। विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही को तीव्र व सहायक बनाने के बी.एम.टी.पी.सी. के ध्येय को ध्यान में रखते हुए परिषद विभिन्न उपभोक्ता वर्गों से बढ़ रही मांग से अपनी चुनौतियों का सबक ले रही है। इन चुनौतियों में अन्य बातों के साथ घरेलू तथा विदेशी निवेश के लिए आकर्षक माहौल पैदा करना, सूचना प्रणाली के प्रवाह को प्रभावी बनाना, सहायक कार्य-कलाप शुरू करना और आवास तथा भवन निर्माण क्षेत्र की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए आधारभूत सुविधाओं में सुधार करना शामिल है। मंत्रालय के सुझाव पर उप-नियमों में प्रारूप संशोधन, कर्मचारियों की आचरण नियमावली एवं भर्ती नियम के साथ-साथ शक्तियों का प्रत्यायोजन का प्रस्ताव किया गया है तथा अपने नियंत्रण मंत्रालय के विचारार्थ भेज दिया गया है।

निर्णण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संबद्धन परिषद्

संस्थागत संरचना



कार्यकारी निदेशक

कार्यकारी विकास	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं विभाग	प्रबन्धन सेवाएँ	प्रशासन
प्रबन्धन एवं भवन विभाग	भवन राज्यों के लिए विभाग	वित	कार्यालय का नामिकरण
नियन्त्रण समिति	कार्यालयों एवं शहरी शासन		
नियन्त्रण विभाग	विभिन्न राज्यों कार्यालय विभाग		
तकनीकी सेवा	नियन्त्रण समिति		
कार्यकारी विकास	प्रशासन		

स्टाफ / कार्मिक संख्या (31.3.2007 की स्थिति के अनुसार)

क्रम संख्या	नाम व पदनाम	कार्यग्रहण की तारीख
1.	आर.के. सैली कार्यकारी निदेशक	01.09.05
2.	एस बालाश्रीनिवासन प्रमुख-वित्त	08.04.92
3.	जे. के. प्रसाद प्रमुख-निर्माण सामग्री	01.09.03
4.	आई.जे. एस. सिंह प्रमुख – परियोजना निगरानी एवं प्रशिक्षण	16.09.99
5.	एस.के. गर्ग उप प्रमुख – कितीय योजना (आई.सी.ए.आई. में लियन पर)	24.03.92
6.	एम रमेश कुमार उप प्रमुख-प्रबंधन सूचना तन्त्र	01.04.93
7.	अरुण कुमार तिवारी उप प्रमुख-मानकीकरण एवं उत्पाद विकास तथा प्रशासन	22.07.03
8.	एस. के. गुप्ता उप प्रमुख-प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, विस्तार एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	26.10.93
9.	अरविन्द कुमार सिस्टम प्रबन्धक	15.4.99
10.	डॉ. अमित राय विकास अधिकारी-निर्माण सामग्री-उत्पाद विकास	05.11.98
11.	चान्दी नाथ झा विकास अधिकारी-निर्माण सामग्री-उत्पाद मूल्यांकन	09.09.99
12.	पंकज गुप्ता विकास अधिकारी-अभियांत्रिकी डिजाइन एवं निष्पादनता मूल्यांकन	14.10.99
13.	डॉ. पी. सिंह विकास अधिकारी- प्रदर्शन, निर्माण एवं प्रदर्शनी	05.10.98
14.	रिच्छपाल सिंह कार्मिक अधिकारी	23.02.94
15.	दलीप कुमार तंत्र विश्लेषक	04.03.91
16.	आलोक भट्टनागर पुस्तकालय अधिकारी	05.10.98
17.	आकाश कुमार माथुर क्षेत्र अधिकारी- उत्पाद मूल्यांकन	01.01.02
18.	एस. एम. मल्होत्रा प्रमुख निजी सचिव	09.04.99
19.	अनीता कुमार वरिष्ठ प्रोग्रामर	03.10.96
20.	एम. कृष्णा रेडी सम्पर्क अधिकारी (कोयला मंत्रालय में प्रतिनियुक्त पर)	29.10.03

लेखा

परिषद् को आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार से 430.00 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। परिषद् ने आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई 649.17 लाख रुपए की राशि पिछले वर्ष से अग्रेनीत की है।

अप्रैल 2006 से मार्च 2007 तक की अवधि के दौरान कुल व्यय 6,16,19,890 रु हुआ, जिसका विवरण इस प्रकार है :-

मुख्य शीर्ष	राशि (रुपये में)
● प्रायोजित अध्ययनों पर व्यय	58,19,652
● संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों एवं सूचना प्रसार पर व्यय	1,03,74,476
● नियत परिसम्पत्तियों की खरीद पर व्यय	412,738
● प्रौद्योगिकी विकास/ अनुप्रयोग के लिए वित्तीय सहायता पर व्यय	60,25,464
● कार्मिक खर्च	1,45,15,169
● प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	76,12,502
● वाल्नीकि अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत प्रदर्शन भवनों के निर्माण पर खर्च	53,77,440
● मिजोरम में प्रदर्शन भवन निर्माण पर व्यय	4,00,000
● पूर्वोत्तर राज्यों में बांस चटाई उत्पादन केन्द्रों की स्थापना	66,09,839
● गृह मंत्रालय एवं अन्य से प्राप्त राशियों के प्रति विभिन्न कार्यक्रमों पर खर्च	16,68,471
● त्रिपुरा में लागत-प्रभावी प्रौद्योगिकी से प्रदर्शन भवन निर्माण एवं प्रदर्शन व उत्पादन केन्द्र पर खर्च	28,04,139
जोड़	6,16,19,890

लेखाओं की लेखा-परीक्षा मैसर्ज़ एम.एस. सेखों एण्ड कम्पनी, चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा की गई है। वर्ष 2006-07 का तुलन-पत्र तथा लेखा विवरण, रिपोर्ट में आगे दिया गया है।

एम.एस. सेखों एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड लेखाकार
170, मधुबन, दिल्ली-110092

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण
निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संबद्धन परिषद्
नई दिल्ली

1. हमने निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संबद्धन परिषद् जो सोसायटीज एक्ट- 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है, की 31 मार्च, 2007 के संलग्न तुलन-पत्र सहित उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के आय तथा व्यय लेखों एवं प्राप्ति तथा भुगतान लेखों की लेखा-परीक्षा की है। इन वित्तीय कथनों की जिम्मेदारी परिषद् के प्रबंधन की है। हमारी जवाबदेही अपनी लेखा-परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय कथनों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारत में आमतौर पर स्वीकार की जाने वाले लेखा मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों की मांग है कि हम त्रुटिपूर्ण सामग्री से रहित वित्तीय कथन के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना तथा लेखा-परीक्षा करें। एक लेखा-परीक्षा में, वित्तीय कथनों में राशि व उल्लेखों को प्रबलित करने वाले जो प्रमाण हैं उनका परीक्षण आधार पर निरीक्षण करना है। एक लेखा-परीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों व प्रबंधन द्वारा दिये गये विशिष्ट अनुभानों का आंकलन करना भी है। इसके साथ-साथ इसमें सकल वित्तीय कथन प्रस्तुतीकरण भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारी राय के बारे में एक तर्क-संगत आधार उपलब्ध कराता है।
2. इससे आगे हमारा कहना है कि
 - i. हमने वे सभी सूचनाएँ तथा स्पष्टीकरण ग्राप्त किए जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक थे।
 - ii. हमारी राय में परिषद् के बहियों की जांच करने से प्रतीत होता है कि परिषद् ने सही बहियां रखी हैं।
 - iii. इस रिपोर्ट में तुलन-पत्र आय तथा व्यय लेखे एवं प्राप्ति तथा भुगतान लेखों से मेल खाते हैं।
3. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखाकरण नीतियों के साथ पठित उक्त लेखे और उनका भाग बनाई गई टिप्पणियां सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं:
 - i. 31 मार्च 2007 को परिषद् के कार्यों के तुलन-पत्र के मामले में;
 - ii. इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए खर्च के सापेक्ष आय की अधिकता के आय एवं व्यय लेखा के मामले में, और
 - iii. इस तिथि को समाप्त वर्ष के दौरान किए गए भुगतानों और प्राप्तियों के प्राप्ति और भुगतान लेखों के मामले में।

कृते एम.एस. सेखों एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेट

ह/
राजीव टंडन
आगीदार
(सदस्यता संख्या 87343)

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 10 अगस्त, 2007

फोन एवं फैक्स : 91-11- 42445194, 42445294, 42445394 ई मेल sekhonms@rediffmail.com & sekhonms@sify.com

31 मार्च, 2007 को तुलन-पत्र

	अनुमति	2006-2007	राशि (रुपये में) 2005-2006
कार्यक / पूँजीगत निधि एवं देयताएं			
कार्यक / पूँजीगत निधि	1	1,000,000	1,000,000
आरक्षित एवं अधिशेष	2	111,963,369	87,633,228
निर्धारित पूँजी	3	48,056,651	64,916,540
चालू देयताएं एवं प्रावधान	4	1,403,714	971,258
कुल		162,423,734	154,521,026
परिस्थितियां			
स्थिर परिस्थितियां	5	41,356,516	42,469,824
चालू परिस्थितियां, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि	6	121,067,218	112,051,202
कुल		162,423,734	154,521,026
नहत्त्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखों की टिप्पणियां	15		

ह०
(एस.बालाश्रीनिवासन)
प्रमुख – वित्त

ह०
(आरके सैली)
कार्यकारी निदेशक

हमारी पृथक संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम.एस. सेखों एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 10 अगस्त, 2007

ह०
(राजीव टडन)
मागीदार

31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

	अनुसूची	2006-07	राशि (रुपये में) 2005-06
<u>आय</u>			
अनुदान/छूट	7	43,000,000	45,200,000
शुल्क/चंदा	8	14,416,838	1,224,590
रोयलटी प्रकाशनों और मशीनों आदि से प्राप्त आय	9	4,722,646	1,420,672
अर्जित ब्याज	10	6,203,095	7,042,993
कुल (क)		68,342,579	54,888,255
<u>व्यय</u>			
स्थापना खर्च	11	14,515,169	17,260,482
अन्य प्रशासनिक खर्च आदि	12	7,594,526	7,160,031
प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि पर खर्च	13	10,360,456	8,951,284
वित्तीय सहायता, प्रायोजित अध्ययनों आदि पर खर्च	14	11,845,116	11,080,722
मूल्यहास	5	1,526,046	1,912,573
कुल(ख)		45,841,313	46,365,092
व्यय से अधिक आय के कारण शेष (क-ख)		22,501,266	8,523,163
जांडे पूर्वविदि समायोजन		1,828,875	
घटाएं पिछले वर्षों के लिए मूल्यहास			33,241,445
बिधिवृक्ष हाने के कारण शेष पूँजी को तुलन-पत्र में ले जाया गया		24,330,141	24,718,282
महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं लेखे की टिप्पणियां	15		

६०
(एस बालाश्रीनिवासन)
प्रमुख - वित्त

६०
(आर.के. सैली)
कार्यकारी निदेशक

हमारी पृथक संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम.एस. सेखों एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

स्थान : दिल्ली
दिनांक 10 अगस्त, 2007

६०
(राजीव टंडन)
मार्गदार

bhartipc निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संबद्धन परिषद्

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार

31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान लेख

	2006-07	2005-06	राशि (रुपय में)
प्राप्तिया			
1 आदि शब्द			
- नकद शेष (बैंक/झापट एवं अग्रदाय सहित)	63,250	292,658	
- नकद शेष	12,013	75,272	
- बैंक शेष			
बैंक शेष			
अनुसूचित बैंकों में			
- केनरा बैंक (संसद गार्ग) के चाल खाते में	140,656	6,346	
- केनरा बैंक के सावधि जमा खाते में	94,488,602	82,560,000	
बचत खाते में			
- केनरा बैंक (संसद गार्ग)	2,102,375	9,582,093	
- केनरा बैंक (होज खाता)	5,732,681	2,395,364	
- केनरा बैंक (बंगलार)	466,361	2,211,947	
- केनरा बैंक संसद गार्ग (द्वितीय परियोजना)	2,271,115	105,201,790	6,890,033
2 केन्द्र सरकार (आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय) से प्राप्त सहायता-अनुदान	43,000,000	45,200,000	
3 शब्द/ शब्दों वाला	14,416,838	1,224,590	
4 स्थानीय शब्द/ प्रकाशनों इत्यादि से आगदनी	4,633,726	1,345,672	
5 पूर्ववधि समायोजन	1,828,875	-	
6 वर्ष के दौरान उगाही गई राशि			3,384,316
7 अंजित व्याज	7,253,855	5,452,392	
8 ऋण और अधिग्राह (निवल)	188,837	-	
9 परामर्श प्रतिभूति जमा आदि के प्रति प्राप्तियां	553,372	880,705	
कुल	177,162,865	165,931,327	
भुगतान			
1 स्थर परिस्थितियों की खरीद	412,738	66,437	
2 स्थापना खर्च	14,515,169	17,260,482	
3 प्रशासनिक खर्च इत्यादि	7,612,502	7,207,877	
4 प्रशासन कार्यक्रम, समाजनीय/कार्यकालान्त्रों आदि पर खर्च	10,374,476	8,863,876	
5 वित्तीय सहायता, प्रायोजित अध्यक्षों आदि पर खर्च	11,845,116	11,080,722	
6 स्टाफ जगत् एवं अधिग्राह राशियां (निवल)		840,870	
7 नियंत्रित निधियां			
नियंत्रित ग्रामीण प्रशासनिकियों से प्रदर्शन भवनों एवं प्रायोगिकों प्रदर्शन व उत्पादन केन्द्र प्रदर्शन भवनों में बाज़ बदली उत्पादन केन्द्रों की स्थापना	2,804,139	976,954	
ग्रामीण में प्रदर्शन भवन का निर्माण	6,609,839	3,868,033	
ग्रामीण कार्यक्रमों अम्बेडकर आवास योजना (विवेद) के अन्तर्गत प्रदर्शन भवन का निर्माण	400,000	714,721	
टाउन एण्ड कॉम्पोनेंट्स योजना (विवेद) के अन्तर्गत प्रदर्शन भवन का निर्माण	5,377,440	8,580,805	
टाउन एण्ड कॉम्पोनेंट्स योजना (विवेद) के अन्तर्गत प्रदर्शन भवन का निर्माण	1,668,471	16,859,889	508,330
8 ग्रामीण राशि व अन्यों से प्राप्त राशि में से विभिन्न कार्यक्रमों पर खर्च		14,648,843	
9 अन्त राशि		685,149	
नकद राशि			
- नकद शेष	18,022	63,259	
- बैंक शेष	114,800	132,822,00	12,013
बैंक शेष			
अनुसूचित बैंकों में			
- चाल खाते में शेष, केनरा बैंक (संसद गार्ग)	140,656	140,656	
- सावधि खाता, केनरा बैंक	100,126,514	94,488,602	
बचत खातों में शेष			
- केनरा बैंक (संसद गार्ग)	7,762,023	2,102,375	
- केनरा बैंक (होज खाता)	5,276,061	5,732,681	
- केनरा बैंक, निपुर	266,485		
- केनरा बैंक (बंगलार)	501,541	466,361	
- केनरा बैंक, संसद गार्ग (द्वितीय परियोजना)	1,328,573	115,309,853	2,271,115
कुल	177,162,865	165,931,327	

३०
(एस बालाश्रीनवजन)
प्रमुख - वित्त

३०
(आर के सेली)
कार्यकारी निदेशक

हमारी पृथक संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृत एमएस संसार्क एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

स्थान : दिल्ली
दिनांक: 10 अप्रैल, 2007

३०
(रुपय ८८०)
भागीदार

31 मार्च, 2007 के तुलन-पत्र के मागों की अनुसूचियां

	राशि (रुपये में)	
	2006-07	2005-06
अनुसूची-1 - कार्यिक / पूँजीगत निधि		
वर्ष के आरम्भ में शेष	1,000,000	1,000,000
कुल	1,000,000	1,000,000

	2006-07		2005-06	
1. पूँजीगत आरक्षित निधि				
गत लेखानुसार	77,623,842		77,557,405	
वर्ष के दौरान जमा	412,738	78,036,580	66,437	77,623,842
2. खर्च से अधिक अतिरिक्त आमदनी				
आदि शेष	10,009,386		34,794,105	
घटाएँ: आय एवं व्यय लेखे से अंतरित की आमदनी से अधिक खर्च	-		24,718,282	
जोड़ें: आय एवं व्यय लेखे से अंतरित की गई खर्च से अधिक आमदनी	24,330,141		-	
	34,339,527		10,075,823	
घटाएँ: पूँजीगत आरक्षित निधि को अंतरित	412,738	33,926,789	66,437	10,009,386
कुल	111,963,369		87,633,228	

मानप निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संबद्धन परिषद्
आवास एवं शहरी नरेवा अभ्यास मञ्चसंघ इतिहास संकलन

31 मार्च, 2007 के तुलन-पत्र के भागों की अनुसूचियाँ

		रुपये (रुपये म)	2006-07	2005-06
अनुसूची-3 – नियारित निधि			2006-07	2005-06
1 त्रिपुरा में लागत-प्रमाणी प्रौद्योगिकियों से प्रदर्शन भवनों एवं प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं उत्पादन केन्द्र भवनों का निर्माण				
आदि शेष		9,878,023	10,854,977	
घटाएः वर्ष के दौरान उपयोग/खर्च		<u>2,804,139</u>	<u>7,073,884</u>	<u>976,954</u>
		<u>9,878,023</u>		
2 पूर्वोत्तर राज्यों में बांस घटाई उत्पादन केन्द्रों की स्थापना				
आदि शेष		11,165,951	15,033,984	
घटाएः वर्ष के दौरान उपयोग/खर्च		<u>3,589,405</u>	<u>3,868,033</u>	
: मशीनों की संरीद के लिए दिया गया अधिक		<u>3,020,434</u>	<u>4,556,112</u>	<u>-</u>
		<u>11,165,951</u>		
3 मिजोरम में प्रदर्शन घरों का निर्माण				
आदि शेष		714,343	1,429,064	
घटाएः वर्ष के दौरान उपयोग/खर्च		<u>400,000</u>	<u>314,343</u>	<u>714,721</u>
		<u>714,343</u>		
4 वालीकि अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत प्रदर्शन घरों का निर्माण				
आदि शेष		40,256,607	48,862,412	
घटाएः वर्ष के दौरान उपयोग/खर्च		<u>5,377,440</u>	<u>34,879,167</u>	<u>8,605,805</u>
		<u>40,256,607</u>		
5 टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग एवं जोनिंग विनियमों में मॉडल संशोधन				
आदि शेष		2,901,616	3,409,946	
घटाएः वर्ष के दौरान उपयोग/खर्च		<u>1,668,471</u>	<u>1,233,145</u>	<u>508,330</u>
		<u>2,901,616</u>		
	कुल	48,056,651		64,916,540



निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संबंधन परिषद्
आवास एवं शहरी गरीबी उपराजन मंत्रालय, भ्रत सरकार

31 मार्च 2007 के तुलन-पत्र के मागों की अनुसूचियां

	राशि (रुपये में)	
	2006-07	2005-06
अनुसूची - 4 - आलू देयताएं और प्रावधान		
आलू देयताएं		
- बकाया देयताएं	471,237	158,661
- इन्डो पोलिश परियोजना के लिए प्राप्त धनराशि	60,600	60,600
- प्रतिष्ठाति जमा	851,065	731,185
- भवन उपनियम बनाने के लिए प्राप्त निधियों का शेष	20,812	20,812
कुल	1,403,714	971,258

निर्माण समग्री एवं प्रौद्योगिकी संबद्धन परिषद्

आवास एवं शहरी तथा उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार

31 मार्च 2007 के तुलन-पत्र के भागों की अनुसूचियाँ

अनुसूची-5 – विभिन्न परियोजनाओं

		सकल ब्लॉक	मूलधारा	निवल ब्लॉक	निवल ब्लॉक	निवल ब्लॉक	निवल ब्लॉक	
	14.06 को लागत	30.09.06 तक वृद्धि	01.10.06 के बाद वृद्धि	कुल	1.04.06 तक	चालू वर्ष	31.03.07 तक	31.03.07 को
भारत पर्यावरण केन्द्र वित्त कार्यालय भवन (एटे ए)	34,319,817	-	-	34,319,817	-	-	-	34,319,817
फॉन्डेशन एं ज़ुडगार	3,073,004	-	-	3,073,004	1,528,005	154,500	1,682,505	1,390,499
कार्यालय उपकरण	16,025,546	-	-	16,025,546	13,268,201	413,602	13,681,803	2,345,743
काम्पूलर / परियोजना समाज	12,197,570	236,808	62,868	12,497,426	11,737,423	437,033	12,174,456	322,790
वातानुकूलन यंत्र	505,775	-	-	505,775	319,095	28,002	347,097	158,678
पंखे एवं कूतूर	32,916	-	-	32,916	28,642	641	29,283	3,633
टी.वी. एं वी.सी.आर	265,450	-	-	265,450	136,584	19,330	155,914	109,536
प्रदर्शन सामग्री, धनत, प्रदर्शन मैदान	11,203,764	57,375	55,687	11,316,826	8,136,068	472,938	8,609,006	2,707,820
पिछला वर्ष (2005-06)	77,623,842	294,183	118,555	78,036,580	35,154,018	1,526,046	36,680,064	41,355,616
	77,557,405	-	66,437	77,623,842	33,241,445	1,912,573	35,154,018	42,469,824
								-

31 मार्च 2007 के तुलन-पत्र के भागों की अनुसूचियां

अनुसूची ६- चालू परिसंचयियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	राशि (रुपये में)	
	2006-07	2005-06
क. चालू परिसंचयियां :		
क. नकदी की शेष राशि :		
- नकद शेष	18,022	63,259
- घैल शेष	114,800	132,822
	<hr/>	<hr/>
2. बैंक शेष		12,013
		75,272
अनुसूचित बैंकों में-		
- चालू खाते में, केनरा बैंक (संसद मार्ग) ने	140,656	140,656
- जमा खाते में, केनरा बैंक बघत खाते में	100,126,514	94,488,602
- केनरा बैंक, संसद मार्ग	7,762,023	2,102,375
- केनरा बैंक, (हौजखास)	5,276,061	5,732,681
- केनरा बैंक (बैंगलोर)	501,541	466,361
- केनरा बैंक, त्रिपुरा	266,485	-
- केनरा बैंक, संसद मार्ग (हैम्पे परियोजना)	1,326,573	115,399,853
	<hr/>	<hr/>
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंचयियां-	2,271,115	105,201,790
1. कर्मचारियों को ऋण	3,258,881	3,262,574
2. अग्रिम व अन्य राशियां जोकि नकद या वस्तु रूप में वसूलीयोग्य हैं या जिनका नूत्य अभी प्राप्त करना है।		
(क) वसूलीयोग्य राशि और अन्य अग्रिम	790,595	1,429,885
(ख) प्रतिमूलि जमा राशि (किराया)	420,000	420,000
(ग) ढोत पर काटा गया वसूलीयोग्य कर	35,570	71,080
3. नशीनों की खरीद के लिए अग्रिम	489,656	1,920,965
4. एफ.डी.आर. पर उपचित ब्याज	539,841	1,590,601
कुल (क + ख)	121,067,218	112,051,202

31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखों के भागों की अनुसूचियां

		रुपये (रुपये में)	
		2006-07	2005-06
अनुसूची 7- अनुदान/छट (अपरिवर्तनीय अनुदान एवं प्राप्त छट)		43,000,000	45,200,000
केन्द्र सरकार (आवास एवं शहरी गरिबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार)		43,000,000	45,200,000
कुल		43,000,000	45,200,000
अनुसूची 8- शुल्क / अंशदान			
1 संगोष्ठी/कार्यक्रम से प्राप्त		3,180,838	622,590
2 परामर्श से प्राप्त		11,236,000	602,000
कुल		14,416,838	1,224,590
अनुसूची 9- रायल्टी, प्रकाशन_आदि से आय			
1 प्रकाशनों की बिक्री, लाइसेंस शुल्क, पीएसीएस आदि के लिए प्राप्तियां		4,722,646	1,420,672
कुल		4,722,646	1,420,672
अनुसूची 10- अर्जित व्याज			
1 अनुसूचित बैंकों में आवधिक जमा पर		5,867,500	6,661,305
2 अनुसूचित बैंकों में बचत खाते पर		298,787	324,085
3 कर्मचारियों/स्टाफ को दिए गए ऋण पर		36,808	57,603
कुल		6,203,095	7,042,993
अनुसूची 11- स्थापना खर्च			
1 देतन एवं भत्ते		11,591,850	11,824,112
2 भविष्य निधि में अंशदान		991,685	769,108
3 एल आई सी समूह उपदान योजना में अंशदान		282,846	2,507,624
4 छुट्टी यात्रा रियायत		91,071	121,594
5 एल आई सी समूह छुट्टी नकदीकरण योजना में अंशदान		372,468	1,297,811
6 चिकित्सा खर्च		945,599	695,546
7 परामर्श/रिटेनरशिप एवं मानदेय		239,650	44,687
कुल		14,515,169	17,260,482

31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष में आय एवं व्यय लेखों के भागों की अनुसूचियां

	राशि (रुपये में)	
अनुसूची 12- प्रशासनिक खर्च, इत्यादि	2006-07	2005-06
1. यात्रा एवं स्थानीय परिवहन	2,961,465	2,609,178
2. डाक, टेलीफोन एवं फैक्स	834,334	856,916
3. आकस्मिक खर्च	532,512	293,998
4. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	430,462	362,120
5. कार्यालय का रखरखाव	1,413,050	1,712,543
6. दरें एवं कर	268,229	268,229
7. व्यावसायिक प्रभार	23,509	58,968
8. सदस्यता शुल्क	23,394	20,200
9. विद्युत प्रभार	418,962	204,113
10. कार्यालय किराया	671,664	755,496
11. लेखा-परीक्षा शुल्क	14,591	14,326
12. बैंक प्रभार	2,354	3,944
कुल	7,594,526	7,160,031

	2006-07	2005-06
अनुसूची 13- प्रसार/ संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि पर व्यय		
1. विज्ञापन	290,150	332,619
2. प्रदर्शनी एवं प्रचार	2,037,154	1,736,458
3. संगोष्ठी और सम्मेलन खर्च	4,856,467	1,034,162
4. मुद्रण और प्रकाशन	1,148,309	340,149
5. पुस्तकें और पत्रिकाएं	107,283	74,612
6. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण	756,738	5,111,603
7. प्रशिक्षण कार्यक्रम	1,164,355	321,681
कुल योग	10,360,456	8,951,284

31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष में आय एवं व्यय लेखों के मागों की अनुसूचियां

		राशि (रुपये में)
	अनुसूची 14 – वित्तीय सहायता प्रायोजित अध्ययनों, इत्यादि पर खर्च	2006-07 2005-06
1 प्रायोजित अध्ययन		
वृहत अनुपयोग और वाणिज्यिकीकरण के लिए स्वदेशी उत्पादन प्रौद्योगिकियों का स्तरोन्नयन तथा आधुनिकीकरण	1,688,000	1,948,150
असुरक्षितता में कमी, जोखिम आकलन और आपदा प्रतिरोधी निर्माण प्रौद्योगिकी क्रियाकलाप।	944,828	482,987
आवास निर्माण में बांस के इस्तेमाल पर प्रौद्योगिकियों का विकास	2,041,000	1,012,500
मानकीकरण और उत्पाद मूल्यांकन क्रियाकलाप	24,004	-
डाटाबेस, प्रौद्योगिकी प्रसार और प्रदर्शन क्षमता को सुदृढ़ बनाना	1,121,820	1,343,211
उप-जोड़	5,819,652	4,786,848
2 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और अनुप्रयोग के लिए वित्तीय सहायता		
आपदा प्रतिरोधी निर्माण और भूकम्पीय सुदृढ़ीकरण तकनीकों को बढ़ावा देना	2,653,400	1,417,131
आवास और भवन निर्माण में बांस आधारित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना और उनका अनुप्रयोग	1,644,006	54,728
निर्माण व्यवसायविदों, श्रम शक्ति आदि का क्षमता निर्माण	125,000	-
लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों का प्रसार और प्रदर्शन	1,603,058	4,822,015
उप-जोड़	6,025,464	6,293,874
जोड़	11,845,116	11,080,722

अनुसूची – 15 : महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां

1 महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

- क) लेखांकन की प्रणाली: वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत प्रभासा के आधार पर तैयार किये जाते हैं और आमतौर पर स्वीकार की जाने वाली लेखांकन पद्धतियों के अनुरूप है।
- ख) स्थिर परिसम्पत्तियां: स्थिर परिसम्पत्तियां प्राप्ति की लागतों पर दर्ज की जाती है और भूत्यहास का प्रावधान, आय कर अधिनियम, 1961 में यथा विदेश तरीके से और दर पर किया जाता है।
- ग) सेवानिवृत्ति लासः:
- कर्मचारियों को इस जाने वाले उपदान के संबंध में देयता का प्रावधान, समूह उपदान योजना के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान किए गई प्रीमियम के जरिए किया जाता है।
- कर्मचारियों को भुगतानयोग्य छुट्टी नकदीकरण के संबंध में देयता का प्रावधान, मास्टर पालिसी के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान की गई प्रीमियम के जरिए किया जाता है और भुगतान की गई प्रीमियम राजस्व को प्रभारित की जाती है।
- परिषद् अपने भविष्य निधि न्यास में अशदान करती है जो आयकर प्राधिकारियों से मान्यता प्राप्त है और इस वर्ष के दौरान भविष्य निधि न्यास में किया गया अशदान राजस्व को प्रभारित किया गया है।
- घ) विदेशी मुद्रा में लेनदेन: विदेशी मुद्रा में होने वाले लेन-देन को, दिनांक को प्रचलित विनियम दर पर लिखा जाता है।
- ड) सामान्य: यहां पर विशेष रूप से उल्लेखित नहीं की गई लेखांकन नीतियां अन्यथा भी आमतौर पर स्वीकार की जाने वाली लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं।

2 आकस्मिक देयताएः: क्रण के रूप में नहीं जाने गए परिषद् के विरुद्ध दावे – शून्य

- ३ प्रबन्धन की राय में, चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों एवं रासान्य व्यवहार में अग्रिम राशियों के वसूली के पश्चात् गूल्य राशि उरा धनराशि से कम नहीं होगी, जिस धनराशि पर उन्हे तुलन-पत्र में दर्शाया गया है। सभी ज्ञात देयताओं के लिए लेखांकनों में आगे प्रावधान कर दिया गया है।
- ४ आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कोई कर योग्य आमदनी नहीं होने के मददेन्जर, आयकर का प्रावधान लेखों में नहीं किया गया है।
- ५ भारत पर्यावास केन्द्र, लोदी रोड नई दिल्ली-०३ स्थित कार्यालय स्थान की कीमत को भारत पर्यावास केन्द्र ने विभिन्न आवंटियों में अनुपातनुसार नहीं बाटा हुआ है। इसलिए ३४३ करोड़ की राशि को परिषद् ने भारत पर्यावास केन्द्र कार्यालय को माग/भुगतान आधार पर पूँजीकृत किया है।
- ६ बैंकों में जगा धनराशि में 76,514 रुपये की एक सावधि जगा भी शामिल है जो बैंल्यू एडड टैक्स विमाग, राष्ट्रीय शजदानों क्षेत्र दिल्ली रारकर के पक्ष में जारी की गई बैंक गारंटी के सावध में कनरा बैंक के पास बद्धक रखी गई है।
- ७ आकड़ों को निकटतम रूपये में पूर्णांकित कर दिया गया है।
- ८ जहां कहीं आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आकड़ों को पुनः समूहीकृत और पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि उन्हे चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप बनाया जा सके।

६०

(एस. बालाश्रीनिवासन)

प्रमुख – वित्त

६०

(आर.के. सैली)

कार्यकारी निदेशक

हमारी पृथक संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम.एस. सेखों एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

६०

(राजीव टड्डे)

भागीदार

स्थान : दिल्ली

दिनांक: 10 अगस्त, 2007

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों में प्रतिभागिता

I प्रदर्शनियां

इस वर्ष के दौरान, परिषद् ने निम्नलिखित प्रदर्शनियों में सक्रिय रूप से भाग लिया जिससे लागत प्रभावी, पर्यावरण-अनुकूल और ऊर्जा दक्ष निर्माण सामग्रियों, निर्माण प्रौद्योगिकियों और निर्माण संघटकों के उत्पादन के लिए सामान्य मशीनों को लोकप्रिय बनाने में सहायता प्राप्त हुई:

अन्तर्राष्ट्रीय

- 27–28 जुलाई, 2006, पूर्वी लंदन (दक्षिण अफ्रीका) में एन.एस.आई.सी. का कैटलॉग शो और 29–31 अगस्त 2006 को जोहन्सबर्ग में।

राष्ट्रीय

- 2–4 मई, 2006, ग्रेटर नोएडा में इंडिया इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एण्ड कन्ट्रैक्टिंग (आईकॉन–2006)"।
- 27–30 मई, 2006 प्रगति मैदान, नई दिल्ली में वर्ल्ड एक्सपो प्रदर्शनी।
- 1–8 सितम्बर, 2006 को कोलकाता में 10वां नेशनल एक्सपो।
- "बिल्ड टैक" और "टेकमार्ट" में प्रभावशाली प्रदर्शन करके शानदार तरीके से आई.आई.टी.एफ.' 06 में प्रदर्शनी। 14–27 नवम्बर, 2006 के दौरान टेकमार्ट 2006 में अपने प्रदर्शन के लिए परिषद् को "विशेष सम्मान अवार्ड" प्राप्त हुआ।
- 7–9 दिसम्बर 2006, मुम्बई में, इंडिया टेक फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'कंस्ट्रू इंडिया 2006'।
- 16–23 दिसम्बर 2006, अगरतला (त्रिपुरा) में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय बांस कार्यक्रम–बम्फेस्ट 2006।
- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा आयोजित प्रदर्शनी, जिसमें माननीय लघु उद्योग मंत्री श्री महावीर प्रसाद ने जनवरी 2007 में उद्घाटन समारोह के दौरान बी.एम.टी.पी.सी. के कार्यकलापों में गहन रुचि ली।
- 25–29 जनवरी 2007 के दौरान कोयम्बटूर में आयोजित किया गया 'बिल्ड एक्सपो–2007'।
- 24–25 फरवरी, 2007 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 'प्रोपर्टीज अहैड–07' विषय पर प्रदर्शनी।
- 24–26 मार्च, 2007, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में चौथी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कान्फ्रेंस बी.एम.सी.टी.'07।

II संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम

- 31 मार्च से 1 अप्रैल 2006 तक नई दिल्ली में "खतरों का प्रभावी विश्लेषण और जोखिम आकलन" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम यंकज गुफा।

- 20 अप्रैल, 2006 को नई दिल्ली में "न्यू केजन" विषय पर एक-दिवसीय कार्यशाला एस. बालाश्रीनिवासन, एस.के. गुप्ता, असविन्द कुमार, सी. एन. झा /
- 21 अप्रैल 2006 को पी.एचडी. हाउस, नई दिल्ली में '5एस और 3आर' विषय पर एक-दिवसीय कार्यशाला एम. रमेश कुमार, ए.के. तिवारी, डॉ. अमित राय, एस.के. गर्ग /
- 25 अप्रैल 2006 को इटानगर, अरुणाचल प्रदेश में बी.एम.टी.पी.सी. द्वारा आयोजित की गई 'टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग एक्ट, जोनिंग रेग्युलेशन, विकास एवं नियंत्रण विनियम और प्राकृतिक खतरों के प्रति सुरक्षा के लिए भवन निर्माण विनियम' में मॉडल संशोधन' विषय पर एक दिवसीय तकनीकी कार्यशाला जे.के. प्रसाद /
- 25-26 अप्रैल 2006, नई दिल्ली में "वैशिक अर्थव्यवस्था में विपणन पद्धतियां" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम..... आई.जे.एस. सिद्ध एस.के. गुप्ता, डी.पी. सिंह /
- 26-28 अप्रैल, 2006, नई दिल्ली में "जल संसाधन क्षेत्र के लिए कंकरीट की मजबूती" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम डॉ. अमित राय /
- 5 मई 2006 को नई दिल्ली में गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित, राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के राहत कमीशन के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया आई.जे.एस. सिद्ध /
- 8-19 मई 2006 ए.एस.सी.आई., हैदराबाद में "परियोजना रचना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम एस.के. गर्ग, डी.पी. सिंह /
- 5 जून 2006 को नई दिल्ली में गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के राहत कमीशन के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया जे.के. प्रसाद /
- 16 जून, 2006 को दिल्ली मेनेजमेंट एसोसिएशन, नई दिल्ली द्वारा आयोजित "प्रभावी लिखित व्यवसाय सम्प्रेषण" विषय पर एक दिवसीय कार्यक्रम..... ए.के. तिवारी /
- युवा विकास कार्यक्रम: जून, 2006, 16 जून, 2006 को नई दिल्ली में "प्रभावी लिखित व्यवसाय सम्प्रेषण" विषय पर कार्यक्रम एस.के. गर्ग, एम. रमेश कुमार /
- 19 जून 2006 को नई दिल्ली में 'भारतीय राष्ट्रीय निर्माण संहिता 2005' विषय पर कार्यशाला जे.के. प्रसाद, पंकज गुप्ता, सी.एन. झा /
- 24 जून, 2006 को पटना में सी.आई.डी.सी. द्वारा आयोजित "बिहार राज्य में आवास एवं सिविक अवसंरचना विकास" विषय पर संगोष्ठी जे.के. प्रसाद /

- नई दिल्ली में “राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियमः भोजन सुरक्षा प्राप्त करने और ग्रामीण लोगों के लिए आवास एवं पर्यावास में सुधार करने के तरीके खोजने के प्रति” विषय पर एक दिवसीय परामर्श आई.जे.एस. सिद्धू /
- नई दिल्ली में “लीड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग” विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम..... जे.के. प्रसाद, आई.जे.एस. सिद्धू /
- 30 जून 2006 को दिल्ली मेनेजमेंट एसोसिएशन नई दिल्ली द्वारा आयोजित “अपनी छिपी हुई अन्तःशक्ति को खोजें” विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ए.के. तिवारी /
- नई दिल्ली में “निर्माण उद्योग में मानव संसाधन प्रबंधन” विषय पर आई.बी.सी. का 12वां वार्षिक सम्मेलन और राष्ट्रीय संगोष्ठी..... जे.के. प्रसाद, एम. रमेश कुमार, ए.के. तिवारी /
- 7 जुलाई, 2006 को हैदराबाद में विभिन्न नगर निगमों और नगरपालिकाओं के म्युनिसिपल इंजीनियरों और पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय कार्यशाला आई.जे.एस. सिद्धू /
- 13–14 जुलाई, 2006 को नई दिल्ली में हुडको के अधिकारियों के लिए “बी.एस.यू.पी. और आई.एच.एस.डी.पी.” विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला आई.जे.एस. सिद्धू, सी.एन. झा /
- 20–22 जुलाई, 2006, यशदा, पुणे में “म्युनिसिपल पदाधिकारियों के लिए जे.एन.एन.यू.आर.एम.” विषय पर आयोजित किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम आई.जे.एस. सिद्धू /
- 21 अगस्त, 2006 को इम्फाल में बी.एम.टी.पी.सी. द्वारा “टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग एक्ट, जोनिंग रेग्यूलेशन, विकास और नियंत्रण विनियमन एवं प्राकृतिक खतरों के प्रति सुरक्षा हेतु निर्माण विनियम में मॉडल संशोधन” विषय पर तकनीकी कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लगभग 50 इंजीनियरों और आर्चीटेक्टों ने भाग लिया जे.के. प्रसाद /
- 22–23 अगस्त, 2006 नई दिल्ली में बी.एम.टी.पी.सी. द्वारा आयोजित “भवनों और इमारतों की मरम्मत, रखरखाव और सुधार” विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पंकज गुप्ता, डी.पी. सिंह /
- 1 सितम्बर, 2006 को गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित “ग्रीन बिल्डिंग्स – मेनस्ट्रीमिंग सोलर पैसिव बिल्डिंग्स थोरेटिंग सिस्टम्स” विषय पर गोल मेज सम्मेलन आई.जे.एस. सिद्धू /
- 6–8 सितम्बर, 2006 दिल्ली में बी.एम.टी.पी.सी. द्वारा आयोजित “कंकरीट मेकिंग मेटीरियल्स, मिक्स डिजाइन और हाई परफोरमेंस कंकरीट” विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जे.के. प्रसाद, सी.एन. झा /

- 6–8 सितम्बर, 2006 नई दिल्ली में "व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण तथा स्थायी आर्थिक विकास" विषय पर सुरक्षा सम्मेलन आई.जे.एस. सिंहू।
- 11–12 सितम्बर, 2006, एस.ई.आर.सी., चेन्नई द्वारा आयोजित 'कंकरीट में फोलीमर्स' विषय पर 5वीं ऐशियन विचार गोष्ठी सी.एन. झा।
- 18 सितम्बर, 2006 को शिलांग में पूर्वोत्तर राज्यों के आवास मंत्रियों, सचिवों और कमीशनरों के लिए जे.एन.एन.यू.आर.एम. विषय पर एम.ओ.एच. यू.पी.ए. सम्मेलन आर.के. सैली, आई.जे.एस. सिंहू एस.के. गुप्ता।
- 18 से 22 सितम्बर के दौरान दिल्ली में आई.आई.टी., रुड़की के सहयोग से बी.एम.टी.पी.सी. द्वारा आयोजित "भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन और भवन निर्माण" विषय पर 5 दिवसीय अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जे.के. प्रसाद, ए.के. तिवारी।
- सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित "संस्थागत पद्धतियां" विषय पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ए.के. तिवारी, एस.एम. मल्होत्रा।
- 22–23 सितम्बर, 2006, सी.डी.सी., नई दिल्ली में क्यूई.–प्रो–साफ्टवेयर के इस्तेमाल द्वारा "गुणवत्ता आकलन, दर विश्लेषण और बिल्डिंग प्लान्स से परियोजना प्लानिंग" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला असदिन्द कुमार।
- 6 अक्टूबर, 2006 को आई.एस.टी.डी., नई दिल्ली में "निर्माण उद्योग में मानव संसाधन पद्धतियां और परामर्श" विषय पर ई.डी.पी. आई.जे.एस. सिंहू।
- 11–12 अक्टूबर, 2006 को नई दिल्ली में "कृषि–वनविद्या और काष्ठ आधारित उद्योगों के समेकन के माध्यम से ग्रामीण विकास" विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आर.के. सैली, जे.के. प्रसाद, आई.जे.एस. सिंहू एस.के. गुप्ता, डी.पी. सिंह।
- 17–20 अक्टूबर, 2006 को सेन्ट्रल सोयल एण्ड मेट्रीरियल रिसर्च स्टेशन, नई दिल्ली द्वारा आयोजित जल संसाधन सेक्टर परियोजनाओं के लिए डी.पी.आर. तैयार करना" विषय पर चार दिवसीय कार्यशाला आई.जे.एस. सिंहू।
- 20–22 अक्टूबर, 2006 नई दिल्ली में "भौतिक अवसंरचना का विकास – सीनर्जी अप्रोच" विषय पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन आई.जे.एस. सिंहू।
- 24 अक्टूबर, 2006 को मिजोरम में बी.एम.टी.पी.सी. द्वारा "टाउन और कन्ट्री प्लानिंग एवट, जोनिंग रेग्युलेशन, विकास एवं नियंत्रण विनियम और प्राकृतिक खतरों के प्रति सुरक्षा के लिए निर्माण विनियम में मॉडल संशोधनों विषय पर तकनीकी कार्यशाला आयोजित की गई जे.के. प्रसाद

- 27 अक्टूबर, 2006 को परिषद के आई.एच.सी. कार्यालय में आयोजित, बी.एम.टी.पी.सी. के अधिकारियों की आंतरिक क्षमता निर्माण के लिए बी.एस.यू.पी. पर एक दिवसीय कार्यशाला आई.जे.एस. सिद्ध।
- 28 अक्टूबर, 2006 को भुवनेश्वर में म्युनिसिपल पदाधिकारियों के लिए "जे.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत बी.एस.यू.पी. के लिए डी.पी.आर. तैयार करना और मूल्यांकन करना" विषय पर कार्यक्रम आई.जे.एस. सिद्ध।
- 30-31 अक्टूबर, 2006 को "अधिक ऊंचाई के भवन: सामग्रियां और पद्धतियां" विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन जे.के. प्रसाद।
- 31 अक्टूबर, 2006 को एच.एस.एम.आई. में "शहरी विकास प्रबंधन: परिप्रेक्ष्य और संभावनाएं" विषय पर और एच.एस.एम.आई., नई दिल्ली द्वारा आयोजित "लागत प्रभावी और पर्यावरण-अनुकूल निर्माण सामग्रियां तथा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना – बी.एम.टी.पी.सी. के प्रयास और अनुभव" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आर.के. सैली, आई.जे.एस. सिद्ध।
- 2-3 नवम्बर, 2006, नई दिल्ली में "संविदा प्रबंधन का कानूनी पक्ष – मध्यस्थता और विवाद निपटान तंत्र" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आई.जे.एस. सिद्ध।
- नवम्बर, 2006 से जनवरी, 2007 तक "इंटरनेट के युग में बौद्धिक सम्पदा अधिकार और सूचना प्रौद्योगिकी" विषय पर तीन महीने का ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आर.के. सैली, एस.के. गुप्ता, डॉ. अमित राय।
- 6-8 नवम्बर, 2006 को नई दिल्ली में "ऐतिहासिक निर्माण का संरचनात्मक विश्लेषण" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आर.के. सैली, एस.के. गुप्ता।
- 15-17 नवम्बर, 2006 को आई.एच.सी., नई दिल्ली में "डिजाइन और निर्माण में सूचना प्रौद्योगिकी" विषय पर विश्व स्तरीय सम्मेलन अरविन्द कुमार।
- 17-18 नवम्बर, 2007 को हैदराबाद में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा आयोजित आवास मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आर.के. सैली, आई.जे.एस. सिद्ध।
- 23 नवम्बर, 2006 को कोहिमा, नागालैंड में बी.एम.टी.पी.सी. द्वारा "ठाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग एक्ट, जोनिंग रेग्यूलेशन, विकास और नियंत्रण विनियमन एवं प्राकृतिक खतरों के प्रति सुरक्षा हेतु निर्माण विनियम में मॉडल संशोधन" विषय पर तकनीकी कार्यशाला आयोजित की गई आर.के. सैली, जे.के. प्रसाद।
- नवम्बर, 2006 में अपने "निर्माण प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय नेटवर्क" कार्यक्रम के अंतर्गत सप्ताह अशोक प्रौद्योगिकीय संस्थान (साटी), विदिशा, मध्य प्रदेश के सहयोग से अभिनव प्रौद्योगिकियों का फील्ड अनुप्रयोग" विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आई.जे.एस.सिद्ध।

- 13–16 दिसम्बर, 2006 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित "आवास एवं मानव अधिवास" विषय पर एशिया पेसेफिक मिनीस्ट्रीयल सम्मेलन..... आर.के. सैली, जे.के. प्रसाद, आई.जे.एस. सिंह, एस. बालाश्रीनिवासन, ए.के. तिवारी, एस.के. गुप्ता /
- 7–9 दिसम्बर, 2006 को मुम्बई में इंडिया टैक फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'कंस्ट्रू इंडिया-2006' सम्मेलन व प्रदर्शनी आई.जे.एस. सिंह /
- 15–16 दिसम्बर, 2006 को रायपुर में "ग्रीन बिल्डिंग" विषय पर मध्यावधि सत्र व संगोष्ठी पंकज गुप्ता /
- 18–20 दिसम्बर, 2006 को रुड़की में "भूकम्प इंजीनियरी 13 एस.ई.ई.-06" विषय पर 13वीं विचार गोष्ठी जे.के. प्रसाद, सी.एन. झा /
- 18–22 नवम्बर, 2006 को आई.एस.टी.एम., नई दिल्ली में जेण्डर मुद्दों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम रिछपाल सिंह /
- 23 दिसम्बर, 2006 को "सूचना साक्षरता" विषय पर एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला अरविन्द कुमार, आलोक भट्टनागर /
- 5 जनवरी, 2007 को नई दिल्ली में "भारत में भूकम्प इंजीनियरिंग शिक्षा: लुकिंग एहैड" विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आर.के. सैली, जे.के. प्रसाद /
- 5–6 जनवरी, 2007 को बंगलौर में म्युनिसिपल पदाधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आई.जे.एस. सिंह /
- 8–12 जनवरी, 2007 को वैल्लोर में "प्राकृतिक आपदाओं से सीख – नीतिगत मुद्दे और अल्पीकरण रणनीतियां" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय गोल मेज बैठक..... आर.के. सैली /
- 8–12 जनवरी, 2007 को नई दिल्ली में आई.आई.टी., रुड़की के साथ संयुक्त रूप से परिषद द्वारा "कार्य-निष्पादन आधारित डिजाइन और भवनों तथा इमारतों की रैट्रोफिटिंग" विषय पर पांच दिवसीय अल्पकालिक प्रमाणपत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जे.के. प्रसाद, डी.पी. सिंह /
- 11–12 जनवरी, 2007 को पटना में म्युनिसिपल पदाधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आई.जे.एस. सिंह /
- 15–16 जनवरी, 2007 को कोलकाता में म्युनिसिपल पदाधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आई.जे.एस. सिंह /
- 17–18 जनवरी, 2007 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लयर में जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत, "प्राकृतिक खतरों के प्रति सुरक्षा और परियोजना विकास के लिए निर्माण उप-नियम" विषय पर दो

दिवसीय कार्यशाला आर.के. सैली, जे.के. प्रसाद, आई.जे.एस. सिंह
एस.के. गुप्ता /

- 19 जनवरी, 2007 को नई दिल्ली में "ऊर्जा दक्ष उपकरणों के इस्तेमाल में अद्यतन प्रवृत्ति" विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन आकाश कुमार
मथुरा /
- 22 और 23 जनवरी, 2007 को कोलकाता में कार्यक्रम साझेदार - डॉ.
फीकिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन एण्ड रिहेबिलीटेशन के
सहयोग से "वाटर प्रूफिंग एण्ड डम्प प्रूफिंग मेटरीरियल्स एण्ड टेक्नीक्स
फॉर बिल्डिंग्स एण्ड स्ट्रक्चर्स" विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
. जे.के. प्रसाद, अरविन्द कुमार /
- 23 जनवरी, 2007 को चंडीगढ़ में म्युनिसिपल पदाधिकारियों के लिए
क्षमता निर्माण कार्यक्रम आई.जे.एस. सिंह /
- जनवरी, 2007 में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
जालंधर, पंजाब में "सुरक्षित ढांचागत पद्धतियां" विषय पर संवेदीकरण
संगोष्ठी डी.पी. सिंह /
- 1 फरवरी, 2007 को दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली में आयोजित
"लाइफलाइन बिल्डिंग्स की रेट्रोफिटिंग के लिए मुद्दे और नीतियां" विषय
पर एन.आई.डी.एम. कार्यशाला जे.के. प्रसाद, पंकज गुप्ता /
- 5-9 फरवरी, 2007 को आई.एस.टी.एम., नई दिल्ली में "संगठन और
पद्धतियां" विषय पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ए.के. तिवारी, एस.एम.
मल्होत्रा /
- 10 फरवरी, 2007 को नई दिल्ली में "इंडो-पाकिस्तान व्यवसाय सहयोग" ..
.... आई.जे.एस. सिंह /
- 16 फरवरी, 2007 को सिविकम, गंगटोक में जे.एन.एन.यू.आर.एम. के
अंतर्गत, प्राकृतिक खतरों के प्रति सुरक्षा और परियोजना विकास के लिए
निर्माण उप-नियमों पर एक दिवसीय कार्यशाला आर.के. सैली, जे.के.
प्रसाद /
- 19-22 फरवरी, 2007 को जयपुर में आवास सहकारी समितियों के वरिष्ठ
कार्मिकों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम एस.के. गुप्ता /
- फरवरी, 2007 में भुवनेश्वर में जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत भुवनेश्वर
नगर निगम और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा
आयोजित "बी.एस.यू.पी. और आई.एच.एस.डी.पी. के लिए परियोजना
विकास" विषय पर जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यशाला आई.जे.एस. सिंह /
- 12 मार्च, 2007 को रांची (झारखण्ड) में "टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग एक्ट,
जोनिंग रेग्यूलेशन, विकास और नियन्त्रण विनियमन एवं प्राकृतिक खतरों के

प्रति सुरक्षा हेतु निर्माण विनियम में मॉडल संशोधन” विषय पर तकनीकी कार्यशाला आयोजित की गई जे.के. प्रसाद/

- 16–17 मार्च, 2007 को नई दिल्ली में “जे.एन.एन.यू.आर.एम.: डवलपिंग इन्कलुसिव सिटीज” विषय पर राष्ट्रीय परामर्श आई.जे.एस. सिद्ध एस. के. युक्ता/
- 23 मार्च, 2007 को परिषद् ने निर्माण विकास अनुसंधान संस्थान, रायपुर के साथ संयुक्त रूप से, रायपुर के निकट ग्रामीण क्षेत्रों के 30 राजमिस्त्रियों की क्षमता निर्माण के लिए एक महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।
- 28–29 मार्च, 2007 को “खांचा विहीन प्रौद्योगिकी के माध्यम से शहरी नवीकरण के लिए क्षमता निर्माण” विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आई.जे.एस. सिद्ध/
- 27–28 मार्च, 2007 को नई दिल्ली में “विशेषज्ञों के लिए लागत और मूल्य निर्धारण” विषय पर दो दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम..... डी.पी. सिंह/

III भारतीय मानक ब्यूरो की समितियां

- बी आई एस में 6 जुलाई, 2006 को सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन कार्डिसिल (सी ई डी सी) की 12वीं बैठक जे.के. प्रसाद/
- 11 अगस्त, 2007 को भूकम्प इंजीनियरिंग तकनीकी समिति, सी.ई.डी.39 की बी आई एस बैठक जे.के. प्रसाद/
- 23 नवम्बर, 2006 को नई दिल्ली में “निर्माण परियोजना प्रबंधन” विषय पर समिति की बी आई एस बैठक। बी एम टी पी सी को निर्माण परियोजना प्रबंधन पर बनाए गए कार्य दल के एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया आई.जे.एस. सिद्ध/
- 2 फरवरी, 2007 को भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली में आयोजित की गई, सुरक्षा प्रबंधन सहित निर्माण प्रबंधन समिति की बी आई एस बैठक आई.जे.एस. सिद्ध/

IV तकनीकी समिति/कार्य दल आदि

- 3 अप्रैल, 2006 को, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के उप मंत्री महामहिम नटोपाइले क्गान्यागों के साथ बैठक आर.के. सैली/
- 8 अप्रैल, 2006 को हुडको में निम्न लागत आवास प्रतियोगिता (शहरी) 2005–06 के लिए बैठक आर.के. सैली/

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए) द्वारा देश में आपदा प्रबंधन पर रणनीतिक पेपर तैयार करने के संबंध में एन डी एम ए की बैठक। भूकम्प के विभिन्न जोनों में पड़ने वाले जिलों तथा बहुविध खतरे वाले जिलों की सूची, उसकी रिपोर्ट में शामिल करने के लिए एन डी एम ए को उपलब्ध कराई गई आर.के. सैली।
- 10 अप्रैल, 2006 को, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में गुणवत्ता आश्वासन पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में श्री सी.वी. शंकर के साथ बैठक..... आर.के. सैली।
- 18 अप्रैल, 2006 को बी एम टी पी सी के करार बोर्ड (पी ए सी) की बैठक आर.के. सैली, जे.के. प्रसाद, ए.के. तिवारी।
- 24 अप्रैल, 2006 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित सिविकिम के माइक्रोजोनेशन पर बैठक आर.के. सैली, जे.के. प्रसाद।
- 27 अप्रैल, 2006 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अवसर पर आयोजित की गई बैठक..... आर.के. सैली।
- 3 मई, 2006 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक..... आर.के. सैली।
- 5 मई, 2006 को निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा गठित सूचना प्रौद्योगिकी कार्य दल की बैठक आई.जे.एस. सिंह।
- 6 मई, 2006 को हुड्को द्वारा "आवास एवं मानव अधिवास के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्टता के लिए अवार्ड" के लिए जूरी की बैठक आई.जे.एस. सिंह।
- 6 मई, 2006 को बंगलौर में बी एम टी पी सी द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं की संचालन समिति की बैठक..... आर.के. सैली।
- 20 मई, 2006 को सी आई डी सी में निर्माण उद्योग के सूचना प्रौद्योगिकी दल की बैठक..... आर.के. सैली।
- 28 मई, 2006 को वेनेजुएला के उप विदेश मंत्री के साथ आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन राज्य मंत्री की बैठक आर.के. सैली।
- 6 जून, 2006 को निर्माण भवन में, भारत में मोजाम्बिक के राजदूत श्री कारलॉस अगोस्टीन्हो के साथ बैठक आर.के. सैली।
- 6 जून, 2006 को नई प्रौद्योगिकियों पर मैक्रिसको से आए श्री अल्वारेक के साथ बैठक आर.के. सैली।
- 7 जून, 2006 को सेनेगल के दूतावास के वाणिज्य दूत (आर्थिक) श्री शेकन डिआलो के साथ बैठक आर.के. सैली।

- 19 जून, 2006 को एस.ई.आर.सी., चेन्नई में, सी.एस.आई.आर. के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए "आवास, सड़क एवं निर्माण" विषय पर पहली सैकटोरल बैठक आर.के. सैली।
- 28 जून, 2006 को बी एम टी पी सी की पी ए सी पर तकनीकी आकलन समिति की बैठक आर.के. सैली, ए.के. तिवारी।
- 14 जुलाई, 2007 को नई दिल्ली में विकास विकल्पों द्वारा आयोजित "ग्रीनिंग ऑफ ब्रिक इंडस्ट्री" की परियोजना संचालन समिति की तीसरी बैठक आई.जे.एस. सिंह।
- 17 जुलाई, 2007 को शहरी विकास मंत्रालय में परामर्श समिति की बैठक आर.के. सैली, आई.जे.एस. सिंह।
- नई निर्माण परियोजनाओं और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरण स्वीकृति समिति की बैठक आई. जे.एस. सिंह।
- जे एन एन यू आर एम के बी एस यू पी और आई एच एस डी पी के अन्तर्गत प्राप्त परियोजनाओं पर समीक्षा बैठकों की सीरीज आई. जे. एस. सिंह।
- 3 अगस्त, 2006 को सी आई डी सी द्वारा "डिजाइन और निर्माण में सूचना प्रौद्योगिकी" के विश्व स्तरीय समेलन पर संचालन समिति की बैठक आई. जे.एस. सिंह।
- 22 अगस्त, 2006 को एन डी ए, दिल्ली में भू-स्लखन दिशानिर्देशों पर बनाए गए कोर ग्रुप की बैठक आर.के. सैली।
- 13 सितम्बर, 2006 को दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक आर.के. सैली।
- 15 सितम्बर, 2006 को संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने बी एम टी पी सी में सरकारी कार्य में राजभाषा के इस्तेमाल का निरीक्षण किया और उसकी समीक्षा की। समिति के सदस्य, की गई प्रगति से संतुष्ट थे आर.के. सैली।
- 10 अक्टूबर, 2006 को कोमेसा प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक आर.के. सैली।
- 27 अक्टूबर, 2006 को आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के एम सी आर एच आर डी इंस्टीट्यूट में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा आयोजित आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति निर्धारण पर चर्चा आर.के. सैली।
- 31 अक्टूबर, 2006 को सी बी आर आई, रुड़की में उड़न राख उपयोग कार्यक्रम, टी आई एफ ए सी द्वारा प्रायोजित "मिट्टी उड़न राख ईंटों के विनिर्माण के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी उड़न राख मिश्रण का

- इष्टम इस्तेमाल करने हेतु अंकगणितीय मॉडलिंग" परियोजना की मानीटरिंग समिति की बैठक जे.के. प्रसाद/
- 31 अक्टूबर, 2006 को शहरी विकास पर संसद की स्थायी समिति की बैठक आर.के. सैली, आई.जे.एस.सिद्धू/
 - 4 नवम्बर, 2006 को अभिनव प्रौद्योगिकियों पर रसी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक आर.के. सैली/
 - 15 नवम्बर, 2006 को सी बी आर आई, रुड़की में "नए भवन निर्माण और प्रौद्योगिकियों का विकास" की परियोजना पर मानीटरिंग समिति की बैठक आर.के. सैली/
 - नवम्बर, 2006 में सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में "ग्रामीण आवास और ग्रामीण आवास नीति के प्रारूप पर कार्यदल" की बैठक आई.जे.एस. सिद्धू एस.के. गुप्ता/
 - 2 फरवरी, 2007 को सचिव, शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा गठित, शहरी विकास पर इंडो-फ्रांस कार्य दल की बैठक। आपदा के प्रति तैयारी और अल्पीकरण में क्षमता निर्माण हेतु बी आर जी एम परियोजनाओं पर चर्चा की गई आई.जे.एस. सिद्धू/
 - 12 फरवरी, 2007 को संयुक्त सचिव (आवास) की अध्यक्षता में हुई "किफायती आवास" विषय पर बैठक आर.के. सैली, आई.जे.एस. सिद्धू/
 - 12 फरवरी, 2007 को सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में हुई "ग्रामीण आवास और ग्रामीण आवास नीति के मसौदे पर कार्य दल" की बैठक आई.जे.एस. सिद्धू/
 - 27 फरवरी, 2007 को राष्ट्रीय बांस मिशन की संचालन समिति की पहली बैठक आर.के. सैली/
 - 7 मार्च, 2007 को जे एन यू आर एम के अंतर्गत दिल्ली सरकार की बी एस यू पी परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, सचिव, शहरी विकास और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ बैठक आर.के. सैली, आई.जे.एस. सिद्धू/
 - 13 मार्च, 2007 को, मई 2007 में आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय संगोष्ठी पर इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की संचालन समिति की बैठक आई.जे.एस. सिद्धू/
 - 28 मार्च, 2007 को आई एच सी में बेल्जियम के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक आर.के. सैली/

- आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की 11वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने के लिए बैठकों की शृंखला आर.के. सैली, आई.जे.एस. सिंहू।
- जे एन एन यू आर एम की केन्द्रीय स्वीकृति एवं मानीटरिंग समिति की बैठकों की शृंखला।
- आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के साथ उत्पाद तथा सीमा शुल्क की छूट के लिए बैठकों की शृंखला।
- बी.एम.टी.पी.सी. की परियोजना संवीक्षा समिति की बैठकों की शृंखला।
- वैष्णे की बी एम टी पी सी परियोजना मानीटरिंग समिति की बैठकों की शृंखला।

V अन्य कार्यकलाप

- 2 से 6 फरवरी, 2007 तक हैदराबाद, मुम्बई और गोवा में शहरी विकास पर बनी स्थायी संसदीय समिति (2006-07) का तत्काल अध्ययन दौरा।
- 21 दिसम्बर, 2006 को बी एम टी पी सी के प्रबंधन मंडल की 7वीं बैठक आयोजित की गई।
- 21 दिसम्बर, 2006 को बी एम टी पी सी की कार्यकारिणी की 25वीं बैठक आयोजित की गई।
- बी एम टी पी सी ने एन डी एम ए द्वारा देश में आपदा प्रबंधन पर रणनीतिक पेपर तैयार करने के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए) की बैठक में भाग लिया और उसकी रिपोर्ट में शामिल करने के लिए एन डी एम ए को भूकम्प के विभिन्न जोनों में पड़ने वाले जिलों और बहुविध खतरे वाले जिलों की सूची उपलब्ध कराई।
- बी एम टी पी सी ने 29 जून, 2006 को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। सचिव (आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन) ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की अध्यक्षता की। डॉ. सी.एस. वैकटारमन, निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली ने "संगठनात्मक प्रभावीपन के लिए लोगों का सशक्तीकरण" विषय पर एक अतिथीय भाषण दिया। इस समारोह में मंत्रालय के और मंत्रालय के अधीन विभागों/ संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया।
- बी एम टी पी सी ने अगस्त, 2006 में, अभिनव निर्माण सामग्री और निर्माण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में, डी एस आई डी सी के ठेकेदारों के लिए एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।
- बी.एम.टी.पी.सी. के कार्यकारी निदेशक को दिनांक 26 सितम्बर, 2006 को, एस.ई.आर.सी., चेन्नई में सी.एस.आई.आर. के स्थापना दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्होंने इस अवसर पर "किफायती घर" विषय पर एक भाषण दिया।

- परिषद में आई एस ओ 9000 के अनुसार गुणवत्ता प्रणाली कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण संस्थान (आई आई ई सी) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पार्क (एस टी पी) की साझेदारी में पीम्परी चिंचवाड नगर निगम (पी सी एम सी), स्थायी निर्माण प्रौद्योगिकी केन्द्र (एम बी टी सी) की स्थापना कर रहा है जो वैकल्पिक निर्माण तकनीकों, पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने, उनकी शिक्षा देने और उनका परीक्षण करने के लिए एक हब के रूप में काम करेगा। एक आमंत्रित सदस्य के रूप में, बी एम टी पी सी ने, स्थायी समिति हाल, पीम्परी चिंचवाड नगर निगम में 22 फरवरी, 2007 को, कार्यात्मक आवश्यकताओं, केन्द्र की कार्य प्रणाली का प्रचालन का पता लगाने के लिए आयोजित की गई चर्चा में भाग लिया।
- आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के 11वीं योजना के प्रलेख के लिए, "लागत प्रभावी निर्माण तकनीकों और आपदा अल्पीकरण को बढ़ावा देना" विषय पर एक अध्याय का मसौदा तैयार किया।
- शहरी विकास मंत्रालय की 11वीं योजना के लिए प्रौद्योगिकी पर एक अध्याय का मसौदा तैयार किया।
- 1997 में भारत में पहली बार बी एम टी पी सी द्वारा, भारत में विनिर्मित मशीनरी और उपकरणों की एक डायरेक्टरी निकाली गई थी। डायरेक्टरी का दूसरा संस्करण 2001 में निकाला गया। इस डायरेक्टरी के तीसरे संस्करण का संकलन किया जा रहा है।
- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जी एन आई डी ए) द्वारा निर्मित की जाने वाली 1848 इ.डब्ल्यू.एस. आवास यूनिटों के लिए मैसर्स अधलखा एण्ड एसोसिएट्स द्वारा तैयार किए गए आकलन का पुनरीक्षण, जनवरी 2007 में जी एन आई डी ए की आवश्यकता के अनुसार एक तीसरे पक्ष के रूप में परिषद द्वारा किया गया।

वर्ष के दौरान पूरे किए गए प्रायोजित अध्ययन / परियोजनाएं

क. पूरे किए गए प्रायोजित अध्ययन

1. दिल्ली और हैदराबाद में उड़न राख ईटों / ब्लॉकों का बाजार सर्वेक्षण।
2. बलरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया तैयार करना।
3. प्राकृतिक आपदाओं के प्रति असुरक्षित 19 जोनों के लिए आवास डिजाइन तैयार करना।
4. छत के लिए अनुप्रयोग हेतु बांस चटाई रिज कैप का विकास।
5. जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षित निर्माण के लिए पोस्टर और पुस्तिका तैयार करना।

ख. पूरी कर ली गई परियोजनाएं

1. बेलगांव, कर्नाटक में प्रौद्योगिकी प्रदर्शन व उत्पादन केन्द्र स्थापित करना।
2. हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड, नई दिल्ली में निर्माण उपकरणों का उत्पादन आधार सुदृढ़ करना।
3. कुपवाड़ा, जम्मू एवं कश्मीर में उप-जिला अस्पताल की रेट्रोफिटिंग।
4. वसन्त विहार, नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम के स्कूल के भवन की रेट्रोफिटिंग।
5. नई दिल्ली में बांस आधारित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके प्रदर्शन इमारतों का निर्माण।
6. विदिशा, मध्य प्रदेश में स्थायी प्रदर्शनी स्थापित करना।
7. स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्चाइटेक्चर, नई दिल्ली में स्थायी प्रदर्शनी स्थापित करना।

वर्ष के दौरान आरम्भ की गई प्रायोजित परियोजनाएं, अध्ययन और वीडियो फ़िल्में

क. वर्ष के दौरान आरंभ किए गए प्रायोजित अध्ययन

1. भू-गर्भीय जलवायु विषयक और भौगोलिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धन व्यक्तियों के लिए किफायती घरों हेतु टेम्पलेट्स तैयार करना।
2. बांस की चटाई की लहरदार चादरों से छत बनाने के लिए बांस की चटाई की रिज कैप के उत्पादन में औद्योगिक स्तरोन्नयन।
3. बांस की चटाई के मशीनीकृत उत्पादन हेतु प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं इच्यूबैशन केन्द्र स्थापित करना।
4. फ्लेटेड बैम्बू कम्पोजिट और लेमीनेटेड बैम्बू लम्बर उत्पादों का विकास।
5. कंकरीट में इसके इस्तेमाल पर मार्बल स्तरी / मार्बल डस्ट के निपटान के पर्यावरणीय प्रभावों पर अध्ययन।
6. ग्रेनाइट उद्योग के अपशिष्ट से निर्माण संघटकों का विकास।
7. साव बद्ध उड़नराख से मूल्यवृद्धि निर्माण सामग्रियों के विकास हेतु बड़ा संयंत्र स्थापित करना।
8. प्रीफेब उपकरणों के विनिर्माण हेतु मशीनों का उन्नयन।
9. लागत प्रभावी और आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों पर उत्तराखण्ड में राज मिस्त्रियों, बढ़इयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
10. बवाना में औद्योगिक वर्कर्स आवास परियोजना का दस्तावेज।

ख. वर्ष के दौरान परिषद से प्राप्त वित्तीय सहायता से आरम्भ की गई परियोजनाएं

1. वायांडु, केरल में जनजातीय लोगों के लिए मैट वीविंग सेंटर स्थापित करना।
2. छत्तीसगढ़ में बांस आधारित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके प्रदर्शन गृहों का निर्माण।
3. भूकम्पीय सुदृढीकरण के लिए दिल्ली नगर निगम के स्कूल की 4 बिल्डिंगों की रेट्रोफिटिंग।
4. नागार्लैंड में बांस आधारित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके प्रदर्शन इमारतों का निर्माण।
5. मेघालय में बांस आधारित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके प्रदर्शन इमारतों का निर्माण।

6. स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्चीटेक्चर, नई दिल्ली में स्थायी प्रदर्शनी का निर्माण।
7. उत्तरांखण्ड, छत्तीसगढ़ और कोहिमा में निर्माण केन्द्र के उत्पादन का सुदृढ़ीकरण।

ग. वीडियो फिल्में

1. वैष्णे के अंतर्गत प्रदर्शन आवास परियोजना पर फिल्म।

प्रस्तुत किए गए/प्रकाशित किए गए पेपर

- i. 13–16 दिसम्बर, 2006, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा आयोजित एशिया पेसेफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान “स्थायी विकास के लिए ग्रीन बिल्डिंग प्रौद्योगिकियां” शीर्षक वाला तकनीकी पेपर आर.के. सैली, जे.के. प्रसाद, एस.के. गुप्ता।
- ii. टाइम्स जर्नल ऑफ कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन में छपा “निर्माण सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों में नवीनता” शीर्षक वाला लेख आर.के. सैली, जे.के. प्रसाद।
- iii. 15–16 दिसम्बर, 2006 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में आई.बी.सी. द्वारा “ग्रीन बिल्डिंग्स” विषय पर आयोजित की गई राष्ट्रीय संगोष्ठी में “बांस: भवन और आवास के लिए एक उपयुक्त सामग्री” विषय पर पेपर जे.के. प्रसाद, पंकज गुप्ता।
- iv. जनवरी, 2007 में टाइम्स जर्नल ऑफ कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन में छपा, कंकरीट की मजबूती पर लेख जे.के. प्रसाद।
- v. मार्च, 2007 में टाइम्स जर्नल ऑफ कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन में छपा, स्थायी पर्यावास के लिए ग्रीन बिल्डिंग प्रौद्योगिकियों पर लेख आर.के. सैली, जे.के. प्रसाद, एस.के. गुप्ता।
- vi. 12–17 फरवरी, 2007 के दौरान आयोजन स्कूल ऑफ आर्चिटेक्चर, जयपुर में प्रशिक्षण व कार्यशाला कार्यक्रम, “वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया और खतरे कम करने के उपाय” विषय पर पेपर डी.पी. सिंह।
- vii. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर में “सुरक्षित ढांचागत पद्धतियां” विषय पर संवेदीकरण संगोष्ठी, निर्माण के असुरक्षितता के पहलुओं पर पेपर डी.पी. सिंह।
- viii. विश्व पर्यावास दिवस 2006 को, बिल्डिंग मेटीरियल न्यूज में छपा, “निर्माण परियोजनाओं में टीम वर्क” विषय पर लेख जे.के. प्रसाद, ए.के. तिवारी।
- ix. विश्व पर्यावास दिवस 2006 को, बिल्डिंग मेटीरियल न्यूज में छपा, “ऊंचे भवनों में सुरक्षा” विषय पर लेख आई.जे.एस. सिद्ध आकाश माथुर।
- x. 16–17 नवम्बर, 2006 को हैदराबाद में आवास मन्त्रियों के सम्मेलन में “हाउसिंग स्टॉक का खतरा आकलन – वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया” विषय पर लेख आई.जे.एस. सिद्ध।

वर्ष के दौरान निकाले गए प्रकाशन

1. वलरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया (पहला संशोधन: 2006)
2. नेपाल और भूटान पर सूचना के साथ, भारतीय निर्माण सामग्रियों और उत्पादों की डायरेक्टरी – सातवां संस्करण: 2006
3. विश्व पर्यावास दिवस 2006 पर "सिटीज – मेगनेट्स ऑफ होम्स" विषय पर बिल्डिंग मेटीरियल न्यूज का विशेष अंक।
4. वलरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया के परिचय पर प्रपत्र
5. बी एम टी पी सी की बहु-आयामी पहलों पर प्रपत्र।
6. "आवास एवं भवन निर्माण में बांस – बी एम टी पी सी की पहलें" विषय पर प्रपत्र।
7. भूकम्प के प्रति सुरक्षा के लि, कुपवाड़ा, जम्मू एवं कश्मीर में अस्पताल की रेट्रोफिटिंग विषय पर प्रपत्र।
8. जम्मू एवं कश्मीर के लिए, "भूकम्प सुरक्षा के प्रति सरल तरीके" विषय पर अंग्रेजी और उर्दू में पुस्तिका और पोस्टर।

अन्य देशों से आए महत्वपूर्ण आगन्तुक

1. भारत में मोजाम्बिक गणराज्य के उच्चायुक्त श्री कारलोस अगोस्टीन्हो डो रोजारियो।
2. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के उप मंत्री महामहिम नृटेपाइले क्लगान्यार्गो।
3. सेनेगल दूतावास के वाणिज्य दूत (आर्थिक) श्री शेक्न डिआलो।
4. श्री राज केन्त, के. पैक (कीनिया) लिमिटेड, नैरोबी, कीनिया।
5. श्री गेने मैक ग्लीन्स, सहायक सचिव, आस्ट्रेलियन ग्रीन हाउस कार्यालय, आस्ट्रेलिया सरकार, कैन्बरा, आस्ट्रेलिया।
6. श्री पॉल स्कवेजल्स, वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक, यू.एस. पर्यावरणीय संरक्षण एजेंसी, यू.एस.ए.।
7. यूनिडो, रूस का प्रतिनिधिमंडल।
8. नेपाल का प्रतिनिधिमंडल।
9. दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधिमंडल।
10. बैल्जियम का प्रतिनिधिमंडल।
11. आई सी एफ कंसल्टिंग, यू.एस.ए. का प्रतिनिधिमंडल।

वर्ष 2007-08 के लिए कार्य-योजना

अभिनव और पर्यावरण-अनुकूल निर्माण सामग्रियों तथा निर्माण प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में बी.एम.टी.पी.सी. ने परिषद् के मैंडेट में दिए गए बहु-आयामी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनेक कार्यकलाप आरम्भ किए हैं। पिछले वर्ष में परिषद् ने अभिनव, लागत-प्रभावी, पर्यावरण-अनुकूल और ऊर्जा दक्ष निर्माण सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के विकास तथा संवर्द्धन पर ध्यान केन्द्रित किया है। तथापि, अब आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के सक्रिय समर्थन से परिषद् ने वैम्बे योजना, जिसका विलय अब जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अन्तर्गत समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के साथ हो गया है, के अंतर्गत आवास परियोजनाओं को कार्यान्वित करके अभिनव निर्माण सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों का फील्ड स्तरीय अनुप्रयोग आरम्भ कर दिया है।

परिषद् पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों में प्रदर्शन इमारतों के निर्माण और बम्बू मैट उत्पादन केन्द्रों को स्थापित करके बांस-आधारित निर्माण सामग्री प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रोत्साहन करने की कोशिश कर रही है। परिषद् की वर्ष 2007-08 की कार्य-योजना इस तरीके से बनाई गई है कि इसमें केवल परिषद् के विभिन्न प्रचालनात्मक क्षेत्रों पर ही ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया है बल्कि यह सामाजिक लाभों के साथ प्रत्यक्ष परिणाम भी दर्शाती है।

वर्ष 2007-08 के दौरान जिन विभिन्न कार्यकलापों को परिषद् आरम्भ करने पर विचार कर रही है, वे आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों, प्रौद्योगिकी विकास/ संवर्द्धन और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, निर्माण एवं प्रसार के प्रचालनात्मक क्षेत्रों के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

क. प्रौद्योगिकी विकास/ संवर्द्धन

1. हरित पर्यावास के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार करना

हरित पर्यावास के लिए दिशानिर्देश (जी.जी.एच.) बनाने हेतु अपनाए जाने वाले तरीकों पर चर्चा करने के लिए आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा गठित किए गए हरित पर्यावास के लिए दिशानिर्देश (जी.जी.एच.) बनाने हेतु गठित किए गए कार्य दल की पहली बैठक फरवरी, 2007 में आयोजित की गई। इस वर्ष के दौरान, किए गए मौजूदा कार्य के आंकड़ों/सूचना का एकत्रीकरण, एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण, उपयोगी आंकड़ों/ सूचना की पहचान, आंकड़ों में कमी का पता लगाने और अंतरिम रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने का कार्य किया जाएगा।

2. अभिनव निर्माण सामग्री प्रौद्योगिकियों पर तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना

परिषद् ने पहले ही कुछ प्रौद्योगिकियां अंतरित कर दी हैं, चाहे वे पायलट प्लांट स्केल के लिए हों या वाणिज्यिक स्तरों पर उत्पादन के लिए। परन्तु बी.एम.टी.पी.सी. की वेबसाइट के प्रत्युत्तर में बड़ी संख्या में पृच्छाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें विशिष्ट परियोजना / व्यवहार्यता रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है। ये पृच्छाएं भारतीय उद्यमियों तथा विदेशों, दोनों से प्राप्त हो रही हैं। इसलिए, यह प्रस्ताव दिया जाता है कि निवेश और उत्पादन के विभिन्न स्तरों के लिए 12 अभिनव और लागत-प्रभावी प्रौद्योगिकियों पर तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जाएं।

3. फ्लक्स बाउंडेड फ्लाई ऐश बिल्डिंग कम्पोनेंट्स के विनिर्माण के लिए बड़ा संयंत्र स्थापित करना

यह प्रस्ताव अनुप्रयोग पर आधारित है, क्योंकि उच्च मात्रा वाले फ्लक्स बाउंडेड फ्लाई ऐश बिल्डिंग कम्पोनेंट्स में मूल्यवर्धन के लिए नानो टाइटेनियम आक्साइड पहले ही प्रयोगशाला में विकसित कर लिए गए हैं और अन्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रौद्योगिकीय व्यवहार्यता के लिए स्केल अप कर दिए गए हैं। इस प्रकार के उत्पादों का परिणाम मूल्य वर्धित संघटकों में होगा, क्योंकि कोटिंग्स फ्लाई ऐश बॉडीज एंटी एलगल, एंटी सॉयलिंग और एंटी बैक्टीरियल गुण-धर्म प्रदान करते हैं। 20-30 एनएम रेज के आकार में फोटो कैटलिटिक टाइटेनियम ऑक्साइड तैयार करने की प्रक्रिया को अनुसन्धान समूह द्वारा सफलतापूर्वक विकसित कर लिया गया है और एंटी-एलगल और एंटी सॉयलिंग गुण-धर्मों के प्रति इसकी अभिक्रिया को लागू किया गया है। वाणिज्यिक महत्त्व के उत्पादों पर अनुप्रयोग करने की दृष्टि से इस प्रक्रिया को बड़ी मात्रा में स्केल-अप किए जाने की आवश्यकता है।

इस परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- प्रतिभागी उद्योग की सहायता से फ्लक्स बाउंडेड हाई वॉल्यूम फ्लाई ऐश उत्पादों की पहले से उपलब्ध प्रक्रिया को स्केल-अप करना। ईंटें, फ्लोरिंग्स, वॉलिंग्स और बाह्य इस्तेमाल के लिए विशेष अनुप्रयोग के उत्पाद बनाए जाएंगे।
- उत्कृष्ट फोटो कैटलिटिक गुण-धर्म वाले जलय मार्ग से नानो टाइटेनिया के लिए प्रक्रिया को स्केल-अप करना और इसके बाद कोटिंग प्रिकर्सर का विकास करना। फ्लाई ऐश सरफेसों पर कोटिंग पर प्रयोगशाला के परीक्षणों के आधार पर कोटिंग प्रिकर्सरों को बनाया जाएगा। कोटिंग्स का इस्तेमाल प्रयोगशाला के प्रयोगों के अन्तर्गत और मारफोलॉजिकल परीक्षणों के अंतर्गत किया जाएगा।
- केरल में मैसर्स टेरा टाइल कंसोर्टियम में फ्लक्स बाउंडेड फ्लाई ऐश उत्पादों पर फोटो एक्टिव टाइटेनिया की कोटिंग्स विकसित करना और उनका प्रदर्शन करना। इस परियोजना में भाग लेने के लिए मैसर्स टेरा टाइल कंसोर्टियम ने सहमति प्रदान कर दी है।

4. तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना और प्रौद्योगिकी अंतरण।
4. निर्माण और डेमोलिशन के मलबे की रिसाइकिलिंग के लिए मशीनों का विकास

पुनर्निर्माण करते समय बड़ी मात्रा में निर्माण और डेमोलिशन अवशिष्ट सृजित होता है, जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक और मानवकृत आपदाएं आती हैं, जो इन अवशिष्टों के निपटान में गम्भीर समस्या उत्पन्न कर देती हैं। निर्माण और डेमोलिशन अवशिष्ट की रिसाइकिलिंग के लिए यूरोपीय देशों में प्रौद्योगिकियों को देश में ही बनाने की दृष्टि से समिति का प्रस्ताव है कि इन अवशिष्टों की रिसाइकिलिंग के लिए उपयुक्त मशीनें विकसित की जाएं।
5. ग्रेनाइट उद्योग के अपशिष्ट से टाइलों के विनिर्माण के लिए पायलट संयंत्र स्थापित करना

परिषद् आन्ध्र प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास निगम के सहयोग से ग्रेनाइट उद्योग के अवशिष्ट से टाइलों के विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी विकसित कर रही है। प्रयोगशाला के स्तर पर इस प्रौद्योगिकी ने उत्साहजनक परिणाम दर्शाए हैं। प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिकीकरण की दृष्टि से यह प्रस्ताव दिया गया है कि ग्रेनाइट उद्योग के अवशिष्ट से टाइलों के विनिर्माण हेतु एक पायलट संयंत्र स्थापित किया जाए। वाणिज्यिक मानदंड बनाए जाने के बाद इस प्रौद्योगिकी को इच्छुक उद्यमियों को अंतरित किया जाएगा।
6. आम भवन निर्माताओं के लिए आवास डिजाइन पैकेज का विकास करना

मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए और सैम्पल नक्शे, योजनाएं और आकलन से सम्बन्धित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए जनरल हाउस बिल्डर्स द्वारा बार-बार परिषद् का दौरा किया गया है। इस वर्ष के दौरान, परिषद् का प्रस्ताव है कि विभिन्न भू-गर्भीय जलवायु सम्बन्धी खतरे वाले जोनों में लागत-प्रभावी प्रौद्योगिकियों के लिए विभिन्न विकल्पों के साथ विभिन्न आकारों के घरों की योजनाएं और उनके आकलन तैयार किए जाएं।
7. प्लास्टिक अपशिष्ट की रिसाइकिलिंग के लिए प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिकीकरण

परिषद् ने अभी कुछ दिन पहले पैनलों और बोर्डों के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक अवशिष्ट की रिसाइकिलिंग हेतु एक प्रौद्योगिकी विकसित की है। इस प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिकीकरण करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि बड़े पैमाने पर पैनलों और बोर्डों के विनिर्माण हेतु वाणिज्यिक मानदंड बनाए जाएं। इसलिए, यह प्रस्ताव है कि प्लास्टिक अवशिष्ट की रिसाइकिलिंग हेतु प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिकीकरण करने के लिए एक परियोजना आरम्भ की जाए।

8. कृषि अपशिष्ट का इस्तेमाल करके सीमेंट बाउंडेड पार्टिकल्स बोर्ड के उत्पादन हेतु मध्यम स्तरीय विनिर्माण सुविधाओं का विकास

भारत में बड़े स्तर पर उत्पादन हेतु कृषि अपशिष्ट का इस्तेमाल करके सीमेंट बाउंडेड पार्टिकल बोर्डों के विनिर्माण हेतु प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। लघु और मध्यम स्तरीय उद्यमियों को ग्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सीमेंट के साथ कृषि अपशिष्ट बाउंडेड से पार्टिकल बोर्डों के विनिर्माण हेतु उपयुक्त संयंत्र और मशीनरी विकसित की जाए। इससे कृषि अपशिष्ट, जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, का बड़े पैमाने पर उपयोग करने में सहायता मिलेगी।

9. नई प्रौद्योगिकियों की पहचान करने और उन्हें अपनाने के लिए प्रौद्योगिकी मंच

यह प्रस्ताव दिया जाता है कि पूरे देश में नई अभिनव प्रौद्योगिकियों की पहचान करने, चयन करने और उन्हें अपनाने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जाए। इसके लिए एक डाटाबेस सृजित किया जाएगा, जो व्यवसायविदों, उद्यमियों और प्रौद्योगिकीविदों को सूचना प्रदान करने में सहायक होगा।

10. बाह्य अनुप्रयोग के लिए प्रदूषित शोषक परत के विनिर्माण हेतु एक प्रक्रिया का विकास

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि वायु/ शोर संबंधी प्रदूषण को कम करने के लिए बाह्य अनुप्रयोगों हेतु प्रदूषित शोषक परत के विनिर्माण हेतु एक स्वदेशीय प्रक्रिया विकसित की जाए।

11. कम लागत के क्योरिंग कक्षों का विकास

परिषद का प्रस्ताव है कि पूर्वनिर्मित संघटकों के प्रभावी उपचार के लिए लागत-प्रभावी और ऊर्जा दक्ष क्योरिंग कक्षों के विकास के लिए एक परियोजना आरम्भ की जाए। यह प्रौद्योगिकी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण के लिए उपयुक्त होगी।

ख. प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, निर्माण और प्रसार

1. केरल, हरियाणा, असम और झारखण्ड राज्यों में मास्टर मैसनों, कारपेंटरों, सुपरवाइजरों जैसे निर्माण कार्य दल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रत्येक राज्य में पांच)

आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ नई और अभिनव प्रौद्योगिकियां अपनाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करने हेतु इस बात की आवश्यकता है कि कम से कम ब्लॉक/ तालुका स्तर पर फैल्ड में इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु मास्टर मैसनों, कारपेंटरों, सुपरवाइजरों और स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षित किया जाए। इस क्षेत्र में राज मिस्ट्री संभवतः जानकारी के अभाव के कारण निर्माण में नई प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल न कर सकें, इसलिए यह प्रस्ताव दिया जाता है।

कि केरल, हरियाणा, असम और झारखण्ड राज्यों में लागत-प्रभावी और आपदा प्रतिरोधी निर्माण पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए। प्रत्येक राज्य में पांच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

2. संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/ प्रदर्शनियों के माध्यम से सूचना का प्रसार लागत-प्रभावी, पर्यावरण-अनुकूल निर्माण सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के बड़े पैमाने पर प्रसार हेतु यह प्रस्ताव दिया जाता है कि देश के विभिन्न भागों में संगोष्ठियां/ कार्यशालाएं/ प्रदर्शनियां आयोजित की जाएं और उनमें भाग लिया जाए।
3. ऊर्जा दक्ष निर्माण सामग्रियों, हरित प्रौद्योगिकियों और आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों के संवर्द्धन से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शृंखला आयोजित करना
यह प्रस्ताव दिया जाता है कि विकास प्राधिकरणों, आर्चीटेक्टों, इंजीनियरों, प्लानरों, डेवलपरों आदि के लिए इस वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों पर विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शृंखलाएं आयोजित की जाएं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विषयों का चयन इस प्रकार किया जाएगा कि उनमें पर्यावरण-अनुकूल, ऊर्जा दक्ष निर्माण सामग्रियों, हरित प्रौद्योगिकियों और आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों का एक बड़ा भाग कवर हो जाए।
4. मांग के आधार पर प्रौद्योगिकी प्रदर्शन व उत्पादन केन्द्र स्थापित करना
परिषद् अभिनव और लागत-प्रभावी निर्माण सामग्रियों तथा प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने हेतु मांग के आधार पर बड़े निर्माण संगठनों तक पहुंचने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र की निर्माण एजेंसियों के साथ लागत तथा लाभ शेयरिंग आधार पर प्रौद्योगिकी प्रदर्शन व उत्पादन केन्द्र स्थापित करेगी।
5. कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणीकरण योजना का कार्यान्वयन
बी.एम.टी.पी.सी. ऐसी नई, अभिनव निर्माण सामग्रियों और प्रणालियों, जिन पर भारतीय मानक उपलब्ध नहीं हैं, के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक निरन्तर कार्यकलाप के रूप में कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणीकरण योजना चला रही है। इस योजना के बारे में वृहत जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से यह भी प्रस्ताव दिया जाता है कि इस विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की जाए।
6. बंगलौर में उभरती हुई निर्माण प्रौद्योगिकियों पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन
यह प्रस्ताव दिया जाता है कि विभिन्न देशों में उभरती हुई नई प्रौद्योगिकियों की पहचान, चयन और सूचना प्राप्त करने के लिए बंगलौर में उभरती निर्माण प्रौद्योगिकियों पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाए।

7. छः स्थानों पर उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन

लागत-प्रभावी और अभिनव निर्माण सामग्रियों तथा निर्माण प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने के लिए चुने गए छः स्थानों पर उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लघु निर्माण सामग्री विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक बेरोजगार युवकों को सभी प्रकार की तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

8. तीन इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्थायी प्रदर्शन केन्द्रों की स्थापना

इंजीनियरिंग / आर्चीटेक्चर छात्रों के बीच अभिनव निर्माण सामग्री और निर्माण प्रौद्योगिकियों की जागरूकता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से परिषद् का प्रस्ताव है कि तीन इंजीनियरिंग कॉलेजों में तीन स्थायी प्रदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाएं ताकि इंजीनियरिंग कॉलेज / आर्चीटेक्चर कॉलेज के छात्र इन सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के बारे में केवल जानकारी ही प्राप्त न करें बल्कि फैल्ड परियोजनाओं में इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने में उनका विश्वास भी बढ़े।

9. परिषद् के प्रदर्शन पैनलों और प्रकाशनों को अद्यतन बनाना

अद्यतन लागत-प्रभावी निर्माण सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों पर जागरूकता बढ़ाने की दृष्टि से यह प्रस्ताव दिया जाता है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक रूप में विभिन्न सूचनाएं विकसित की जाएं।

10. बी.एम.टी.पी.सी. पर कॉर्पोरेट फिल्म तैयार करना

परिषद् के कार्यकलापों का प्रचार करने और जनता तक इसकी पहुंच में वृद्धि करने की दृष्टि से यह प्रस्ताव दिया जाता है कि बी.एम.टी.पी.सी. पर एक कॉर्पोरेट फिल्म तैयार की जाए।

11. अभिनव, हरित और आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके प्रदर्शन गृहों का निर्माण

यह प्रस्ताव दिया जाता है कि अभिनव, लागत-प्रभावी, हरित और आपदा प्रतिरोधी निर्माण प्रौद्योगिकियों के बड़े पैमाने पर प्रसार और जागरूकता उत्पन्न करने के दोहरे उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में चार स्थानों पर अभिनव, हरित और आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके कुछ प्रदर्शन गृहों का निर्माण किया जाए। भवनों के निर्माण के दौरान स्थानीय कारीगरों, इंजीनियरों आदि को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया जाएगा कि वे भूमि और अन्य अवसरंचना उपलब्ध कराएं।

12. परिषद् के निम्नलिखित प्रकाशन तैयार करना:

- दरों के विश्लेषण सहित लागत-प्रभावी निर्माण सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों पर मानक और विनिर्देशन।
- भारत में विनिर्मित निर्माण उपकरणों और मशीनरी की डायरेक्टरी।

- भारत और विदेशों में अभिनव निर्माण सामग्री के विनिर्माताओं का सार-संग्रह।
- भारतीय निर्माण सामग्रियों और उत्पादों की डायरेक्टरी।

ग. आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियां

1. तालुका स्तर तक राज्य/ संघ शासित क्षेत्र-वार वलरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया तैयार करना (17 राज्य/ संघ शासित क्षेत्र)

पिछली कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि वलरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया के संकलन के बाद राज्य/ संघ शासित क्षेत्र-वार वलरेबिलिटी एटलसें प्रकाशित की जाएं। वलरेबिलिटी एटलस पर बी.एम.टी.पी.सी. के प्रस्तुतीकरण के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी यह इच्छा व्यक्त की थी कि राज्य से संबंधित एटलसें तैयार की जाएं। राज्य-वार वलरेबिलिटी एटलसों में राज्य-विशिष्ट संस्तुत कार्य-योजनाएं शामिल होंगी और इस पर विचार करते हुए आपदा प्रबंधन योजनाएं जिला स्तर पर तैयार की जा रही हैं। इनमें तालुका स्तर तक सूचना प्रदान की जाएंगी।

2. आपदा प्रतिरोधी इमारतों के लिए भूगर्भीय-तकनीकी दिशानिर्देश तैयार करना

किसी इमारत के लिए विशेष रूप से आपदा संभावित क्षेत्रों में स्थित इमारतों के लिए नींव के उचित चयन हेतु भूगर्भीय-तकनीकी बोरे महत्वपूर्ण होते हैं। भूगर्भीय-तकनीकी संबंधी व्यापक दिशानिर्देश मौजूदा बिल्डिंग की रेट्रोफिटिंग और नए निर्माण, दोनों के लिए उपयोगी होंगे। इसलिए, यह प्रस्ताव दिया जाता है कि आपदा प्रतिरोधी इमारतों के लिए भूगर्भीय-तकनीकी दिशानिर्देश तैयार किए जाएं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यकलाप

1. असम और अरुणाचल प्रदेश में बांस आधारित मिश्रित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके प्रदर्शन गृहों का निर्माण (प्रत्येक स्थान पर पांच इमारतें)

बांस की अधिक पैदावार वाले राज्यों में बांस आधारित प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल को प्रदर्शित करने की दृष्टि से यह प्रस्ताव दिया जाता है कि असम और अरुणाचल प्रदेश में घर, पिकनिक हट, ओ.पी.डी. बिल्डिंग और स्कूल की बिल्डिंग जैसी प्रदर्शन इमारतों का निर्माण आरम्भ किया जाए। प्रत्येक राज्य में पांच प्रदर्शन इमारतों का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा। परियोजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और व्यावसायिक स्वीकार्यता सृजित करना और उसमें वृद्धि करना और बांस तथा बांस

आधारित उत्पादों का इस्तेमाल करके उन्नत गृह निर्माण में स्थानीय कारीगरों की दक्षता को उन्नत करना है।

2. अरुणाचल प्रदेश में बांस चटाई उत्पादन केन्द्र की स्थापना करना

अरुणाचल प्रदेश में बांस चटाई उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। बांस चटाई उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर दिए जाने से गृह निर्माण में बांस चटाई बोर्ड, बांस चटाई नालीदार रुफ शीटों के उत्पादन के लिए बांस की चटाईयों की उपलब्धता में सुविधा प्राप्त होगी और यहां बांस चटाई बुनने के प्रचालनों में स्थानीय पुरुषों और महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

अन्य स्रोतों से परियोजनाएं

1. आपदा प्रतिरोधी भवनों के लिए दिशानिर्देश बनाने सहित जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत 63 चुनिन्दा शहरों / शहरी बस्तियों के लिए वलरेबिलिटी एटलसें तैयार करना (जे.एन.एन.यू.आर.एम. से वित्तपोषण की संभावना है)

जैसाकि कार्यकारिणी समिति की पिछली बैठक में निर्णय लिया गया था, जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत चुने गए 63 शहरों के लिए बी.एम.टी.पी.सी. द्वारा आपदा वाले भवनों के लिए वलरेबिलिटी एटलस और दिशानिर्देश इस वर्ष के दौरान तैयार किए जाएंगे।

2. भूटान में लागत-प्रभावी और अभिनव निर्माण सामग्रियों को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन व उत्पादन केन्द्र स्थापित करना (भूटान सरकार से वित्तपोषण)

भूटान सरकार और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद, परिषद् भूटान में लागत-प्रभावी और अभिनव निर्माण सामग्रियों को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन व उत्पादन केन्द्र स्थापित करने हेतु तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रही है।

3. भूकम्पीय सुदृढीकरण के लिए दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की सात बिल्डिंगों की रेट्रोफिटिंग (दिल्ली नगर निगम से वित्तपोषण की संभावना है)

स्कूल के भवनों के महत्व पर विचार करते हुए यह आवश्यक है कि दिल्ली में ऐसी बिल्डिंगों की रेट्रोफिटिंग की जाए, जो जोन-IV (भूकम्पकीय रूप से अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र) में पड़ते हैं ताकि भविष्य में भूकम्प के आने की स्थिति में इमारतों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह प्रस्ताव दिया जाता है कि दिल्ली नगर निगम के सात स्कूलों में रेट्रोफिटिंग का प्रदर्शन किया जाए।

4. जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत परियोजनाओं का मूल्यांकन और मॉनीटरन
(राजस्व सृजन का कार्यकलाप)

हाल ही में आरम्भ किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत चुनिंदा मिशन शहरों से बी.एस.यू.पी. और आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के मूल्यांकन के लिए परिषद् को एक मूल्यांकन एजेंसी के रूप में नामजद किया गया है। बी.एम.टी.पी.सी. विभिन्न कार्यशालाओं, बैठकों आदि के माध्यम से डी.पी.आर. तैयार करने और उनमें संशोधन करने में म्युनिसिपल निकायों और राज्य नोडल एजेंसियों की सहायता भी कर रही है और बी.एम.टी.पी.सी. ने बी.एस.यू.पी. और आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं के लिए डी.पी.आर. तैयार करने में म्युनिसिपल प्राधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

परिषद्, उन राज्यों में परियोजनाओं की मॉनीटरिंग के लिए एक एक मॉनीटरिंग एजेंसी के रूप में भी नामजद की जा रही है, जहां परिषद् द्वारा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। इन परियोजनाओं की प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के परामर्श से एक विस्तृत मॉनीटरिंग प्रक्रिया तंत्र बनाया जा रहा है।